



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102024-257731
CG-DL-E-07102024-257731

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 288]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 4, 2024/आश्विन 12, 1946

No. 288]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 4, 2024/ASVINA 12, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

नई दिल्ली, 28 सितंबर, 2024

अंतिम निष्कर्ष

मामला स. एडी (एसएसआर)- 08/2023

विषय: चीन जन. गण., जापान, कोरिया जन. , वियतनाम और ताइवान से उत्पन्न या निर्यात किए गए "डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स" (डीओपीपी) के आयात से संबंधित पाटन रोधी जांच।

फ. संख्या 7/20/2023 -डीजीटीआर - समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 और समय-समय पर यथा संशोधित पाटित की गई वस्तुओं पर सीमा शुल्क (पहचान, मूल्यांकन और पाटनरोधी शुल्क का संग्रह और क्षति का निर्धारण) नियम, 1995 ("एडी नियम") को ध्यान में रखते हुए।

क. मामले की पृष्ठभूमि

- नामित प्राधिकारी (इसके बाद "प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित) को टेक्नोवा इमेजिंग सिस्टम्स (पी) लिमिटेड (इसके बाद "आवेदक" या "घरेलू उद्योग" के रूप में संदर्भित) से एक आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स (इसके बाद "डीओपीपी" या "विषय माल" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के आयात पर लगाए गए पाटन रोधी शुल्क की सूर्यास्त समीक्षा शुरू करने की मांग की गई या "विचाराधीन उत्पाद" या "पीयूसी"), चीन जन. गण.,

कोरिया गण. जन. , जापान, ताइवान और वियतनाम (इसके बाद "विषय देशों" के रूप में संदर्भित) से उत्पन्न या निर्यात किया जाता है।

2. संबंधित देशों से संबंधित वस्तुओं के आयात से संबंधित मूल जांच प्राधिकरण द्वारा दिनांक 16.05.2019 की अधिसूचना संख्या 6/7/2019-डीजीटीआर के माध्यम से शुरू की गई थी। प्राधिकरण ने दिनांक 3.10.2019 की अधिसूचना संख्या एफ संख्या 6/7/2019-डीजीटीआर के तहत प्रारंभिक निष्कर्ष जारी किए, जिसमें संबंधित देशों से पीयूसी के आयात पर छह महीने की अवधि के लिए अनंतिम पाटन रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई। वित्त मंत्रालय ने 30 जनवरी, 2020 की अधिसूचना संख्या, 02/2020 – सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से अनंतिम पाटन रोधी शुल्क लगाया।
3. इसके बाद, प्राधिकरण द्वारा अधिसूचना संख्या 6/7/2019-डीजीटीआर दिनांक 15.05.2020 के माध्यम से अंतिम निष्कर्ष जारी किए गए, जिसमें निश्चित पाटन रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई। उक्त सिफारिश के आधार पर, केंद्र सरकार द्वारा सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 21/2020-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 29.07.2020 के माध्यम से संबंधित वस्तुओं के आयात पर निश्चित पाटन रोधी शुल्क लगाया गया था, जो संबंधित देशों में उत्पन्न या वहां से निर्यात किया जाता है। वर्तमान पाटन रोधी शुल्क 29.01.2025 तक लागू हैं।
4. घरेलू उद्योग द्वारा विधिवत् प्रमाणित आवेदन के आधार पर, तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करते हुए, जो डंपिंग की संभावना और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति की पुष्टि करता है, और नियमों के नियम 23(1बी) के अनुसार, प्राधिकारी ने विषयगत देशों में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के संबंध में लागू शुल्कों को जारी रखने की आवश्यकता की समीक्षा करने और यह जांच करने के लिए कि क्या विद्यमान पाटन रोधी शुल्क की समाप्ति से डंपिंग जारी रहने या पुनरावृत्ति होने और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की संभावना है, 30.09.2023 को जांच शुरू की।

ख. प्रक्रिया

5. इस जांच के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया गया है:
 - क. प्राधिकरण ने प्राधिकृत व्यापारी नियमावली के नियम 5(5) के अनुसार जांच शुरू करने से पहले वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबंधित देशों के दूतावासों को अधिसूचित किया।
 - ख. प्राधिकरण ने 30 सितंबर, 2022 को भारत असाधारण राजपत्र में प्रकाशित एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया, जिसमें संबंधित देशों से संबंधित वस्तुओं के आयात से संबंधित पाटन रोधी जांच शुरू की गई।
 - ग. प्राधिकरण ने आवेदक द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, भारत में संबंधित देशों के दूतावासों, विषय देशों के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, विषय आयात के ज्ञात आयातकों/उपयोगकर्ताओं और अन्य इच्छुक पार्टियों को 20.10.2023 को दीक्षा अधिसूचना की एक प्रति भेजी। इच्छुक पार्टियों से अनुरोध किया गया था कि वे दीक्षा अधिसूचनाओं में निर्धारित प्रपत्र और तरीके से संगत सूचना प्रदान करें और दीक्षा अधिसूचना में निर्धारित समय-सीमा के भीतर लिखित रूप में अपनी प्रस्तुतियां दें।
 - घ. प्राधिकरण ने अपने ईमेल दिनांक 20.10.2023 के माध्यम से AD नियम, 1995 के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/उपयोगकर्ताओं और भारत में संबंधित देशों के दूतावासों को आवेदक द्वारा दायर आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण की एक प्रति भी प्रदान की।
 - ङ. भारत में विषय देशों के दूतावासों से भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें कि वे प्रश्नावली के प्रति अपने प्रत्युत्तर दीक्षा अधिसूचना द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रस्तुत करें। विषय देशों के दूतावासों को उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति के साथ-साथ संबंधित देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पते भी भेजे गए थे।
 - च. प्राधिकरण ने प्राधिकृत व्यापारी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार विषय देश में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावली भेजी:
 - I. कोडक (चीन) ग्राफिक कम्युनिकेशंस, चीन जन. गण.
 - II. शंघाई स्ट्रॉन्ग स्टेट्स प्रिंटिंग इक्विपमेंट कं, लिमिटेड, चीन जन. गण.
 - III. लकी हुआगुआंग ग्राफिक्स कंपनी, चीन

- IV. फुजीफिल्म प्रिंटिंग प्लेट (चीन) कं, लिमिटेड, चीन जन. गण.
 - V. माइलैन प्रिंटिंग मीडिया कॉर्पोरेशन
 - VI. टॉप हाई इमेज कॉर्पोरेट
 - VII. जेइल सी एंड पी कंपनी लिमिटेड, कोरिया गण. जन.
 - VIII. फुजीफिल्म कॉर्पोरेशन, जापान
- छ. उपर्युक्त अधिसूचना के प्रत्युत्तर में विषय देशों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली का प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया है
- I. लकी हुआगुआंग ग्राफिक्स कंपनी, चीन
 - II. कोडक (चीन) ग्राफिक कम्युनिकेशंस, चीन जन. गण.
 - III. अनहुइ स्ट्रांग स्टेट न्यू मटेरियल्स कं, लिमिटेड
 - IV. हुआंगशान जिनरुइताई टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड
 - V. झेजियांग जिनरुइताई न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड
 - VI. चोंगकिंग हुआफेंग डि जेट प्रिंटिंग मटेरियल कंपनी लिमिटेड
 - VII. फुजीफिल्म कॉर्पोरेशन
 - VIII. फुजीफिल्म प्रिंटिंग प्लेट (चीन) कं, लिमिटेड
 - IX. फुजीफिल्म ग्राफिक सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन
 - X. फुजीफिल्म (चीन) इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड
 - XI. ईस्टमैन कोडक कंपनी
 - XII. जेइल सी एंड पी कंपनी लिमिटेड
- ज. जिन देशों/निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है अथवा जांच में सहयोग नहीं किया है, उन्हें जांच में असहयोगी माना गया है।
- झ. प्राधिकरण ने भारत में संबंधित वस्तुओं के ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावली भी भेजी है जिसमें प्राधिकृत व्यापारी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मांगी गई है।
- ञ. निम्नलिखित आयातकों/उपयोगकर्ताओं ने आयातक/उपयोगकर्ता प्रश्नावली प्रतिक्रियाएं प्रस्तुत कीं:
- I. कपूर इमेजिंग प्राइवेट लिमिटेड
 - II. गणपति इंपीरियल इंडिया
 - III. फुजीफिल्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
 - IV. कोडक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (केआईपीएल)
 - V. एआरटी प्रिंटिंग हाउस प्रा.
 - VI. सीईआई प्रिंट पैक प्राइवेट लिमिटेड
 - VII. सीईआई प्रिंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
 - VIII. एक्सक्विजिट प्रिंट एंड पैक प्राइवेट लिमिटेड
 - IX. सरस्वती प्रिंट फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड
 - X. प्रिंटटच
 - XI. स्क्रीन प्वाइंट सिस्टम

- XII. ट्रायो प्लेट सिस्टम
- XIII. श्री प्रियन ग्राफिक्स
- XIV. वीपीआर डिजिटल कार्ड
- XV. ब्लू स्टार प्रिंटर
- XVI. सुदर्शन ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड
- XVII. प्रिंटलाइन सिस्टम - सी.टी.पी. व्यूरो
- XVIII. मां इमेजेस
- XIX. प्रिंटलाइन सिस्टम - द प्रिंट हाउस
- XX. स्कैन ग्राफिक सिस्टम
- XXI. भाग्यम बाइंडिंग वर्क्स
- XXII. कलर सोलूशंस
- XXIII. काल पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड
- XXIV. थॉमसन प्रेस
- XXV. निप्पॉन कलर

- ट. इसके अतिरिक्त, भारत के एक संघ नामत अखिल भारतीय मास्टर प्रिंटेर्स परिसंघ (एआईएफएमपी) ने जांच में भाग लिया।
- ठ. 1 दिसंबर, 2023 को, प्राधिकरण ने विषय जांच में उत्पाद नियंत्रण संख्या ("पीसीएन") के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति पर चर्चा की। प्राधिकरण ने इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर, 12 जनवरी, 2024 की अधिसूचना के माध्यम से विषय जांच में पीसीएन पद्धति को अंतिम रूप दिया। इसके बाद, इच्छुक पार्टियों को प्राधिकरण द्वारा प्रसारित प्रश्नावली का जवाब दाखिल करने के लिए 31 जनवरी, 2024 तक का समय प्रदान किया गया।
- ड. सिस्टम एंड डेटा मैनेजमेंट महानिदेशालय (डीजी सिस्टम्स) से अनुरोध किया गया था कि वे पिछली क्षति जांच अवधि और जांच की अवधि के लिए संबंधित वस्तुओं के आयात का लेनदेन-वार विवरण प्रदान करें। इसे प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किया गया था और वर्तमान जांच के उद्देश्य से विचार किया गया था।
- ढ. एडी नियम, 1995 के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकरण ने इच्छुक पार्टियों को 19 अगस्त, 2024 को आयोजित एक सार्वजनिक सुनवाई के माध्यम से विषय जांच के बारे में मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले इच्छुक पक्षों से मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों की लिखित प्रस्तुतियाँ दर्ज करने का अनुरोध किया गया था, इसके बाद प्रत्युत्तर प्रस्तुतियाँ, यदि कोई हों, दर्ज की गईं। इच्छुक पक्षों को उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रस्तुतियों के गैर-गोपनीय संस्करण को अन्य इच्छुक पार्टियों के साथ साझा करने का निर्देश दिया गया था।
- ण. पहली सार्वजनिक सुनवाई 19 अगस्त, 2024 को आयोजित की गई थी, जिसके बाद मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों का लिखित सबमिशन और प्रत्युत्तर दिया गया था। हालांकि, नए नामित प्राधिकारी की नियुक्ति के कारण, प्राधिकरण ने इच्छुक पार्टियों को मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया और 07-01-2011 को 2006 की सिविल अपील संख्या 949 में दिए गए 'ऑटोमोटिव टायर मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (एटीएमए) बनाम नामित प्राधिकरण' के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसरण में लिखित रूप में प्रस्तुतियाँ दीं। तदनुसार, प्राधिकरण ने 12 सितंबर, 2024 को एक और सार्वजनिक सुनवाई की। दूसरी मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले इच्छुक पक्षों से मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों की लिखित प्रस्तुतियाँ दर्ज करने का अनुरोध किया गया था, इसके बाद प्रत्युत्तर प्रस्तुतियाँ, यदि कोई हों, दर्ज की गईं। इच्छुक पक्षों को उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रस्तुतियों के गैर-गोपनीय संस्करण को अन्य इच्छुक पार्टियों के साथ साझा करने का निर्देश दिया गया था।

- त. प्राधिकरण ने विभिन्न इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए सबमिशन का गैर-गोपनीय संस्करण उपलब्ध कराया। डीजीटीआर की वेबसाइट पर सभी इच्छुक पक्षों की एक सूची अपलोड की गई थी, जिसमें उन सभी से अनुरोध किया गया था कि वे अपने सबमिशन के गैर-गोपनीय संस्करण को अन्य सभी इच्छुक पार्टियों को ईमेल करें।
- थ. गैर-हानिकारक मूल्य (इसके बाद 'एनआईपी' के रूप में संदर्भित) का निर्धारण भारत में संबंधित वस्तुओं के उत्पादन की लागत और उचित लाभ के आधार पर किया गया है, जो आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) और एडी नियम, 1995 के अनुलग्नक III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के आधार पर है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटन माजिन से कम पाटन रोधी शुल्क घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा।
- द. प्राधिकरण ने जांच के दौरान इच्छुक पार्टियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना की यथार्थता, जो इस अंतिम निष्कर्ष का आधार बनती है, को यथासंभव सीमा तक संतुष्ट किया और प्रासंगिक, व्यवहार्य तथा आवश्यक समझी जाने वाली सीमा तक घरेलू उद्योग तथा इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के दस्तावेजों का सत्यापन किया।
- ध. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की स्थल सत्यापन के साथ-साथ तालिका सत्यापन के दौरान आवश्यक समझी गई सीमा तक जांच और सत्यापन किया गया है और वर्तमान अंतिम निष्कर्षों के लिए उस पर भरोसा किया गया है।
- न. संबंधित देशों के सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना की जांच और सत्यापन भी आवश्यक समझी जाने वाली सीमा तक किया गया था और वर्तमान अंतिम निष्कर्षों के उद्देश्य से इस पर भरोसा किया गया है।
- प. वर्तमान जांच के उद्देश्य से जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 (12 महीने) है। क्षति परीक्षा की अवधि 1 अप्रैल 2019 - 31 मार्च 2020, 1 अप्रैल 2020 - 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 - 31 मार्च 2022 और पीओआई से है।
- फ. प्राधिकरण ने व्यापार नोटिस संख्या 10/2018 दिनांक 7 सितंबर 2018 के माध्यम से निर्धारित तरीके से आपसी आधार पर विभिन्न इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का गैर-गोपनीय संस्करण उपलब्ध कराया। गोपनीय आधार पर इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी / प्रस्तुतियों की जांच ऐसे गोपनीयता दावों की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। इच्छुक पार्टियों द्वारा दायर गोपनीयता दावों की पर्याप्तता के संबंध में संतुष्ट होने पर, प्राधिकरण ने ऐसी जानकारी/प्रस्तुतियों को गोपनीय माना है। गोपनीयता दावों को स्वीकार न करने के मामले में, इच्छुक पार्टियों को उसी का गैर-गोपनीय संस्करण प्रस्तुत करने और इसे अन्य इच्छुक पार्टियों को परिचालित करने का निर्देश दिया गया था।
- ब. जहां कहीं भी किसी इच्छुक पक्ष ने वर्तमान जांच के दौरान आवश्यक जानकारी प्रदान करने से इनकार कर दिया है या अन्यथा प्रदान नहीं किया है, या जांच में काफी बाधा डाली है, प्राधिकरण ने ऐसे पक्षों को गैर-सहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर वर्तमान अंतिम निष्कर्ष दर्ज किए हैं।
- भ. प्राधिकरण ने इस स्तर पर सभी इच्छुक पक्षों द्वारा उठाए गए सभी तर्कों और प्रदान की गई जानकारी पर विचार किया है, जिस हद तक साक्ष्य के साथ समर्थित हैं और वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक माने जाते हैं।
- म. जांच के आवश्यक तथ्यों वाला एक प्रकटीकरण बयान जो अंतिम निष्कर्षों का आधार बना है, इच्छुक पार्टियों को 20 सितंबर, 2024 को जारी किया गया था और इच्छुक पार्टियों को उसी पर टिप्पणी करने के लिए 25 सितंबर, 2024 तक का समय दिया गया था। इच्छुक पक्षों से प्राप्त प्रकटीकरण विवरण की टिप्पणियों पर इस अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना में प्रासंगिक और गैर-दोहराव वाली सीमा तक विचार किया गया है।
- य. इस अंतिम निष्कर्ष में '***' गोपनीय आधार पर एक इच्छुक पार्टी द्वारा प्रस्तुत जानकारी का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए एडी नियम, 1995 के नियम 7 के तहत प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाता है।
- कक. विषय जांच के लिए प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई पीओआई के लिए विनिमय दर 1 यूएस \$ 81.06 रुपये है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और वस्तु

ग.1 अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए प्रस्तुतियाँ

6. अन्य इच्छुक पार्टियों ने विचाराधीन उत्पाद के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

- क. मूल पाटन रोधी जांच में पीयूसी का विवरण और सनसेट रिव्यू के लिए आवेदन स्पष्ट रूप से बताते हैं कि पॉलिएस्टर प्लेटों को पीयूसी के दायरे में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि, जैसा कि घरेलू उद्योग के उत्पाद कैटलॉग से देखा जा सकता है, यह पॉलिएस्टर-आधारित डिजिटल प्रिंटिंग प्लेटों की बड़ी किस्मों का निर्माण करता है।
- ख. वर्तमान जांच एक सूर्यास्त समीक्षा है, और विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही है जो मूल जांच में प्राधिकरण द्वारा परिभाषित किया गया है।
- ग. विचाराधीन उत्पाद में तीन प्रकार होते हैं: (i) थर्मल प्लेटें; (ii) बैंगनी प्लेट; और (iii) सीटीसीपी/यूवी सीटीपी प्लेटें। प्राधिकरण ने लागत और मूल्य में अंतर के आधार पर इन तीन प्रकारों को विभिन्न पीसीएन (उत्पाद नियंत्रण संख्या) के रूप में वर्गीकृत किया है।
- घ. मूल जांच में, इच्छुक पार्टियों ने तर्क दिया कि घरेलू उद्योग कुछ उत्पाद प्रकारों का उत्पादन नहीं करता है: (i) डबल लेयर सीटीसीपी प्लेटें; (ii) नकारात्मक कार्यशील यूवी सीटीपी प्लेट्स; (iii) वाणिज्यिक पैमाने पर प्रक्रियाहीन प्लेटों (अर्थात् बैंगनी और यूवी सीटीपी) के अन्य रूपांतर; (iv) वाणिज्यिक पैमाने पर रसायन रहित यूवी सीटीपी प्लेटें।
- ङ. प्राधिकरण ने पहले माना था कि यदि वाणिज्यिक मांग है, और क्या टेक्नोवा में इन उत्पाद प्रकारों का उत्पादन करने की क्षमता है। इन उत्पाद प्रकारों की मांग के बावजूद, टेक्नोवा ने इन उत्पादों की कोई बिक्री नहीं की है और उनका निर्माण करने में असमर्थ है। प्राधिकरण को इस बात की गंभीर रूप से जांच करनी चाहिए कि क्या इन उत्पादों का उत्पादन कभी घरेलू उद्योग द्वारा किया गया था।
- च. इसमें शामिल उत्पाद विषम हैं, विभिन्न उत्पादन लागत और प्रक्रियाओं के साथ। उत्पाद प्रकारों में व्यापक मूल्यांकन लागू करने के बजाय पीसीएन स्तर पर मूल्य क्षति का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
- छ. यह भी जांच की जानी चाहिए कि क्या टेक्नोवा के स्व-आयात में ये उत्पाद प्रकार शामिल हैं, जो इंगित करेगा कि टेक्नोवा उन उत्पादों का आयात कर रहा है जो इसका उत्पादन नहीं कर सकते हैं। घरेलू उद्योग को आयात किए जा रहे उत्पादों के प्रकार और उन्हें आयात करने के कारणों का खुलासा करना आवश्यक होना चाहिए, जिससे इच्छुक पार्टियों को प्रभावी टिप्पणियां करने की अनुमति मिल सके।
- ज. पीयूसी में विभिन्न उत्पाद शामिल हैं, और घरेलू उद्योग उत्पाद की पूरी श्रृंखला का उत्पादन नहीं करता है। इसके बजाय, यह उन उत्पादों के आयात पर निर्भर करता है जिनका वह निर्माण नहीं करता है।

ग. 2 घरेलू उद्योग की ओर से किए गए प्रस्तुतीकरण

7. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग की ओर से निम्नलिखित प्रस्तुतियां दी गई हैं:
 - क. डिजिटल प्लेट्स का उपयोग मुद्रण उद्योग में कागज पर या टिन शीट, पॉली फिल्म आदि जैसे गैर-शोषक सबस्ट्रेट पर एक छवि (डॉट पैटर्न या पाठ) के रूप में डेटा स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स का उपयोग करके मुद्रण प्रक्रिया में, डिजिटल वर्कफ़्लो एनालॉग वर्कफ़्लो के विपरीत लेजर का उपयोग करके 'कंप्यूटर से प्लेट में' (सीटीपी) से एक छवि के प्रत्यक्ष हस्तांतरण को सक्षम बनाता है जिसके लिए छवि को स्थानांतरित करने के लिए मध्यस्थ फिल्म की आवश्यकता होती है।
 - ख. पीयूसी भारत में मुक्त रूप से आयात योग्य है और किसी आयात प्रतिबंध के अधीन नहीं है।
 - ग. डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स एक रासायनिक कोटिंग के साथ लेपित उच्च शुद्धता लिथो-ग्रेड एल्यूमीनियम काँइल से बने होते हैं। डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स या तो सकारात्मक (गैर-उजागर क्षेत्र रूपों की छवि) या नकारात्मक (उजागर क्षेत्र रूपों की छवि) काम करने वाली प्लेटें हो सकती हैं।
 - घ. कोटिंग घटक, जिसे 'सेंसिटाइज़र' के रूप में भी जाना जाता है, विभिन्न प्रकार की प्लेटों के लिए भिन्न होते हैं। कोटिंग घटकों और लेजर प्रकार के प्लेट सेटर्स के आधार पर, डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स को मोटे तौर पर उनके आवेदन के आधार पर थर्मल, वायलेट और सीटीसीपी / यूवी सीटीपी (कंप्यूटर-टू-कन्वेंशनल प्लेट) नामक तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है।
 - ङ. सभी प्रकार की डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स, सभी आयामों में, विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल हैं, सिवाय पानी रहित सीटीपी प्लेटों के।

- च. मूल पाटनरोधी जांच के निष्कर्ष के बाद से संबंधित वस्तुओं के विवरण और उनके उपयोग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
- छ. प्राधिकरण ने घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पादों, उत्पाद के आयातों और घरेलू एवं आयातित उत्पादों के अन्त्य उपयोग और प्रतिस्थापन का मूल्यांकन करने के बाद उत्पाद क्षेत्र को अंतिम रूप दिया। चूंकि यह एक सनसेट समीक्षा है, विचाराधीन उत्पाद के दायरे को बनाए रखा जाना चाहिए, जैसा कि मूल पाटन रोधी जांच में पुष्टि की गई थी।
- ज. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स सभी मामलों में संबंधित देशों से आयातित डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेटों के समान हैं। आयातित वस्तुओं का अंतिम उपयोग, तकनीकी विशेषताएं और भौतिक विशेषताएं घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित पीयूसी के साथ तुलनीय हैं।
- झ. घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि उनकी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, आयातित विषय वस्तुओं और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है।
- ञ. इसलिए, भारत में आयात किए जा रहे उत्पाद सभी प्रकार से घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पादों के समान हैं।
- ट. घरेलू उद्योग का तर्क है कि उठाए गए मुद्दों को मूल जांच में पहले ही हल कर लिया गया है और सूर्यास्त समीक्षा के दौरान उन पर फिर से विचार नहीं किया जाना चाहिए। समीक्षा का दायरा तय किया गया है और इच्छुक पार्टियों से इनपुट के बाद 12 जनवरी, 2024 की अधिसूचना द्वारा अंतिम रूप दिया गया था। बहिष्करण के दावों का समर्थन करने के लिए कोई नया उत्पाद विनिर्देश या सबूत प्रदान नहीं किया गया है, इसलिए मूल दायरे पर भरोसा किया जाना चाहिए।
- ठ. घरेलू उद्योग डबल लेयर-थर्मल (एलीट) और वायलेट प्लेटों का निर्माण कर सकता है और इसमें डबल-लेयर यूवी सीटीसीपी प्लेटों का उत्पादन करने की क्षमता है, जैसा कि मूल जांच के दौरान पुष्टि की गई है।
- ड. घरेलू उद्योग नकारात्मक काम करने वाली यूवी सीटीसीपी प्लेटों का निर्माण करता है, जैसा कि पहले स्थापित किया गया था।
- ढ. घरेलू उद्योग स्पष्ट करता है कि यह वायलेट केम-मुक्त प्लेटों का उत्पादन करता है, लेकिन ध्यान दें कि बाजार में कोई भी खिलाड़ी, जिसमें स्वयं भी शामिल है, वायलेट प्रक्रिया-मुक्त प्लेटों या प्रक्रिया-मुक्त यूवी सीटीसीपी प्लेटों का निर्माण नहीं करता है। घरेलू उद्योग रसायन मुक्त यूवी सीटीसीपी प्लेटों का उत्पादन कर सकता है, हालांकि लागत काफी अधिक है, जिससे भारत में कम वाणिज्यिक मांग है।
- ण. इच्छुक पार्टी में से एक ने तर्क दिया कि घरेलू उद्योग ने उन उत्पादों का आयात किया है जो इसका उत्पादन नहीं कर सकते हैं, उन्हें अस्वीकार कर दिया गया है। टेक्नोवा ने इनमें से किसी भी उत्पाद का आयात नहीं किया है और टेक्नोवा द्वारा आयातित सभी उत्पाद भी कंपनी द्वारा उत्पादित किए जाते हैं, जिससे कपूर के दावे निराधार हैं।
- त. पीयूसी के दायरे में पॉलिएस्टर प्लेट नहीं होती हैं।

ग.3. प्राधिकरण द्वारा समीक्षा

8. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स है।
9. यह सूर्यास्त समीक्षा जांच होने के कारण पीयूसी का दायरा वही है जो मूल जांच में था। मूल जांच में पीयूसी को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

विचाराधीन उत्पाद "डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स" है। डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेटों का उपयोग मुद्रण उद्योग में कागज पर या गैर-शोषक सबस्ट्रेट जैसे टिन शीट, पॉली फिल्म आदि पर एक छवि के रूप में डेटा स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स का उपयोग करके मुद्रण प्रक्रिया में, डिजिटल वर्कफ़्लो लेजर का उपयोग करके 'कंप्यूटर से प्लेट' (सीटीपी) तक छवि के प्रत्यक्ष हस्तांतरण को सक्षम बनाता है, एनालाॅग वर्कफ़्लो के विपरीत जिसमें छवि को स्थानांतरित करने के लिए मध्यस्थ फिल्म की आवश्यकता होती है। डिजिटल प्लेट्स एक रासायनिक कोटिंग के साथ लेपित उच्च शुद्धता लिथो-ग्रेड एल्यूमीनियम कॉइल से बने होते हैं। डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स या तो सकारात्मक (गैर-

उजागर क्षेत्र रूपों की छवि) या नकारात्मक (उजागर क्षेत्र रूपों की छवि) काम करने वाली प्लेटें हो सकती हैं। रेंज में प्लेटें शामिल हैं जिन्हें प्लेटों को संसाधित करने के लिए रसायनों की आवश्यकता होती है; और पर्यावरण के अनुकूल जिन्हें प्रसंस्करण के लिए कोई रसायन या पानी की आवश्यकता नहीं होती है। कोटिंग फॉर्मूलेशन विभिन्न प्रकार की प्लेटों के लिए भिन्न होते हैं। डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट तीन प्रकार की होती हैं, अर्थात्,

- i. थर्मल प्लेट्स;
- ii. वायलेट प्लेट्स;
- iii. सीटीसीपी/यूवी सीटीपी प्लेट्स।

प्राधिकरण ने प्रकटीकरण पश्चात टिप्पणियों को नोट किया है और यह माना है कि सभी आयामों और मोटाई में सभी प्रकार की डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेटें विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल हैं। हालांकि, पानी रहित सीटीपी प्लेटों को ऊपर बताए गए कारणों से पीयूसी के दायरे से बाहर रखा गया है।

10. प्राधिकरण नोट करता है कि कुछ इच्छुक पार्टियों ने तर्क दिया है कि मूल जांच में, प्राधिकरण में डबल लेयर सीटीसीपी प्लेट्स, नेगेटिव वर्किंग यूवी सीटीपी प्लेट्स, प्रोसेस-लेस प्लेट्स के अन्य वेरिएंट (यानी, वायलेट और यूवी सीटीपी), और केम-फ्री यूवी सीटीपी प्लेट्स शामिल हैं पीयूसी के भीतर क्योंकि घरेलू उद्योग ने इन उत्पादों के लिए कोई व्यावसायिक मांग नहीं दिखाई। हालांकि, उन्हें अब पीयूसी के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए, क्योंकि घरेलू उद्योग इन उत्पादों का उत्पादन जारी नहीं रखता है।
11. प्राधिकरण द्वारा 1 दिसंबर, 2023 को पीयूसी/पीसीएन के दायरे पर एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें जांच के दायरे से उत्पादों को बाहर रखने के संबंध में इच्छुक पक्षों द्वारा कोई प्रस्तुतिकरण नहीं किया गया था। इच्छुक पक्षों से प्राप्त प्रस्तुतिकरणों के अनुसार प्राधिकरण ने 12 जनवरी, 2024 के अपने संचार के माध्यम से वर्तमान जांच के लिए अपनाई जाने वाली पीयूसी और पीसीएन पद्धति के दायरे को निम्नानुसार स्पष्ट किया है:

क्र.स.	पीसीएन पैरामीटर	कोड
1	कम्प्यूटर से परम्परागत प्लेट (सीटीसीपी) / यूवी कम्प्यूटर से प्लेट (यूवी सीटीपी)	C
2	थर्मल प्लेट्स	T
3	वायलेट प्लेट्स	V

12. प्राधिकरण यह भी नोट करता है कि इच्छुक पार्टियां यह प्रदर्शित करने के लिए कोई सबूत देने में विफल रही हैं कि ये उत्पाद घरेलू रूप से उत्पादित उत्पादों की तरह नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण ने मूल जांच में जांच के दायरे से विभिन्न प्रकार के उत्पादों को बाहर रखने के मुद्दों की जांच की है और इच्छुक पार्टियों ने यह स्थापित करने के लिए कोई नया साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है कि आवेदक ऐसे किसी उत्पाद का विनिर्माण नहीं करता है। इसे देखते हुए, प्राधिकरण इस समय इच्छुक पार्टियों द्वारा उत्पाद बहिष्करण के इन दावों की जांच करना उचित नहीं समझता है।
13. "समान वस्तु" की परिभाषा से संबंधित नियम 2 (डी) निर्दिष्ट करता है कि "जैसा लेख" का अर्थ है एक लेख जो जांच के तहत लेख के समान या सभी मामलों में समान है, या इस तरह के लेख की अनुपस्थिति में, एक अन्य लेख जिसमें जांच के तहत लेख के समान विशेषताएं हैं।

14. "जैसा वस्तु" शब्द की उपरोक्त परिभाषा से, यह स्पष्ट है कि समान वस्तु को जांच के तहत लेख के समान या सभी मामलों में समान होना चाहिए। वस्तु जैसे शब्द के दायरे में उन लेखों को भी शामिल किया जाएगा जिनकी विशेषताएं सभी मामलों में समान या समान लेखों की अनुपस्थिति में जांच के अधीन लोगों के समान हैं।
15. प्राधिकरण नोट करता है कि भारतीय घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित विषय वस्तुओं और संबंधित देशों से आयातित वस्तुओं में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों भौतिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया, कार्यों और उपयोग, उत्पाद विनिर्देशों, वितरण और विपणन, और माल के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। दोनों तकनीकी और व्यावसायिक रूप से प्रतिस्थापन योग्य हैं। उपभोक्ता भी दोनों का परस्पर उपयोग करते हैं। प्राधिकरण का मानना है कि आवेदक द्वारा विनिर्मात उत्पाद संबंधित देशों से भारत में आयात की जा रही वस्तुओं की वस्तु की तरह है।
16. जांच के दायरे में शामिल उत्पादों की विविधता के दावों के संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि उसने जांच के दायरे में शामिल विषय उत्पादों की उचित तुलना सुनिश्चित करने के लिए पीसीएन पद्धति का पालन करने का निर्णय लिया है।
17. पीयूसी सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की टैरिफ मद 844250 के अंतर्गत आता है। पीयूसी का आयात 37013000, 37040090, 37051000, 76061190, 76069190 और 76069290 सहित अन्य सीमा शुल्क टैरिफ मदों के अंतर्गत भी किया जा रहा है। क्षति के आकलन के उद्देश्य से सभी विभिन्न एचएस कोड के तहत किए गए पीयूसी के आयात को ध्यान में रखा गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी तरह से बाध्यकारी नहीं है।

घ. घरेलू उद्योग और स्थिति का दायरा

घ.1 अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए प्रस्तुतियाँ

18. अन्य इच्छुक पार्टियों ने घरेलू उद्योग और स्टैंडिंग के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:
 - क. आवेदक, टेक्रोवा इमेजिंग प्राइवेट लिमिटेड ने अपने आवेदन में स्वीकार किया कि उन्होंने पाटन रोधी संरक्षण होने के बावजूद पीओआई के दौरान विषय और गैर-विषय दोनों देशों से संबंधित वस्तुओं का आयात किया, लेकिन इस तरह के आयात के कारणों का खुलासा नहीं किया।
 - ख. आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुक्रमित आंकड़ों से पता चलता है कि घरेलू उद्योग द्वारा विषय देशों से ये आयात पीओआई के दौरान विषय देशों से विषय वस्तुओं के कुल आयातों का लगभग 3% से 4% के बीच होता है। यह लगभग 6,09,929 वर्गमीटर है, जो गैर-विषयक देशों (1,66,592 वर्गमीटर) से संबंधित वस्तुओं के कुल आयात से छह गुना अधिक है और जापान, दक्षिण कोरिया और वियतनाम से संयुक्त आयात से अधिक है।
 - ग. इच्छुक पक्षों का तर्क है कि टेक्रोवा को नियम 2(बी) के तहत "घरेलू उद्योग" माना जाना अयोग्य है क्योंकि यह जांच के तहत देशों से विषय वस्तुओं का एक महत्वपूर्ण और आदतन आयातक है। जांच की अवधि के दौरान इसमें काफी वृद्धि हुई, जिससे इसे घरेलू उद्योग के रूप में माना जाने से अयोग्य घोषित कर दिया गया। इस तर्क का समर्थन करने के लिए चीन जन. गण. (2017) से एल्युमिनियम फॉयल, चीन जन. गण. (2018) से फ्लैक्स यार्न और चीन पीआर (2017) से ग्लेज्ड/अनग्लेज्ड पॉर्सिलेन/विट्रिफाइड टाइल्स सहित कई पिछले मामलों का हवाला दिया गया है।
 - घ. टेक्रोवा के नियमित आयात इस दावे का खंडन करते हैं कि ऐसे आयात अस्थायी हैं, जैसा कि पिछली जांच में उल्लेख किया गया है जहां नामित प्राधिकरण ने मुख्य ग्राहकों को बनाए रखने के लिए अस्थायी आयात की अनुमति दी थी। हालांकि, वर्तमान आयात आंकड़ों से पता चलता है कि टेक्रोवा ने न केवल पीओआई और क्षति की अवधि के दौरान बल्कि पीओआई से पहले और बाद में भी लगातार विषय वस्तुओं का आयात किया है। यह पैटर्न नियम 2 (बी) के तहत घरेलू उद्योग की पात्रता को चुनौती देता है।
 - ड. पाटन रोधी नियमों के नियम 2 (बी) में कहा गया है कि संबंधित वस्तुओं के नियमित आयातकों को "घरेलू उद्योग" नहीं माना जा सकता है। उत्तरदाताओं का कहना है कि टेक्रोवा का आयात वित्त वर्ष

2019-20 में 100 इंडेक्स पॉइंट से बढ़कर पीओआई के दौरान 354 इंडेक्स पॉइंट हो गया, जिससे इसे नियम 2 (b) के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया।

- च. व्यापार उपचार जांच के लिए परिचालन प्रथाओं के मैनुअल (अनुच्छेद 4.9.20 (v)) में याचिकाकर्ताओं द्वारा आयात के मुद्दे पर महानिदेशक से एक विशिष्ट संदर्भ की आवश्यकता होती है। याचिकाकर्ता ने इन आयातों के लिए कोई असाधारण परिस्थितियां नहीं बताई हैं, और ऐसे आयात के कारणों को गोपनीय रखा गया है।
- छ. प्राधिकरण को नियम 2 (बी) के अनुपालन का मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि आवेदक द्वारा नियमित आयात, भले ही अस्थायी होने का दावा किया गया हो, घरेलू उद्योग के रूप में इसकी स्थिति के विपरीत है। आवेदक के पर्याप्त आयात, दोनों विषय और गैर-विषय देशों से, इसकी पात्रता के बारे में सवाल उठाते हैं, क्योंकि तुर्की और संयुक्त राज्य अमेरिका से सोडा ऐश जैसे पिछले मामलों में समान उत्पादकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
- ज. फेडरेशन ने बताया कि मेसर्स एचएल प्रिंटिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो चीनी कंपनियों से विषय वस्तुओं का एक प्रमुख आयातक है और टेक्रोवा के आवेदन का समर्थक है, ने इसके आयात या निर्यातकों/आयातकों के साथ इसके संबंधों का खुलासा नहीं किया है। यह टेक्रोवा के आवेदन के लिए उनके समर्थन की वैधता को कम करता है।
- झ. टेक्रोवा की सहयोगी कंपनी मेसर्स लास्ट्रा नीरज प्राइवेट लिमिटेड के अस्तित्व का टेक्रोवा द्वारा खुलासा नहीं किया गया, जिससे आवेदक की स्थिति प्रभावित हुई। प्राधिकरण को प्रौद्योगिकी के साथ लास्ट्रा नीरज के संभावित आयातों और परिचालन संबंधों की पूरी तरह से जांच करनी चाहिए।
- ञ. फेडरेशन का तर्क है कि टेक्रोवा और एचएल प्रिंटिक सॉल्यूशंस दोनों को उनकी आयात गतिविधियों के कारण नियम 2 (बी) के तहत वैध घरेलू उत्पादक नहीं माना जाना चाहिए, जो पर्याप्त और अभ्यस्त हैं। प्राधिकरण से इन आधारों पर जांच समाप्त करने का अनुरोध किया जाता है।
- ट. टेक्रोवा के लगातार आयात महत्वहीन नहीं हैं, जैसा कि दावा किया गया है, और सबूत बताते हैं कि ये आयात नियमित थे, क्षति की अवधि, पीओआई और पोस्ट-पीओआई के दौरान होते थे। आवेदक का आयात न तो अस्थायी था और न ही शुल्क मुक्त योजना के तहत किया गया था।
- ठ. मूल जांच के दौरान, घरेलू उद्योग का आयात कुल आयात का 7% था, लेकिन प्राधिकरण ने इन्हें अस्थायी माना। हालांकि, वर्तमान साक्ष्य बताते हैं कि घरेलू उद्योग आयात पर निर्भर है, खासकर चीन और जापान जैसे विषय देशों से।
- ड. टेक्रोवा ने पीओआई के दौरान नियमित रूप से विषय और गैर-विषय दोनों देशों से माल आयात किया है, यह दर्शाता है कि घरेलू उत्पादन और बिक्री में किसी भी गिरावट को केवल विषय वस्तुओं के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
- ढ. घरेलू उद्योग सभी ग्राहकों की सेवा करने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित नहीं है, पर्याप्त तकनीक का अभाव है, और मांग को पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर करता है, जो आत्मनिर्भर निर्माता होने के अपने दावों का खंडन करता है।
- ण. इच्छुक पार्टियों ने आरोप लगाया है कि याचिकाकर्ता ने 2020-21 और 2021-22 के आयात डेटा के संबंध में झूठे दावे किए हैं। नतीजतन, उन्होंने एक डेटासेट प्रस्तुत किया है जो इंगित करता है कि 2019-20 और 2020-22 के दौरान, घरेलू उद्योग ने कुल 115,873 वर्गमीटर का आयात किया।
- त. याचिकाकर्ता द्वारा आयातित मात्रा अनुसंधान एवं विकास उद्देश्यों के लिए आयात किए जाने के लिए बहुत अधिक है।

घ.2. घरेलू उद्योग की ओर से किए गए प्रस्तुतीकरण

19. घरेलू उद्योग के संबंध में घरेलू उद्योग की ओर से निम्नलिखित प्रस्तुतियां दी गई हैं

- क. कुल घरेलू उत्पादन में से, घरेलू उत्पादक के हिस्से का उत्पादन हिस्सा 96% है। इसे ध्यान में रखते हुए, घरेलू उत्पादक वर्तमान आवेदन के प्रयोजनों के लिए घरेलू उद्योग का गठन करने के लिए अपेक्षित सीमा को पूरा करता है।
- ख. घरेलू उत्पादक ने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया है कि वह सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, मूल्यांकन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियम, 1995 (एडी नियम) के नियम 2(ख) और नियम 5(3) के अर्थान्तर्गत "घरेलू उद्योग" के रूप में अर्हता प्राप्त करता है।
- ग. 'घरेलू उद्योग' के तौर पर अपनी योग्यता हासिल करने के लिए घरेलू उत्पादकों के उत्पादन के लिए पात्र घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा होना चाहिए। घरेलू उत्पादक का उत्पादन न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करता है।
- घ. जबकि घरेलू उत्पादक को पीओआई के दौरान कुछ आयात करने के लिए बाध्य किया गया था, घरेलू उत्पादक के कुल उत्पादन, भारत में पीयूसी के कुल आयात और पीयूसी के अधीन आयात की तुलना में ये आयात नगण्य हैं।
- ङ. घरेलू उद्योग ने पीयूसी को विषय और गैर-विषयक दोनों देशों से आयात किया है क्योंकि उनके दो संयंत्रों में से प्रत्येक को अलग-अलग नियमित रखरखाव बंद करना पड़ा है।
- च. यह ध्यान दिया जा सकता है कि दोनों संयंत्रों में से कोई भी एक ही समय में बंद नहीं हुआ था। नतीजतन, मौजूदा ग्राहकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए, घरेलू उद्योग ने एक अस्थायी समाधान के रूप में पीयूसी का आयात किया।
- छ. इसके अलावा, कोविड-19 के बाद, पीयूसी में एक पेंट-अप मांग देखी गई जो उसी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री से स्पष्ट है। अपने मौजूदा ग्राहकों की मांग में अचानक वृद्धि को पूरा करने के लिए, घरेलू उद्योग ने पाटन रोधी शुल्क सहित लागू शुल्कों का भुगतान करते समय सीमित मात्रा में पीयूसी का आयात किया।
- ज. घरेलू उद्योग यह प्रस्तुत करता है कि उपर्युक्त कारणों से अधीन देशों से आयात पीओआई अवधि में इसके उत्पादन का केवल 18% और संबद्ध वस्तुओं की समग्र मांग का 12% है।
- झ. घरेलू उद्योग ने संबंधित वस्तुओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा है और अपने मौजूदा ग्राहकों की सेवा के लिए एक अस्थायी उपाय के रूप में पीयूसी आयात करने के लिए विवश था। यह घरेलू उद्योग के व्यवसाय की मौलिक विशेषता यानी पीयूसी का निर्माण करना और अपने ग्राहकों को इसकी आपूर्ति करना नहीं बदलता है।
- ञ. गैर-विषयक देशों (अर्थात् यूरोपीय संघ) से आयातों के संबंध में, परीक्षण और बाजार रोपण के उद्देश्य से इसके पूर्ववर्ती प्रौद्योगिकी भागीदार से आयात किए गए हैं।
- ट. चूंकि घरेलू उत्पादक द्वारा संबंधित देशों से आयात पीयूसी के कुल उत्पादन का केवल 1.8%, कुल मांग का 1.2% और संबंधित देशों से आयात का 3.5% होता है, इसलिए ऐसे कम आयात आवेदक को कोई अनुचित लाभ नहीं दे सकते थे।
- ठ. भारतीय न्यायालयों ने माना है कि जहां उत्पादक का प्रमुख व्यवसाय आयात नहीं है, उसे घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए। एक उत्पादक जो अपने कुल उत्पादन का एक छोटा सा हिस्सा आयात करता है, और वह भी उत्पादन व्यवधानों के दौरान, पाटन रोधी नियमों के नियम 2 (बी) के तहत आयातक नहीं माना जाना चाहिए।
- ड. याचिकाकर्ता भारत में एक प्रमुख गतिविधि के रूप में विषय वस्तुओं का निर्माण करता है और एक निर्माता की सभी आवश्यक विशेषताओं के अधिकारी हैं। याचिकाकर्ता का घरेलू उत्पादन संबंधित वस्तुओं की मांग का लगभग 67% है।
- ढ. याचिकाकर्ता विषय वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक है जो कुल घरेलू उत्पादन का 96% हिस्सा है।

- ण. याचिकाकर्ता घरेलू उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखता है, भारत सरकार की "मेक इन इंडिया" की महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाता है और घरेलू ग्राहकों की सेवा के लिए अपनी क्षमताओं का विस्तार करना जारी रखता है।
- त. घरेलू उद्योग का तर्क है कि "अस्थायी" आयात को "गैर-आवर्ती" के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। कभी-कभी छोटे आयात यह इंगित नहीं करते हैं कि उद्योग एक अभ्यस्त आयातक है या व्यापारिक गतिविधियों की ओर बढ़ रहा है। ये आयात अल्पकालिक जरूरतों से प्रेरित होते हैं, और प्राथमिक ध्यान घरेलू उत्पादन रहता है।
- थ. प्राधिकरण ने पिछली पाटनरोधी जांचों में न्यूनतम आयात वाले घरेलू उत्पादकों को घरेलू उद्योग का दर्जा प्राप्त करने के लिए लगातार पात्र माना है। उदाहरणों में प्राकृतिक अभ्रक-आधारित पिगमेंट, सन यार्न और कैप्रोलैक्टम से जुड़े मामले शामिल हैं।
- द. घरेलू उद्योग इस बात की पुष्टि करता है कि एलएनपीएल कंपनी में टेकनोवा की हिस्सेदारी के आधार पर उसकी सहयोगी कंपनी है। एलएनपीएल एनपीयूसी का निर्माता है, और इसलिए, विषय समीक्षा के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक नहीं है।

घ.3 प्राधिकरण द्वारा समीक्षा

20. नियमों के नियम 2 (बी) में निम्नानुसार प्रावधान है:

"घरेलू उद्योग" का अर्थ है घरेलू उत्पादक एक पूरे के रूप में समान वस्तु के निर्माण में लगे हुए हैं और उनसे जुड़ी कोई गतिविधि या वे जिनके उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा है, सिवाय इसके कि जब ऐसे उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हों या स्वयं उसके आयातक हों, ऐसे मामले में 'घरेलू उद्योग' शब्द बाकी निर्माताओं का जिक्र करते हुए।"

21. प्राधिकरण नोट करता है कि आवेदन मैसर्स टेकनोवा इमेजिंग सिस्टम्स (पी) लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। टेकनोवा के अलावा, विषय वस्तुओं का केवल एक अन्य निर्माता एचएल प्रिंटेक प्राइवेट लिमिटेड है, जिसने उक्त जांच में एक समर्थन पत्र दायर किया है।
22. आवेदक ने प्रस्तुत किया कि यह संबंधित देशों से पीयूसी के किसी भी निर्यातक या संबंधित देशों से पीयूसी के आयातकों से संबंधित नहीं है। हालांकि, आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि उसने जांच की अवधि के दौरान संबंधित देशों में से एक से पीयूसी आयात किया है।
23. प्राधिकरण नोट करता है कि एडी नियमों के नियम 2 (बी) में प्रावधान है कि घरेलू उत्पादक जो निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हैं या जो स्वयं कथित रूप से डंप किए गए माल के आयातक हैं, उन्हें घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखा जा सकता है। नियम 2 (बी) के तहत "हो सकता है" शब्द का उपयोग इंगित करता है कि निर्यातकों या आयातकों के साथ-साथ आयात करने वाले उत्पादकों से संबंधित उत्पादकों को स्वचालित रूप से घरेलू उद्योग का हिस्सा होने से बाहर नहीं रखा गया है। प्राधिकरण के पास घरेलू उद्योग के दायरे में ऐसे उत्पादकों को शामिल करने अथवा बाहर रखने के संबंध में मामला-दर-मामला आधार पर इस संबंध में सभी सम्यक विचार करने के बाद निर्णय लेने का विवेकाधिकार है। विशेष रूप से, प्राधिकरण को यह जांचना आवश्यक है कि क्या आवेदक ने इतनी बड़ी मात्रा में और ऐसी शर्तों के तहत पीयूसी का आयात किया है जो आवेदक को एडी नियमों के नियम 2 (बी) के तहत घरेलू उद्योग के रूप में अयोग्य बना देगा।
24. प्राधिकरण ने इच्छुक पार्टियों द्वारा उठाए गए तर्कों पर भी ध्यान दिया है, जो दावा करते हैं कि आवेदक के विषय वस्तुओं के आयात को 'अस्थायी' के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है, यह देखते हुए कि आवेदक ने मूल जांच के पीओआई के दौरान भी विषय वस्तुओं का आयात किया था। घरेलू उद्योग (डीआई), जवाब में, तर्क देता है कि 'अस्थायी' शब्द को 'गैर-आवर्ती' के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। प्राधिकरण नोट करता है कि घरेलू उत्पादकों द्वारा किए गए सामयिक आयात, जो अप्रत्याशित मांग में वृद्धि या उत्पादन व्यवधानों जैसी विशिष्ट और अल्पकालिक आवश्यकताओं से प्रेरित होते हैं, का परिणाम यह निष्कर्ष नहीं होना चाहिए कि आयात 'अभ्यस्त' हैं।

या 'अस्थायी' नहीं हैं जब तक कि ऐसे आयात घरेलू निर्माता के रूप में इसकी प्राथमिक भूमिका के लिए प्रासंगिक हैं और व्यापार की ओर अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में बदलाव का संकेत नहीं देते हैं।

25. इस संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि आवेदक द्वारा किए गए आयात का विवरण इस प्रकार है:

विवरण	इकाई	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
आवेदक द्वारा विषय देशों से किए गए आयात	वर्गमीटर	***	***	***	***
उत्पादन की मात्रा	वर्गमीटर	***	***	***	***
कुल आयात	वर्गमीटर	1,45,05,334	73,67,190	86,88,785	1,43,03,156
कुल मांग	वर्गमीटर	***	***	***	***
आयात के संबंध में					
- आवेदक का उत्पादन	%	0-1%	शून्य	शून्य	1-2%
- विषय वस्तुओं की मांग	%	0-1%	शून्य	शून्य	1-2%
- विषय आयात	%	1-2%	शून्य	शून्य	3-4%

26. प्राधिकरण नोट करता है कि पीओआई के दौरान आवेदक द्वारा पीयूसी के आयात की मात्रा कुल आयात, कुल घरेलू उत्पादन या देश की कुल मांग की तुलना में नगण्य है। कुल मांग, इसकी घरेलू बिक्री और उत्पादन के संबंध में आवेदक द्वारा किए गए आयात की मात्रा 1-2% की सीमा में है। इसकी पुष्टि डीजी सिस्टम्स डाटा से की गई है।
27. यह ध्यान दिया जाता है कि आवेदक विषय वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो देश में कुल घरेलू उत्पादन का लगभग 96% है। इसलिए, आवेदक द्वारा किए गए आयात घरेलू उत्पादक के रूप में अपनी भूमिका के अनुरूप हैं और व्यापार या अभ्यस्त आयात की ओर बदलाव का संकेत नहीं देते हैं।
28. आवेदक की सहयोगी कंपनी, लस्ट्रा नीरज प्राइवेट लिमिटेड के पीयूसी के उत्पादन और आयात में शामिल होने के संबंध में इच्छुक पक्षों द्वारा किए गए दावों के संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि लस्ट्रा नीरज प्राइवेट लिमिटेड पीयूसी के आयात या बिक्री में शामिल नहीं है। इसका सत्यापन डीजी सिस्टम डाटा से किया गया है।
29. एचएल प्रिंटिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए कथित आयात के संबंध में, जो वर्तमान समीक्षा में एक समर्थक है, प्राधिकरण नोट करता है कि समर्थक ने इसकी शुरुआत के बाद वर्तमान समीक्षा में भाग नहीं लिया है। हालांकि, प्राधिकरण ने आयात आंकड़ों का विश्लेषण किया और पाया कि एचएल प्रिंटिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा क्षति की अवधि में किए गए पीयूसी का कोई आयात नहीं किया गया है। प्राधिकरण ने आगे नोट किया कि एचएल प्रिंटिक भारत में पीयूसी के घरेलू उत्पादन का केवल 4% है। तदनुसार, इसकी पात्रता के बावजूद, आवेदक कानून के तहत आवश्यक स्थायी आवश्यकताओं को पूरा करता है।
30. उपरोक्त के मद्देनजर, प्राधिकरण का मानना है कि आवेदक यानी टेक्नोवा इमेजिंग सिस्टम्स (पी) लिमिटेड नियमों के नियम 2 (बी) की आवश्यकता को पूरा करता है और घरेलू उद्योग की स्थिति निर्धारित करने के उद्देश्य से एक पात्र घरेलू उत्पादक माना जाता है।

31. रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर, प्राधिकरण नोट करता है कि पीओआई में आवेदक का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन का लगभग 96% है और यह एक बड़ा हिस्सा है। तदनुसार, आवेदक द्वारा दायर आवेदन विज्ञापन नियमों के नियम 5 (3) के संदर्भ में खड़े होने के मानदंडों को पूरा करता है।

ड. गोपनीयता

ड.1 अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए प्रस्तुतियाँ

32. अन्य इच्छुक पार्टियों ने गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

- क. आवेदक ने विभिन्न सूचनाओं पर अत्यधिक गोपनीयता का दावा करके ट्रेड नोटिस नंबर 10/2018 दिनांक 7.09.2018 के विशिष्ट प्रावधानों का उल्लंघन किया है।
- ख. आवेदक ने निम्नलिखित जानकारी को गोपनीय होने का दावा किया है, जिसमें शामिल हैं:
- उत्पादन की प्रक्रिया
 - प्रमुख कच्चे माल के नाम
 - घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयात (+/- 5% रेंज)
 - गैर-हानिकारक मूल्य गणना (+/- 10% सीमा)
- ग. भारतीय पाटन रोधी नियमों के नियम 7 में गोपनीय जानकारी प्रदान करने वाले पक्षों को गैर-गोपनीय सारांश प्रस्तुत करने या कारण प्रदान करने की आवश्यकता होती है कि संक्षेपण संभव क्यों नहीं है।
- घ. यदि नामित प्राधिकारी यह पाता है कि गोपनीयता का दावा वांछित नहीं है या पार्टी सामान्यीकृत रूप में जानकारी का खुलासा करने के लिए तैयार नहीं है, तो प्राधिकरण सूचना की अवहेलना कर सकता है।
- ङ. नियम 7 इस बात पर जोर देता है कि गोपनीय रूप से प्रस्तुत की गई सभी सूचनाओं को तब तक नहीं माना जाना चाहिए जब तक कि वैध कारणों से समर्थित न हो और प्राधिकरण द्वारा स्वीकार न किया गया हो।
- च. आवेदक गोपनीय जानकारी की उचित समझ की अनुमति देने के लिए विस्तृत सारांश प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है, जिससे अन्य इच्छुक पार्टियाँ प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें और सही निर्धारण करने में प्राधिकरण की सहायता कर सकें।
- छ. माननीय सीईएसटीएटी ने विट्रिफाइड टाइल्स मामले में यह निर्णय दिया कि गोपनीय रूप से प्रस्तुत की गई सूचना को स्वतः गोपनीय नहीं माना जाना चाहिए और पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया।
- ज. सीस्टेट के फैसले ने गोपनीयता के दावों की जांच के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए और कहा कि प्राधिकरण के लिए गोपनीय जानकारी की उचित समझ की अनुमति देने के लिए पार्टियों से विस्तृत गैर-गोपनीय सारांश की आवश्यकता है।
- झ. यदि गोपनीयता के अनुरोध की आवश्यकता नहीं है, और पार्टी सामान्यीकृत या सारांशित रूप में जानकारी का खुलासा करने से इनकार करती है, तो प्राधिकरण ऐसी जानकारी की अवहेलना कर सकता है।
- ञ. उत्तरदाताओं का अनुरोध है कि प्राधिकरण जांच को समाप्त कर दे, क्योंकि यह आवेदक के अत्यधिक और अनुचित गोपनीयता दावों के कारण अधिकार क्षेत्र के बिना है।

ड.2 घरेलू उद्योग की ओर से किए गए प्रस्तुतीकरण

33. घरेलू उद्योग ने गोपनीयता के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

- क. इच्छुक पार्टियों ने प्रश्नावली प्रतिक्रियाएं दायर की हैं जो घोर कमी, अत्यधिक गोपनीय हैं, और 7 सितंबर, 2018 को व्यापार सूचना 07/2018 के तहत आवश्यक मानकों को पूरा नहीं करती हैं।
- ख. घरेलू उद्योग बताता है कि कोडक चीन को 2019 में लकी हुआगुआंग द्वारा अधिग्रहित किया गया था, लेकिन कोडक चीन और इसकी मूल कंपनी, ईस्टमैन कोडक ने अपनी प्रतिक्रियाओं में इस जानकारी का खुलासा नहीं किया।

- ग. याचिकाकर्ता अनुरोध करता है कि प्राधिकरण कोडक चाइना और लकी इमेजिंग के वाणिज्यिक संबंधों, भारत में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के उत्पादन, बिक्री और विपणन पर प्रभाव की जांच करे और क्या संबंधित पक्षों ने इनपुट/कच्चा माल प्रदान किया है।
- घ. घरेलू उद्योग प्राधिकरण से इच्छुक पार्टियों से अपूर्ण प्रश्नावली प्रतिक्रियाओं को अस्वीकार करने के लिए कहता है।
- ङ. इच्छुक पार्टियों द्वारा दायर प्रतिक्रियाएं अत्यधिक गोपनीय हैं, जिनमें सार्थक गैर-गोपनीय सारांश का अभाव है, जिससे याचिकाकर्ता को प्रदान किए गए डेटा पर टिप्पणी करने की क्षमता में बाधा आती है।
- च. कई मामलों का हवाला देते हुए यह प्रदर्शित किया गया कि कैसे प्राधिकरण ने विदेशी उत्पादकों की प्रतिक्रियाओं को खारिज कर दिया है जब उन्हें कमी या अत्यधिक गोपनीय पाया गया था।

ड.3 प्राधिकरण द्वारा समीक्षा

34. सूचना की गोपनीयता पर, नियमों का नियम 7 इस प्रकार है:

"गोपनीय जानकारी: (1) नियम 6 के उप-नियम (2), (3) और (7), नियम 12 के उप-नियम (2), नियम 15 के उप-नियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में निहित किसी भी बात के बावजूद, नियम 5 के उप-नियम (1) के तहत प्राप्त आवेदनों की प्रतियां, या जांच के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा गोपनीय आधार पर नामित प्राधिकारी को प्रदान की गई कोई अन्य जानकारी, नामित प्राधिकारी द्वारा अपनी गोपनीयता के बारे में संतुष्ट होने पर, उसके द्वारा ऐसा माना जाएगा और ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्ष के विशिष्ट प्राधिकरण के बिना किसी अन्य पार्टी को ऐसी कोई जानकारी प्रकट नहीं की जाएगी।

(2) अभिहित प्राधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षों से अपेक्षा कर सकेगा कि वे उसका गैर-गोपनीय सारांश प्रस्तुत करें और यदि, ऐसी जानकारी प्रदान करने वाले पक्ष की राय में, ऐसी जानकारी सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है, तो ऐसा पक्षकार अभिहित प्राधिकारी को उन कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकेगा कि संक्षेपण क्यों संभव नहीं है।

(3) उपनियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, यदि अभिहित प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि गोपनीयता के लिए अनुरोध वांछित नहीं है या सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने या उसके प्रकटन को सामान्यीकृत या सारांश रूप में प्राधिकृत करने के लिए या तो अनिच्छुक है तो वह ऐसी जानकारी की अवहेलना कर सकेगा।

35. प्राधिकरण ने नियम 6(7) के अनुसार निरीक्षण के लिए विभिन्न इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय संस्करण वाली सार्वजनिक फाइल के माध्यम से सभी इच्छुक पक्षों को विभिन्न इच्छुक पक्षों द्वारा प्रदान की गई सूचना का अगोपनीय संस्करण उपलब्ध कराया है।
36. माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिलायंस इंडस्ट्रीज बनाम पदनामित प्राधिकारी के मामले में गोपनीयता के महत्व पर बल दिया था। उक्त निर्णय के अनुच्छेद 3 में यह पुष्टि की गई थी कि:

"3. ... नियम 7 के तहत गोपनीयता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे स्वचालित रूप से ग्रहण किया जाना चाहिए। बेशक, ऐसे मामलों में गोपनीयता की आवश्यकता होती है क्योंकि अन्यथा व्यापार प्रतियोगी गोपनीय जानकारी प्राप्त करेंगे जो वे अन्यथा प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन क्या आपूर्ति की गई जानकारी को गोपनीय रखने की आवश्यकता है, इस पर मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जाना चाहिए। यह नामित प्राधिकारी को तय करना है कि क्या किसी विशेष सामग्री को गोपनीय रखने की आवश्यकता है।

37. तदनुसार, प्राधिकरण ने एडी नियमों के नियम 7 के अनुसार ऐसे दावों की पर्याप्तता के लिए गोपनीय आधार पर घरेलू उद्योग और अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी की जांच की। संतुष्ट होने पर, प्राधिकरण ने गोपनीयता के दावों को स्वीकार कर लिया, जहां भी आवश्यक था और ऐसी जानकारी को गोपनीय माना गया

है। जहां कहीं संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षों को गोपनीय आधार पर दायर की गई सूचना का पर्याप्त गैर-गोपनीय विवरण उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था।

38. कच्चे माल के नाम, उत्पादन प्रक्रिया, घरेलू उद्योग द्वारा आयात के साथ-साथ एनआईपी रेंज पर गोपनीयता के दावों के संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि कच्चे माल का नाम, रेंज में आयात के साथ-साथ रेंज में क्षति मार्जिन का खुलासा घरेलू उद्योग द्वारा याचिका सहित अपनी प्रस्तुतियों में किया गया है। उत्पादन प्रक्रिया पर गोपनीयता के संबंध में, यह नोट किया जाता है कि ऐसी सूचना गोपनीय प्रकृति की होती है और ऐसी सूचना के प्रकटीकरण से घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

च. विविध

च.1 अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए प्रस्तुतियाँ

39. इच्छुक पार्टियों द्वारा निम्नलिखित विविध प्रस्तुतियाँ की गई हैं:

- क. टेक्रोवा इमेजिंग प्राइवेट लिमिटेड ने 2011 से लगातार विभिन्न देशों से डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स पर पाटन रोधी और काउंटरवेलिंग झूठी सहित व्यापार उपाय सुरक्षा की मांग की है और प्राप्त की है। शुल्क को बार-बार बढ़ाया गया है, हाल ही में चीन, जापान, कोरिया, ताइवान और वियतनाम के खिलाफ बढ़ाया गया है, सितंबर 2023 में चीन और ताइवान के खिलाफ काउंटरवेलिंग जांच शुरू की गई है। इन लंबे समय से चली आ रही सुरक्षा के बावजूद, टेक्रोवा डंप और सब्सिडी वाले आयात से क्षति का दावा करना जारी रखता है। फेडरेशन का तर्क है कि यह या तो घरेलू उद्योग के भीतर मनगढ़ंत क्षति के दावों या आंतरिक संरचनात्मक मुद्दों का संकेत दे सकता है जो व्यापार उपचार हल नहीं कर सकते हैं। वे जोर देकर कहते हैं कि मांग-आपूर्ति के अंतर को देखते हुए कई देशों के लिए लगातार भारत में माल पाटित करना आर्थिक रूप से अतार्किक है।
- ख. इच्छुक पार्टियाँ प्राधिकरण से कर्तव्यों के विस्तार की सिफारिश करने से पहले टेक्रोवा के निरंतर क्षति के दावों का गंभीर मूल्यांकन करने का आग्रह करती हैं। वे सुझाव देते हैं कि उपयोगकर्ता उद्योग को अतिरिक्त कर्तव्यों का बोझ नहीं उठाना चाहिए, खासकर अगर घरेलू उद्योग के भीतर अक्षमताएँ प्राथमिक कारण हैं। वे कर्तव्यों की तत्काल समाप्ति की सिफारिश करते हैं, यह कहते हुए कि कोई वास्तविक क्षति या इसकी पुनरावृत्ति की संभावना नहीं है।
- ग. इच्छुक पक्ष प्राधिकरण से आग्रह करते हैं कि शुल्कों के विस्तार की संस्तुति करने से पहले टेक्रोवा के निरंतर क्षति के दावों का गंभीरता से मूल्यांकन किया जाए। उनका सुझाव है कि उपयोगकर्ता उद्योग को अतिरिक्त शुल्कों का बोझ नहीं उठाना चाहिए, खासकर यदि घरेलू उद्योग के भीतर की अक्षमताएँ प्राथमिक कारण हैं। वे शुल्कों को तत्काल समाप्त करने की संस्तुति करते हैं, यह दावा करते हुए कि कोई वास्तविक क्षति नहीं है या इसके दोबारा होने की संभावना नहीं है।
- घ. इच्छुक पार्टियाँ प्रस्तुत करती हैं कि याचिकाकर्ता, टेक्रोवा, प्रतिस्पर्धा के खिलाफ ढाल के रूप में व्यापार उपचार का उपयोग करते हुए, जांच के लिए फाइल करने के लिए प्रतिकूल बाजार प्रवृत्तियों की अवधि चुनता है।
- ङ. इच्छुक पाटयाँ प्राधिकरण से पाटनरोधी और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच दोनों को समवर्ती रूप से पूरा करने का अनुरोध करती हैं। यह क्षति मार्जिन के व्यापक और एकीकृत मूल्यांकन की अनुमति देगा और लगातार और प्रभावी उपचार सुनिश्चित करेगा। पाटन रोधी और काउंटरवेलिंग दोनों जांचों को एक साथ संभालकर, प्राधिकरण खंडित और असंगत निष्कर्षों से बचते हुए, अनुचित व्यापार प्रथाओं के संचयी प्रभावों का एकीकृत विश्लेषण कर सकता है। यह दृष्टिकोण अलग-अलग जांच से उत्पन्न होने वाले दोहराव प्रयासों और संभावित विसंगतियों को रोककर दक्षता में भी वृद्धि करेगा।
- च. उत्पादक/निर्यातक प्रस्तुत करता है कि सूर्यास्त की समीक्षा केवल तभी शुरू की जा सकती है जब याचिकाकर्ता पाटन, सामग्री की क्षति और कारण के पर्याप्त सबूत प्रदान करता है। इस मामले में, याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान की गई जानकारी नियमों के नियम -5 (3) के तहत जांच को सही ठहराने के लिए अपर्याप्त है, जो मुख्य रूप से अनुमानों और मान्यताओं पर निर्भर है।
- छ. प्राधिकरण ने नियम 23 (आईबी) के तहत उचित रूप से जांच शुरू की है, जो पूरी तरह से मौजूदा पाटन रोधी कर्तव्यों के विस्तार से संबंधित है, जैसा कि दीक्षा अधिसूचना में दर्शाया गया है। आवेदक ने विशेष रूप

- से अपने आवेदन के पृष्ठ 56 पर वर्तमान कर्तव्यों के पांच साल के विस्तार का अनुरोध किया। चूंकि यह जांच नियम 23 (आईबी) के तहत शुरू की गई थी, इसलिए उत्तरदाता सम्मानपूर्वक प्राधिकरण से अनुरोध करते हैं कि वह अपने दायरे को मौजूदा कर्तव्यों के विस्तार तक सीमित करे, न कि उनके संशोधन तक, क्योंकि संशोधन केवल नियम 23 (1 ए) के तहत हो सकता है, जो यहां लागू नहीं है।
- ज. उत्पादक/निर्यातक प्रस्तुत करता है कि घरेलू उद्योग ने मौखिक सुनवाई के दौरान पर्याप्त प्रस्तुतियाँ करने से परहेज किया है, संभवतः क्योंकि वे मानते हैं कि तथ्य कर्तव्यों के विस्तार को सही नहीं ठहराते हैं। प्रत्युत्तर चरण तक पर्याप्त प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत करने में उनकी देरी ने इच्छुक पार्टियों को अपने दावों को ठीक से संबोधित करने से रोका।
- झ. इच्छुक पार्टियाँ इस बात पर जोर देती हैं कि सत्यापन मौजूदा जानकारी को क्रॉस-चेक करने के लिए है, न कि नए साक्ष्य पेश करने के लिए। वे प्राधिकरण से आग्रह करते हैं कि घरेलू उद्योग को भौतिक सत्यापन के दौरान नई जानकारी प्रस्तुत करने की अनुमति न दें, क्योंकि इससे उचित प्रक्रिया और निष्पक्षता कमजोर होगी।
- ञ. मूल जांच में, विभिन्न एचएस कोड (3701.3000, 3704.0090, 3705.1000, 7606.1190, 7606.9190, और 7606.9290) के तहत आयात को क्षति के आकलन के लिए माना जाता था, लेकिन वर्तमान जांच में, याचिकाकर्ता ने केवल टैरिफ आइटम 8442.50 पर ध्यान केंद्रित किया है, संभावित रूप से अन्य प्रासंगिक एचएस कोड को छोड़कर क्षति विश्लेषण को तिरछा कर दिया है। यह चयनात्मक दृष्टिकोण वास्तविक आयात मात्रा को विकृत कर सकता है और क्षति का गलत मूल्यांकन प्रदान कर सकता है, जिससे त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकल सकते हैं। प्राधिकरण से आग्रह है कि वह इस चयनात्मक रिपोर्ट की जांच करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्षति का आकलन संगत आयात आंकड़ों के पूर्ण दायरे को दर्शाता है।
- ट. याचिकाकर्ता का यह आरोप कि फुजीफिल्म समूह ने देरी से जवाब दाखिल किया, गलत है। प्राधिकरण ने योग्यता के आधार पर फुजीफिल्म समूह को विस्तार प्रदान किया और निर्धारित समय-सीमा के भीतर उत्तर दायर किया गया।
- ठ. यह दावा कि एफएफपीएस, चीन सहित चीनी निर्यातक व्यापार कदाचार में संलग्न हैं, निराधार है। एफएफपीएस नैतिक रूप से संचालित होता है और उच्च मानकों का पालन करता है। इसके अलावा, शून्य शुल्क लगाए जाने से ऐसे कदाचारों के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है। आवेदक ने इन आरोपों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है।
- ड. कोडक ने टेकनोवा से दस्तावेजी साक्ष्य का अनुरोध किया ताकि परिधि के बारे में दावों को प्रमाणित किया जा सके। चूंकि पाटनरोधी नियमावली के नियम 25 के अंतर्गत कोई छल जांच शुरू नहीं की गई है, इसलिए छल के आरोपों की वैधता नहीं है।
- ढ. मूल पाटन रोधी जांच में टेकनोवा ने क्षमता बढ़ाने के लिए 400 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता जताई थी। हालांकि, टेकनोवा की ओर से इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।
- ण. चोंगकिंग हुआफेंग डि जेट प्रिंटिंग मटेरियल कं. लिमिटेड और हुआंगशान जिनरुइताई टेक्नोलॉजी कं. लिमिटेड को व्यक्तिगत शुल्क दिया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने क्षति अवधि के दौरान उत्पादन शुरू किया था।
- त. आवेदक ने अपने आवेदन के पृष्ठ संख्या 56 पर प्राधिकरण से स्पष्ट रूप से अनुरोध किया है कि "मौजूदा पाटन रोधी शुल्क लगाने की अवधि को पांच साल की ओर अवधि के लिए बढ़ाया जाए"। तदनुसार, प्राधिकरण ने नियम 23(1ख) के संदर्भ में जांच शुरू की है जैसा कि आरंभिक अधिसूचना से स्पष्ट है, जो प्रारंभिक समीक्षा जांच के लिए है और केवल मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों के अधिरोपण की अवधि के विस्तार के लिए निर्धारित है न कि मौजूदा शुल्कों में संशोधन करने के लिए।
- थ. घरेलू उद्योग ने केवल शुल्क बढ़ाने का अनुरोध किया है और कोडक चाइना और लकी के लिए शुल्क की सामान्य दर निर्धारित करने का अनुरोध नहीं किया है। उपरोक्त के मद्देनजर, उन्होंने प्राधिकरण से संबंधित संस्थाओं के लिए शुल्कों की व्यक्तिगत दर को जारी रखने का अनुरोध किया जैसा कि मूल जांच में किया गया था।
- द. अनहुई स्ट्रॉन्ग स्टेट न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड जिसे पहले अनहुई स्ट्रॉन्ग स्टेट प्रिंटिंग मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, ने अपने प्रश्नावली के जवाब में संबंधित दस्तावेजों के साथ व्यवसाय के

नाम में बदलाव के बारे में बताया। नाम बदलने के लिए अनुरोध करते हुए मध्यावधि समीक्षा का आवेदन भी दायर किया गया था।

च.2. घरेलू उद्योग की ओर से किए गए प्रस्तुतीकरण

40. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध प्रस्तुतियों की गई हैं

- क. सुनवाई के बाद लिखित प्रस्तुतियाँ में नए तर्कों को उजागर करने के प्राधिकरण के निर्देश के बावजूद, अधिकांश इच्छुक पक्ष अनुपालन करने में विफल रहे। इसने घरेलू उद्योग को दो दिन की तंग समय सीमा के भीतर लंबी प्रस्तुतियों के माध्यम से झारना करने के लिए मजबूर किया, जिससे एक महत्वपूर्ण नुकसान हुआ। प्राधिकरण के निर्देश का पालन करने में विफलता ने पाटन रोधी जांच की दक्षता को बाधित किया, कार्यवाही की समय-संवेदनशील प्रकृति को कम कर दिया।
- ख. कोडक समूह ने तर्क दिया कि भौतिक क्षति के खतरे और संभावित परिदृश्यों की जांच के लिए पोस्ट-पीओआई डेटा पर विचार किया जाना चाहिए। हालांकि, घरेलू उद्योग ने इस बात पर प्रकाश डाला कि व्यापार उपचार जांच के लिए संचालन प्रथाओं के मैनुअल के अनुच्छेद 5.15 में कहा गया है कि पोस्ट-पीओआई डेटा का उल्लेख आरंभिक अधिसूचना में किया जाना चाहिए, जो इस मामले में नहीं किया गया था। इस प्रकार, पोस्ट-पीओआई डेटा पर अब विचार करना प्रक्रियात्मक रूप से अनुचित होगा।
- ग. इच्छुक पक्षों ने तर्क दिया कि घरेलू उद्योग ने जांच शुरू करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं दिए। घरेलू उद्योग ने जवाब दिया कि समीक्षा पाटन रोधी नियमों के अनुसार शुरू की गई थी, और याचिका में किसी भी कमी को प्राधिकारी द्वारा समीक्षा शुरू करने से पहले ठीक कर लिया गया था।
- घ. कुछ पक्षों ने दावा किया कि घरेलू उद्योग ने सुनवाई के दौरान कोई मौखिक प्रस्तुतियाँ नहीं दीं। घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया कि उसने साक्ष्य के लिए अपनी याचिका पर भरोसा करते हुए प्रस्तुतियाँ दीं। मौखिक प्रस्तुतियाँ करने के लिए कोई कानूनी दायित्व नहीं है, और लिखित प्रस्तुतियाँ और प्रत्युत्तर सभी पक्षों को पूरी तरह से अपना बचाव करने की अनुमति देते हैं।
- ङ. इन चुनौतियों के बावजूद, घरेलू उद्योग ने निवेश किया है और अपनी क्षमता का विस्तार करने की योजना बनाई है, जो पाटन रोधी कर्तव्यों के प्रवर्तन पर निर्भर है। निरंतर शुल्क संरक्षण के बिना, उद्योग को डंप किए गए आयात से नए सिरे से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, जिससे इसकी वृद्धि और स्थिरता को खतरा होगा।
- च. इच्छुक पार्टियों ने दावा किया कि घरेलू उद्योग ने आयात डेटा को विकृत करने के लिए टैरिफ आइटम 8442.50.20 पर चुनिंदा रूप से ध्यान केंद्रित किया। घरेलू उद्योग ने जवाब दिया कि प्राधिकरण आंकड़ों का सत्यापन कर सकता है और समीक्षा के लिए डीजी सिस्टम्स या डीजीसीआईएस डेटा पर भरोसा कर सकता है।

ग.3 प्राधिकरण द्वारा समीक्षा

41. प्राधिकरण नोट करता है कि कुछ इच्छुक पार्टियों ने तर्क दिया है कि वर्तमान सूर्यास्त समीक्षा गलत तरीके से शुरू की गई है क्योंकि घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका में एडी नियमों के नियम 5 (3) के तहत आवश्यक पर्याप्त सबूत नहीं हैं। प्राधिकरण नोट करता है कि पाटन, क्षति और पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना के प्रथम दृष्टया साक्ष्य से संतुष्ट होने के बाद जांच शुरू की गई थी। जांच के दौरान, प्राधिकरण ने इच्छुक पक्षों से सूचना और साक्ष्य एकत्र किए हैं जो वर्तमान समीक्षा में सिफारिश के लिए इसका आधार बनेंगे।
42. प्राधिकरण नोट करता है कि घरेलू उद्योग ने तर्क दिया है कि फुजीफिल्म की प्रतिक्रियाओं को खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे प्रश्नावली का जवाब दाखिल करने में देरी हुई। इस संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि उसके अनुरोध और वास्तविक कारणों के प्रदर्शन पर, प्राधिकरण ने फुजिलफिल्म समूह को आवश्यक प्रश्नावली का जवाब दाखिल करने के लिए समय सीमा में विस्तार दिया।
43. प्राधिकरण मूल जांच में पीयूसी के दायरे में शामिल कुछ एचएस टैरिफ मदों को शामिल न करने के संबंध में इच्छुक पार्टियों द्वारा उठाई गई चिंताओं को नोट करता है। इस संबंध में, प्राधिकरण ने भारत में संबंधित देशों से

किए गए संबंधित वस्तुओं के आयात की मात्रा निर्धारित करने के लिए डीजी सिस्टम्स से आयात आंकड़ों की जांच की है और उन पर भरोसा किया है। डीजी सिस्टम्स से आयात आंकड़ों की जांच उन सभी एचएस टैरिफ मदों के लिए की गई है जिन्हें मूल जांच में शामिल किया गया था और जिन्हें आवेदक द्वारा याचिका में सूचित किया गया है। आयात आंकड़ों को उत्पाद विवरण के साथ-साथ संगत एचएस टैरिफ मदों के आधार पर पीयूसी और गैर-पीयूसी में क्रमबद्ध किया गया है।

44. विभिन्न इच्छुक पक्षों द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में कि घरेलू उद्योग को सत्यापन के दौरान अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई थी, प्राधिकरण नोट करता है कि सत्यापन के दौरान सुधार किए गए या प्राधिकरण द्वारा मांगे गए डेटा में परिवर्तनों को छोड़कर सत्यापन के दौरान कोई अतिरिक्त जानकारी स्वीकार या प्रस्तुत नहीं की गई थी।
45. मौखिक सुनवाई के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा की गई सीमित प्रस्तुतियों पर विभिन्न इच्छुक पार्टियों के विवाद के संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि पाटन रोधी नियमों के नियम 6 में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के तहत अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया में सभी इच्छुक पार्टियों को दी गई सुनवाई का अधिकार शामिल है। जिस तरह से प्रत्येक पार्टी अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहती है, वह विवेक का विषय है। प्राधिकरण यह भी नोट करता है कि चूंकि मौखिक प्रस्तुतियों को केवल तभी रिकॉर्ड पर लिया जाता है जब इच्छुक पार्टियों द्वारा लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए कोई भी इच्छुक पक्ष किसी भी इच्छुक पक्ष द्वारा किए गए सीमित या वर्णनात्मक मौखिक प्रस्तुतियों से पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होता है। प्राधिकरण ने घरेलू उद्योग सहित सभी इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण पर लिखित रूप में विचार किया है।
46. शुल्क को जारी रखने या बढ़ाने के संबंध में विभिन्न इच्छुक पक्षों ने दलील दी है कि नियम 23 (1बी) केवल शुल्कों को जारी रखने की अनुमति देता है, शुल्कों में वृद्धि की नहीं। प्राधिकरण नोट करता है कि एडी नियमों के नियम 23 (1 बी) प्राधिकरण को केवल कर्तव्यों को जारी रखने के लिए सीमित नहीं करता है, बल्कि कर्तव्यों को बढ़ाने या बदलने की अनुमति देता है, अगर यह निष्कर्ष पर आता है कि पाटन और परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है। प्राधिकरण यह भी नोट करता है कि *बीएएसएफ दक्षिण पूर्व एशिया पं लिमिटेड* वी। *नामित प्राधिकारी*, माननीय सीईएसटीएटी ने पाया कि "सरकार के पास सीटीए की धारा 9 ए (5) के तहत सूर्यास्त समीक्षा के निष्कर्ष पर इसे जारी रखते हुए पाटन रोधी शुल्क को बदलने की शक्ति है। हालांकि, वर्तमान पाटन मार्जिन को निर्धारित करने और पाटन रोधी ज्यूटी को धारा 9 ए (1) के तहत ऐसी सीमा तक सीमित करने के लिए उक्त धारा 9 ए (5) के तहत कोई वारंट नहीं है।
47. विभिन्न इच्छुक पार्टियों ने कहा है कि प्राधिकरण को घरेलू उद्योग को हुई क्षति के दोहरेपन, व्यापक, समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण से बचने के लिए पाटनरोधी और समानांतर रूप से चल रही काउंटरवेलिंग ज्यूटी (सीवीडी) जांच दोनों की एक साथ जांच करनी चाहिए। इस संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि दोनों जांचों का उत्पाद दायरा समान है और दोनों जांचों में शामिल विषय देशों में ओवरलैप की डिग्री है। जबकि दोनों जांच अलग-अलग हैं और इसके गुणों के आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए, प्राधिकरण दोनों जांचों में अपनी सिफारिशें करते समय इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को उचित रूप से ध्यान में रखेगा। हालांकि, प्राधिकरण नोट करता है कि, उनके संबंधित नियमों द्वारा शासित अलग-अलग समय-सीमा के साथ स्वतंत्र जांच के रूप में, प्राधिकरण प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के अनुसार, अलग-अलग समय पर प्रत्येक जांच को समाप्त करने का पूरी तरह से हकदार है।
48. विभिन्न इच्छुक पक्षों के इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग द्वारा दायर याचिका में एडी नियमों के नियम 5 (3) के तहत पर्याप्त सबूत नहीं हैं, प्राधिकरण नोट करता है कि पाटन, क्षति और पाटन और क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना के *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य से संतुष्ट होने के बाद जांच शुरू की गई थी। जांच के दौरान, प्राधिकरण ने इच्छुक पक्षों से जानकारी और सबूत एकत्र किए हैं जो वर्तमान जांच में सिफारिश के लिए इसका आधार बनेंगे।

49. विभिन्न इच्छुक पार्टियों ने कहा है कि आवेदक ने 2011 से आयात से सुरक्षा का आनंद लिया है, इसके बावजूद कि वह क्षति से पीड़ित है। इसके अलावा, इच्छुक पार्टियों ने तर्क दिया है कि दावा की गई क्षति आंतरिक संरचनात्मक समस्याओं या मनगढ़ंत दावों के कारण हो सकती है। कानूनी मानक के लिए सुरक्षा की अवधि के बावजूद पाटन और क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना का आकलन करने की आवश्यकता होती है। प्राधिकरण ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति के अपने आकलन के लिए सत्यापित सूचना पर भरोसा किया है। प्राधिकरण आगे इस बात पर जोर देता है कि पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य केवल एक समान अवसर सृजित करना और घरेलू उद्योग पर अनुचित मूल्य वाले आयातों के हानिकारक प्रभावों को कम करना है। इन शुल्कों का उद्देश्य घरेलू उद्योग को अनुचित संरक्षण प्रदान करना या किसी अन्य उद्योग को नुकसान पहुंचाना नहीं है।
50. इच्छुक पार्टियों ने यह भी तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग कथित तौर पर जांच के लिए फाइल करने के लिए प्रतिकूल बाजार अवधि का चयन करता है, जो प्रतिस्पर्धा से खुद को बचाने के प्रयास का सुझाव देता है। इस संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि घरेलू उद्योग ने सूर्यास्त समीक्षा की शुरुआत के लिए याचिका दायर करने के संबंध में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अनुरूप वर्तमान सूर्यास्त समीक्षा की शुरुआत के लिए दायर किया है।
51. प्राधिकरण नोट करता है कि कोडक और फुजीफिल्म ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने चीनी निर्यातकों द्वारा शुल्कों की चोरी / उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि किसी भी छल को केवल एडी नियमों के नियम 25 के तहत शुरू की गई जांच के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिए। प्राधिकरण नोट करता है कि घरेलू उद्योग ने शुल्क के कथित परिवर्चना/अपवर्चन की जांच करने के लिए प्राधिकरण से अनुरोध नहीं किया है और इसके बजाय अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए उपयुक्त मंच से संपर्क किया है। प्राधिकरण ने अंतिम निष्कर्षों के संगत भाग में इन दावों की और विस्तार से जांच की है।
52. क्षमताओं के विस्तार के लिए निवेश पर विभिन्न इच्छुक पार्टियों की प्रस्तुतियों के संबंध में, घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि उसने संयंत्र खरीदा है, लेकिन कोविड के प्रभावों के कारण इसे स्थापित नहीं कर सका। प्राधिकरण नोट करता है कि घरेलू उद्योग ने क्षमता विस्तार के लिए मशीनरी खरीदी है जो वित्तीय विवरणों में उनकी पूंजी डब्ल्यूआईपी का हिस्सा है।
53. प्राधिकरण ने पाया कि अनहुई स्ट्रांग स्टेट न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड ने अपने व्यवसाय का नाम अनहुई स्ट्रांग स्टेट प्रिंटिंग मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड से बदलकर अनहुई स्ट्रांग स्टेट न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड करने के लिए मध्यावधि समीक्षा के लिए आवेदन किया था। यह निर्णय लिया गया कि उक्त मध्यावधि समीक्षा आवेदन को चल रही सूर्यास्त समीक्षा जांच में निपटाया जाना चाहिए। वर्तमान जांच में उक्त निर्यातक ने अपने व्यवसाय के नाम में परिवर्तन का उल्लेख करते हुए प्रासंगिक दस्तावेजों को संलग्न करते हुए प्रश्नावली का उत्तर दाखिल किया। प्राधिकरण ने अपने व्यवसाय के नाम में परिवर्तन के संबंध में रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजों की जांच करने के बाद, अनहुई स्ट्रांग स्टेट प्रिंटिंग मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड के स्थान पर नया नाम अनहुई स्ट्रांग स्टेट न्यू मैटेरियल्स कंपनी लिमिटेड के रूप में दर्ज किया।

छ. बाजार अर्थव्यवस्था उपचार (एमईटी), सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन का निर्धारण

छ.1 अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए प्रस्तुतियाँ

54. सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन माजन के संबंध में अन्य इच्छुक पार्टियों के विचार निम्नानुसार हैं
- क. उत्पादक/निर्यातक प्रस्तुत करता है कि विश्व व्यापार संगठन में चीन का परिग्रहण प्रोटोकॉल 11 दिसंबर 2016 को समाप्त हो गया था, और पाटन रोधी कार्यों में "सरोगेट देश" अभ्यास के उपयोग में उस तारीख से कानूनी आधार का अभाव है।
 - ख. निर्यातक अनुरोध करता है कि नामित प्राधिकरण इस मामले के लिए सामान्य मूल्य की गणना करने के लिए "सरोगेट देश" पद्धति का उपयोग न करें, भले ही चीन को बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जाता हो।
 - ग. चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 (ए) और 15 (बी) की व्याख्या, जैसा कि डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय के "फास्टनर मामले" में स्पष्ट किया गया है, अनुच्छेद 15 की समाप्ति के बाद चीन की बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति की स्वचालित प्राप्ति का समर्थन करता है।
 - घ. "पैक्टा सुंट सर्विडा" के अंतर्राष्ट्रीय कानून सिद्धांत के लिए हस्ताक्षरकर्ताओं को अपने संधि दायित्वों को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं से बचने के लिए घरेलू कानूनों को लागू नहीं करने का दायित्व भी शामिल है।
 - ङ. चीन ने विश्व व्यापार संगठन ढांचे के तहत अपने दायित्वों को पूरा किया है और उसे अपनी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति की मान्यता सहित संबंधित अधिकार दिए जाने चाहिए।
 - च. भारत, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य के रूप में, 11 दिसंबर 2016 के बाद चीन की बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति को मान्यता देने के लिए बाध्य है और चीन के खिलाफ पाटन रोधी जांच में "सरोगेट देश" दृष्टिकोण का उपयोग बंद करने के लिए अपने घरेलू नियमों में संशोधन करना चाहिए।
 - छ. चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल की धारा 15 में कहा गया है कि चीन के डब्ल्यूटीओ परिग्रहण से 15 साल बाद, पाटन रोधी जांच में चीन के साथ डब्ल्यूटीओ के किसी अन्य सदस्य की तरह व्यवहार किया जाना चाहिए।
 - ज. "सरोगेट देश" पद्धति 11 दिसंबर 2016 के बाद समाप्त हो गई, और चीन से आयात के लिए सामान्य मूल्य अब चीनी कीमतों और लागतों के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए।
 - झ. अमेरिका और यूरोपीय संघ ने पहले इस समझ का समर्थन किया था कि विश्व व्यापार संगठन में चीन के प्रवेश के 15 साल बाद "सरोगेट देश" दृष्टिकोण समाप्त हो जाएगा।
 - ञ. 11 दिसंबर 2016 के बाद, पाटन रोधी जांच में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए घरेलू कानून के तहत गैर-बाजार अर्थव्यवस्था (एनएमई) के रूप में चीन का वर्गीकरण अप्रासंगिक है।
 - ट. ईसी में डब्ल्यूटीओ अपीलीय निकाय – फास्टनरों ने पुष्टि की कि धारा 15 (ए) के प्रावधान चीन के परिग्रहण के 15 साल बाद समाप्त हो जाते हैं, यह स्थापित करते हुए कि डब्ल्यूटीओ के सदस्यों को चीनी कीमतों और लागतों का उपयोग करके चीनी आयात के लिए सामान्य मूल्य की गणना करनी चाहिए।
 - ठ. 11 दिसंबर 2016 के बाद "सरोगेट कंट्री" प्रथा को जारी रखना विश्व व्यापार संगठन के पाटन रोधी समझौते और भारत के डब्ल्यूटीओ दायित्वों के साथ असंगत होगा।
 - ड. यह भी ध्यान रखना प्रासंगिक है कि 26 अगस्त, 2021 को आग लगने से जेइल की अधिकांश उत्पादन सुविधाएं नष्ट हो गई थीं। आग लगने के बाद, जनवरी 2023 में उत्पादन फिर से शुरू होने के साथ, नई उत्पादन सुविधाएं स्थापित होने तक जेइल पीयूसी का उत्पादन करने में असमर्थ था। माननीय प्राधिकरण से अनुरोध है कि वे 2022 तक होने वाली लागत को पीयूसी की लागत में समायोजित करें, क्योंकि यह एक दुर्लभ घटना थी।

छ.2 घरेलू उद्योग की ओर से किए गए प्रस्तुतीकरण

55. विचाराधीन उत्पाद के संबंध में घरेलू उद्योग की ओर से निम्नलिखित प्रस्तुतियां दी गई हैं:
- क. एडी नियमों के अनुलग्नक I के अनुच्छेद 8 के उप- अनुच्छेद (2) में निर्धारित किया गया है कि किसी देश को पाटन रोधी जांच में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था ("एनएमई") माना जाएगा यदि देश को जांच अवधि

से पहले तीन (3) वर्षों में प्राधिकरण द्वारा एनएमई के रूप में माना गया है। यह नोट किया जाए कि जब तक जांच में सहयोग करने वाले उत्पादक/निर्यातक यह स्थापित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते कि यह बाजार अर्थव्यवस्था सिद्धांतों के तहत कार्य करता है, तब तक प्राधिकरण द्वारा देश को एनएमई के रूप में माना जाना चाहिए।

- ख. प्राधिकरण ने 30 मार्च, 2022 को अपनी अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना संख्या एफ संख्या 6/4/2021-डीजीटीआर में, कुछ रबर रसायनों के आयात से संबंधित पाटन रोधी जांच में जारी किया गया, जैसे चीन जन. गण., यूरोपीय संघ और रूस से उत्पन्न या निर्यात किए गए टीडीक्यू, चीन जन. गण. में उत्पन्न या निर्यात किए गए पीवीआई, और चीन जन. गण. और यूरोपीय संघ से उत्पन्न या निर्यात किए गए सीबीएस "और अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना संख्या एफ संख्या 6/3/2021-डीजीटीआर दिनांक 29 मार्च, 2022, चीन जन. गण. में उत्पन्न या निर्यात किए गए फ्लोरो बैकशीट के आयात से संबंधित पाटन रोधी जांच में जारी किया गया है, जिसमें चीन जन. गण. को एनएमई के रूप में माना गया है।
- ग. तदनुसार, इसने एडी नियमों के अनुबंध 1 के अनुच्छेद 7 और 8 के अनुसार चीन जन. गण. से उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य की गणना की है।
- घ. प्राधिकरण को चीन जन. गण. में प्रचालनरत उत्पादकों/निर्यातकों को एनएमई सिद्धांतों के अंतर्गत प्रचालन के रूप में मानना जारी रखना चाहिए जब तक कि संगत सूचना दाखिल करने वाले उक्त उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा अन्यथा स्थापित न किया गया हो।
- ङ. कुछ इच्छुक पार्टियों का दावा है कि चीन को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया जाना चाहिए क्योंकि इसका परिग्रहण प्रोटोकॉल 11 दिसंबर, 2016 को समाप्त हो गया था। हालांकि, घरेलू उद्योग का तर्क है कि प्रोटोकॉल की धारा 15 का हवाला देते हुए यह व्याख्या गलत है, जो तीन अलग-अलग समय-सीमाओं और शर्तों को रेखांकित करती है।
- च. चीन को केवल एक बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में माना जा सकता है यदि यह आयात करने वाले देश के राष्ट्रीय कानून के तहत ऐसा साबित करता है।
- छ. धारा 15(ए)(ii) गैट के अनुच्छेद VI के दूसरे विज्ञापन नोट के तहत मौजूदा प्रावधानों को दोहराती है, वैकल्पिक मूल्य तुलना विधियों की अनुमति देती है। पाटन रोधी समझौते का अनुच्छेद 2.7 इसका समर्थन करता है, जिसका अर्थ है कि 2016 के बाद चीन को बाजार अर्थव्यवस्था मानने के लिए भारत की कोई बाध्यता नहीं है।
- ज. प्राधिकरण ने पूर्व जांच में पुष्टि की है, जैसे कि "अनुपचारित फ्यूमड सिलिका" और "विनाइल टाइल्स" मामले, कि चीन एक एनएमई बना हुआ है जब तक कि अन्यथा साबित न हो। भारतीय कानून यह भी कहता है कि किसी देश को एनएमई के रूप में माना जाता रहेगा यदि पिछले तीन वर्षों के लिए इस तरह वर्गीकृत किया गया है, जब तक कि उत्पादक बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति का प्रमाण नहीं देते।
- झ. यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे प्रमुख न्यायालय व्यापार उपचारात्मक जांच में चीन को एनएमई के रूप में मानते हैं। यूरोपीय संघ और अमेरिका में अपनी एनएमई स्थिति पर डब्ल्यूटीओ पैनल के फैसलों के लिए चीन के अनुरोधों के परिणामस्वरूप चीन के लिए अनुकूल परिणाम नहीं हुए हैं।
- ञ. वर्तमान जांच में, किसी भी चीनी उत्पादक या निर्यातक ने बाजार अर्थव्यवस्था उपचार के लिए अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए, यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि पीयूसी के चीनी उत्पादक बाजार अर्थव्यवस्था सिद्धांतों के तहत काम करते हैं।
- ट. इन कारकों के आधार पर, घरेलू उद्योग प्राधिकरण से आग्रह करता है कि वे चीन के उत्पादकों/निर्यातकों को एनएमई सिद्धांतों के तहत प्रचालन के रूप में मानते रहें और संगत खर्चों और उचित लाभ के लिए समायोजित घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत के आधार पर निम्न सामान्य मूल्य पर भरोसा करें।
- ठ. जेड ने 2021 से जनवरी 2023 के बीच अपने संयंत्र के चालू न होने के कारण अपनी लागत में कुछ समायोजन का दावा किया है। इस संबंध में, घरेलू उद्योग प्राधिकरण से अनुरोध करता है कि वह पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार जेआईएल के पाटन माजन की गणना करे।

छ.3 प्राधिकरण द्वारा समीक्षा

चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

56. विश्व व्यापार संगठन में चीन के परिग्रहण प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार प्रावधान है: गैट 1994 का अनुच्छेद VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता 1994 ("पाटन रोधी एग्रीमेंट") के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन पर समझौता और एससीएम समझौता निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्य में चीनी मूल के आयात से जुड़ी कार्यवाही में लागू होगा:

(क) गैट 1994 के अनुच्छेद VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत मूल्य तुलनीयता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य जांचाधीन उद्योग के लिए या तो चीनी कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा अथवा ऐसी कार्यप्रणाली का उपयोग करेगा जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ कड़ी तुलना पर आधारित न हो

(i) यदि जांच के अधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के निर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रबल है, तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य तुलनीयता निर्धारित करने में जांच के तहत उद्योग के लिए चीनी कीमतों या लागतों का उपयोग करेगा;

(ii) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य ऐसी पद्धति का प्रयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू मूल्यों अथवा लागतों के साथ कड़ाई से तुलना पर आधारित न हो यदि जांचाधीन उत्पादक स्पष्ट रूप से यह नहीं दर्शा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में इस प्रकार के उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति विद्यमान है।

(ख) एससीएम समझौते के भाग II, III और V के तहत कार्यवाही में, अनुच्छेद 14 (ए), 14 (बी), 14 (सी) और 14 (डी) में वर्णित सब्सिडी को संबोधित करते समय, एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे; हालांकि, यदि उस आवेदन में विशेष कठिनाइयां हैं, तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य सब्सिडी लाभ की पहचान करने और मापने के लिए कार्यप्रणाली का उपयोग कर सकता है जो इस संभावना को ध्यान में रखता है कि चीन में प्रचलित नियम और शर्तें हमेशा उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य को चीन के बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के प्रयोग पर विचार करने से पहले ऐसे प्रचलित निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य पाटन रोधी प्रथाओं पर समिति को उप-अनुच्छेद (ए) के अनुसार उपयोग की जाने वाली पद्धतियों को अधिसूचित करेगा और सब्सिडी और काउंटरवेलिंग उपायों पर समिति को उप-अनुच्छेद (बी) के अनुसार उपयोग की जाने वाली पद्धतियों को अधिसूचित करेगा।

(घ) एक बार चीन ने डब्ल्यूटीओ के आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत यह स्थापित कर दिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, उप-अनुच्छेद (ए) के प्रावधानों को समाप्त कर दिया जाएगा, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में परिग्रहण की तारीख के अनुसार बाजार अर्थव्यवस्था मानदंड शामिल हों। किसी भी घटना में, उप-अनुच्छेद (ए) (ii) का प्रावधान परिग्रहण की तारीख के 15 साल बाद समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा, चीन को डब्ल्यूटीओ के आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसार, यह स्थापित करना चाहिए कि किसी विशेष उद्योग या क्षेत्र में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति प्रबल है, उप-अनुच्छेद (ए) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रावधान अब उस उद्योग या क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे।

57. यह ध्यान दिया जाता है कि जबकि अनुच्छेद 15 (ए) (ii) में निहित प्रावधान 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, विश्व व्यापार संगठन के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत प्रावधान , परिग्रहण प्रोटोकॉल के 15 (ए) (i) के तहत दायित्व के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें नियमों के अनुलग्नक I के अनुच्छेद 8 में निर्धारित मानदंड को बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति का दावा करने पर पूरक प्रश्नावली में प्रदान की जाने वाली जानकारी/डेटा के माध्यम से संतुष्ट किया जाना आवश्यक है।
58. चूंकि चीन जनसंपर्क के किसी भी निर्माता ने प्रश्नावली का उत्तर दायर नहीं किया है, इसलिए सामान्य मूल्य नियमों के अनुलग्नक I के अनुच्छेद 7 के अनुसार निर्धारित किया गया है जो निम्नानुसार है:

"7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर किया जाएगा, या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों में कीमत, या जहां यह संभव नहीं है, किसी अन्य उचित आधार पर, जिसमें वास्तव में भुगतान की गई कीमत या भारत में देय उत्पाद के लिए शामिल है, विधिवत समायोजित, यदि आवश्यक हो, तो उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए। संबंधित देश के विकास के स्तर और प्रश्रुत उत्पाद को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी द्वारा उचित तरीके से एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी भी विश्वसनीय जानकारी का उचित ध्यान रखा जाएगा। हिसाब भी समय सीमा के भीतर लिया जाएगा; जहां उपयुक्त हो, जांच की, यदि कोई अन्य बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश के संबंध में इसी तरह के मामले में की गई है। जांच के पक्षकारों को बिना किसी अनुचित देरी के बाजार अर्थव्यवस्था तीसरे देश के उपरोक्त चयन के बारे में सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियों की पेशकश करने के लिए उचित अवधि दी जाएगी।

8. (1) शब्द "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था देश" का अर्थ है कोई भी देश जिसे प्राधिकरण नामित करता है जो लागत या मूल्य निर्धारण संरचनाओं के बाजार सिद्धांतों पर काम नहीं कर रहा है, ताकि ऐसे देश में माल की बिक्री उपअनुच्छेद (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार माल के उचित मूल्य को प्रतिबिंबित न करे।

(2) यह पूर्वधारणा होगी कि कोई भी देश, जिसे जांच से पहले तीन वर्ष की अवधि के दौरान नामनिर्दिष्ट प्राधिकरण या सक्षम डब्ल्यूटीओ सदस्य देश के प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित किया गया है या माना गया है, एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। बशर्ते, कि गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश या ऐसे देश की संबंधित फर्में नामित प्राधिकरण को जानकारी और साक्ष्य प्रदान करके ऐसी अनुमान का खंडन कर सकती हैं जो यह स्थापित करता है कि ऐसा देश उप- अनुच्छेद (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश नहीं है।

(3) अभिहित प्राधिकरण प्रत्येक दशा में निम्नलिखित मानदण्डों पर विचार करेगा कि क्या: (क) ऐसे देश में संबंधित फर्मों के मूल्यों, लागतों और आदानों के बारे में, जिनके अंतर्गत कच्चा माल, प्रौद्योगिकी और श्रम की लागत, उत्पादन, विक्रय और निविष्टियां हैं, आपूर्ति और मांग को प्रतिबिम्बित करने वाले बाजार संकेतों के प्रत्युत्तर में और इस संबंध में महत्वपूर्ण राज्य हस्तक्षेप के बिना किए जाते हैं, और क्या प्रमुख इनपुट की लागत बाजार मूल्यों को काफी हद तक दर्शाती है; (ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति पूर्व गैर-बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से किए गए महत्वपूर्ण विकृतियों के अधीन है, विशेष रूप से परिसंपत्तियों के मूल्यहास, अन्य बड़े खाते डालने, वस्तु विनिमय व्यापार और ऋणों के मुआवजे के भुगतान के संबंध में; (c) ऐसी फर्में दिवालियापन और संपत्ति कानूनों के अधीन हैं जो फर्मों के संचालन के लिए कानूनी निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं, और (d) विनिमय दर रूपांतरण बाजार दर पर किए जाते हैं।

वशर्ते, हालांकि, जहां इस अनुच्छेदग्राफ में निर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य द्वारा यह दिखाया गया है कि पाटन रोधी जांच के अधीन ऐसी एक या एक से अधिक फर्मों के लिए बाजार की स्थिति प्रबल होती है, नामित प्राधिकरण अनुच्छेदग्राफ 7 और इस अनुच्छेदग्राफ में निर्धारित सिद्धांतों के बजाय अनुच्छेदग्राफ 1 से 6 में निर्धारित सिद्धांतों को लागू कर सकता है।

(4) उप अनुच्छेद (2) में किसी बात के होते हुए भी, अभिहित प्राधिकरण ऐसे देश को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मान सकेगा, जिसके अंतर्गत सुसंगत मानदंडों के नवीनतम विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर, जिसके अंतर्गत उप अनुच्छेद (3) में विनिर्दिष्ट मानदंड भी हैं, किसी सार्वजनिक दस्तावेज में ऐसे मूल्यांकन के प्रकाशन द्वारा, प्रतिपाटन अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना या अवधारित किया गया है, एक देश द्वारा जो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है

59. अनुच्छेद 7 में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए पदानुक्रम निर्धारित किया गया है और यह प्रावधान किया गया है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत या निर्मित मूल्य के आधार पर किया जाएगा, या ऐसे तीसरे देश से भारत सहित किसी अन्य देश में कीमत के आधार पर किया जाएगा, या जहां यह संभव नहीं है, वहां किसी भी उचित आधार पर, जिसमें समान वस्तु के लिए भारत में वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत शामिल है, जिसे उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए, यदि आवश्यक हो, विधिवत समायोजित किया जाएगा। इस प्रकार, प्राधिकरण नोट करता है कि अनुबंध-1 के तहत प्रदान किए गए विभिन्न अनुक्रमिक विकल्पों को ध्यान में रखते हुए सामान्य मूल्य निर्धारित किया जाना आवश्यक है।
60. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पार्टियों द्वारा पहली और दूसरी विधियों के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्माण के लिए कोई जानकारी/सबूत प्रदान नहीं किया गया है। उपर्युक्त सूचना/साक्ष्य के अभाव में प्राधिकरण के लिए प्रथम अथवा द्वितीय विधि के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करना संभव नहीं है। इसलिए, प्राधिकरण ने जांच की अवधि के प्रत्येक तिमाही के लिए तीसरी विधि के आधार पर अर्थात् भारत में वास्तव में भुगतान किए गए या देय मूल्य सहित किसी अन्य युक्तिसंगत आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण करने का निर्णय लिया है। प्राधिकरण ने भारत में भुगतान या देय मूल्य के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्माण किया है।

चीन जन. गण. के लिए निर्यात मूल्य

कोडक (चीन) ग्राफिक कम्प्युनिकेशंस कंपनी लिमिटेड ("कोडक चीन"), ईस्टमैन कोडक कंपनी और कोडक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

61. कोडक चाइना ने विचाराधीन उत्पाद का ***वर्गमीटर भारत को निर्यात किया है। उपर्युक्त निर्यातों में से *** वर्गमीटर पीयूसी ईस्टमैन कोडक कंपनी के माध्यम से निर्यात किया जाता है, जो एक संबंधित व्यापारी है जिसने कोडक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को निर्यात किया है। उत्पादक ने समुद्री मालभाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और अन्य खर्चों, क्रेडिट लागत और पैकिंग लागत के कारण समायोजन का दावा किया है। प्राधिकरण ने विधिवत जांच के बाद निर्माता द्वारा दावा किए गए समायोजन को स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात मूल्य नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

लकी हुआगुआंग ग्राफिक्स कंपनी

62. लकी हुआगुआंग ग्राफिक्स कंपनी ने विचाराधीन *** वर्गमीटर उत्पाद का निर्यात असंबंधित आयातक के माध्यम से भारत को किया है। उपर्युक्त निर्यातों में से *** वर्गमीटर पीयूसी कोडक (चीन) ग्राफिक कम्प्युनिकेशंस कंपनी लिमिटेड के माध्यम से निर्यात किया जाता है। निर्माता ने समुद्री मालभाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और अन्य खर्चों, क्रेडिट लागत और बैंक शुल्क के कारण समायोजन का दावा किया है। प्राधिकरण ने विधिवत जांच के बाद निर्माता द्वारा दावा किए गए समायोजन को स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात मूल्य नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

अनहुइ स्ट्रांग स्टेट न्यू मटेरियल्स कं. लिमिटेड

63. उत्पादक ने जांच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात के रूप में *** वर्ग मीटर की सूचना दी है। उत्पादक ने दावा किया है कि उसने भारत को सीधे उत्पाद का निर्यात किया है और विचाराधीन उत्पाद के निर्यात में कोई अन्य संबंधित/असंबंधित पक्ष शामिल नहीं है। उत्पादक ने समुद्री मालभाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, कमीशन, बंदरगाह और अन्य खर्चों, बैंक शुल्क और क्रेडिट लागत के कारण समायोजन का दावा किया है। प्राधिकरण ने विधिवत जांच के बाद निर्माता द्वारा दावा किए गए समायोजन को स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात मूल्य नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

फुजीफिल्म प्रिंटिंग प्लेट (चीन) कं, लिमिटेड (एफएफपीएस), फुजीफिल्म कॉर्पोरेशन (एफटीवाईओ) और फुजीफिल्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

64. निर्माता ने संबंधित व्यापारी फुजीफिल्म कॉर्पोरेशन (एफटीवाईओ) के माध्यम से जांच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन *** वर्गमीटर उत्पाद का निर्यात किया है, जिसने फुजीफिल्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को निर्यात किया है, जो एक संबंधित आयातक है, जिसने भारतीय बाजार में बेचा है। उत्पादक और निर्यातक ने समुद्री माल दुलाई, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन और ऋण लागत के कारण समायोजन का दावा किया है। प्राधिकरण ने विधिवत जांच करने के बाद निर्माता द्वारा दावा किए गए समायोजन को स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात मूल्य नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

हुआंगशान जिनरुइताई टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड और झेजियांग जिनरुइताई न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड

65. उत्पादक ने जांच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात के रूप में *** वर्ग मीटर की सूचना दी है। उत्पादक ने दावा किया है कि उसने भारत को सीधे उत्पाद का निर्यात किया है और विचाराधीन उत्पाद के निर्यात में कोई अन्य संबंधित/असंबंधित पक्ष शामिल नहीं है। उत्पादक ने समुद्री मालभाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, बंदरगाह और अन्य खर्चों, बैंक शुल्क और क्रेडिट लागत के कारण समायोजन का दावा किया है। प्राधिकरण ने विधिवत जांच के बाद निर्माता द्वारा दावा किए गए समायोजन को स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात मूल्य नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

चोंगकिंग हुआफेंग डि जेट प्रिंटिंग मटेरियल कंपनी लिमिटेड

66. उत्पादक ने जांच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात के रूप में *** वर्गमीटर की सूचना दी है। उत्पादक ने दावा किया है कि उसने भारत को सीधे उत्पाद का निर्यात किया है और विचाराधीन उत्पाद के निर्यात में कोई अन्य संबंधित/असंबंधित पक्ष शामिल नहीं है। उत्पादक ने अंतर्देशीय भाड़ा, हैंडलिंग प्रभार, बैंक प्रभार और ऋण लागत के कारण समायोजन का दावा किया है। प्राधिकरण ने विधिवत जांच के बाद निर्माता द्वारा दावा किए गए समायोजन को स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात मूल्य नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

चीन जन. गण. से सभी गैर-सहकारी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य

67. चीन जनगण से अन्य असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य का निर्धारण नियमों के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है

कोरिया गण.जन. के लिए सामान्य मूल्य

जेइल सी एंड पी कंपनी लिमिटेड

68. निर्माता ने जांच की अवधि में *** वर्गमीटर की घरेलू बिक्री की सूचना दी है। निर्माता ने दावा किया है कि सभी घरेलू बिक्री असंबंधित पार्टियों के लिए हैं। उत्पादक ने गोदाम भंडारण शुल्क, अंतर्देशीय परिवहन, क्रेडिट लागत और मुफ्त माल के कारण समायोजन का दावा किया है। प्राधिकरण ने सामान्य व्यापार ("ओसीटी") परीक्षण किया है। प्राधिकरण नोट करता है कि कुल घरेलू बिक्री का ***% घाटे में चल रहा पाया गया। इसलिए, सामान्य मूल्य के निर्धारण के उद्देश्य से प्राधिकरण सामान्य मूल्य के आधार के रूप में घरेलू बिक्री की अवहेलना करता है। तदनुसार, प्राधिकरण ने 5% के उचित लाभ के साथ उत्पादक के उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य की गणना की।

कोरिया गण. जन. में अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

69. कोरिया गण. जन. के अन्य सभी गैर-सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और इसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

कोरिया गण. जन. के लिए निर्यात मूल्य**जेइल सी एंड पी कंपनी लिमिटेड**

70. उत्पादक ने जांच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यात के रूप में *** वर्गमीटर की सूचना दी है। उत्पादक ने दावा किया है कि उसने भारत को सीधे उत्पाद का निर्यात किया है और विचाराधीन उत्पाद के निर्यात में कोई अन्य संबंधित/असंबंधित पक्ष शामिल नहीं है। उत्पादक ने समुद्री भाड़ा, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन, दलाली, बंदरगाह और अन्य खर्चों, बैंक शुल्क, कूरियर प्रभार, क्रेडिट लागत और शुल्क वापसी के कारण समायोजन का दावा किया है। प्राधिकरण ने विधिवत जांच के बाद निर्माता द्वारा दावा किए गए समायोजन को स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात मूल्य नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

कोरिया गण. जन. से सभी गैर-सहकारी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य

71. कोरिया गण. जन. से अन्य असहकारी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य नियमों के नियम 6 (8) के संदर्भ में उपलब्ध सर्वोत्तम के आधार पर निर्धारित किया गया है।

जापान के लिए सामान्य मूल्य**फुजीफिल्म ग्राफिक सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन, फुजीफिल्म कॉर्पोरेशन और फुजीफिल्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड**

72. फुजीफिल्म कारपोरेशन ने जांच अवधि में *** वर्गमीटर की घरेलू बिक्री की सूचना दी है। निर्माता ने दावा किया है कि सभी घरेलू बिक्री संबंधित पार्टी यानी फुजीफिल्म ग्राफिक सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन को होती है। निर्माता ने बीमा और अंतर्देशीय परिवहन के कारण समायोजन का दावा किया है। प्राधिकरण ने सामान्य व्यापार ("ओसीटी") परीक्षण किया है। प्राधिकरण नोट करता है कि बैंगनी प्लेटों के लिए कुल घरेलू बिक्री का ***% घाटे में चल रहा था। इसलिए, सामान्य मूल्य के निर्धारण के उद्देश्य से प्राधिकरण ने सामान्य मूल्य के आधार के रूप में घरेलू बिक्री की अवहेलना की और 5% के उचित लाभ के साथ-साथ उत्पादक के उत्पादन की लागत के आधार पर बैंगनी प्लेटों के लिए सामान्य मूल्य की गणना की। थर्मल प्लेटों के लिए सामान्य मूल्य की गणना के संबंध में, सभी लाभ कमाने वाले लेनदेन पर विचार किया जाता है। इस प्रकार निर्धारित निवल निर्यात मूल्य नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

73. इस प्रकार निर्धारित पूर्व-कारखाना सामान्य मूल्य का उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

जापान में अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

74. जापान के अन्य सभी गैर-सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और इसका उल्लेख नीचे पाटन मार्जिन तालिका में किया गया है।

जापान के लिए निर्यात मूल्य**फुजीफिल्म ग्राफिक सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन, फुजीफिल्म कॉर्पोरेशन और फुजीफिल्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड**

75. निर्माता ने जांच अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद का *** वर्गमीटर निर्यात किया है, जो एक संबंधित व्यापारी फुजीफिल्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से है, जिसने भारतीय बाजार में असंबंधित ग्राहकों को बेचा है। निर्माता और निर्यातक ने समुद्री माल ढुलाई, बीमा, अंतर्देशीय परिवहन और बंदरगाह तथा अन्य संबंधित खर्चों के कारण समायोजन का दावा किया है। प्राधिकरण ने उचित जांच के बाद निर्माता द्वारा दावा किए गए समायोजन को स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार निर्धारित शुद्ध निर्यात मूल्य नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है।

जापान से सभी असहकारी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य

76. जापान से अन्य असहकारी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य नियमों के नियम 6 (8) के संदर्भ में उपलब्ध सर्वोत्तम के आधार पर निर्धारित किया गया है।

ताइवान और वियतनाम में अन्य उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य

77. चूंकि इन दोनों देशों के किसी उत्पादक/निर्यातक ने अपने प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं, इसलिए ताइवान और वियतनाम के सभी सहयोग न करने वाले उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है और उसका उल्लेख नीचे पाटन माजन तालिका में किया गया है।

ताइवान और वियतनाम से सभी गैर-सहकारी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य

78. ताइवान और वियतनाम के अन्य असहकारी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य नियमों के नियम 6 (8) के संदर्भ में उपलब्ध सर्वोत्तम के आधार पर निर्धारित किया गया है।

पाटन मार्जिन

79. वर्तमान जांच में सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन मार्जिन तिमाही आधार पर निर्धारित किया जाता है और निम्नानुसार है:

पाटन मार्जिन तालिका

क्र.सं.	विशेष	सामान्य मूल्य	शुद्ध निर्यात मूल्य	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन	श्रेणी
		अमरीकी डालर/वर्ग मीटर	अमरीकी डालर/वर्ग मीटर	अमरीकी डालर/वर्ग मीटर	%	%
1	चीन जन. गण.					
क.	लकी हुआगुआंग ग्राफिक्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	40-50
ख.	कोडक चीन ग्राफिक संचार कं, लिमिटेड	***	***	***	***	20-30
ग.	फुजीफिल्म प्रिंटिंग प्लेट (चीन) कं, लिमिटेड	***	***	***	***	20-30
घ.	एन्हुई स्ट्रॉन्ग स्टेट न्यू मटेरियल्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	30-40
ङ.	हुआंगशान जिनरुइताई टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	30-40
च.	चोंगकिंग हुफेंग डि जेट प्रिंटिंग मटेरियल कं, लिमिटे	***	***	***	***	50-60
छ.	कोई अन्य	***	***	***	***	50-60
2	कोरिया गण. जन.					
क.	जेइल सी एंड पी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	80-90
ख.	कोई अन्य	***	***	***	***	90-100
3	जापान					
क.	फुजीफिल्म कॉर्पोरेशन	***	***	***	***	100-110
ख.	कोई अन्य	***	***	***	***	110-120

4	ताइवान					
क.	सभी	***	***	***	***	50-60
5	वियतनाम					
क.	सभी	***	***	***	***	50-60

ज. भौतिक क्षति का मूल्यांकन और कारणात्मक संबंध की जांच

ज.1 अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए प्रस्तुतियाँ

80. अन्य इच्छुक पार्टियों ने क्षति और कारण लिंक के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

- क. उत्पादक/निर्यातक प्रस्तुत करता है कि भारतीय प्रिंटिंग प्लेट बाजार में 48 मिलियन वर्ग मीटर की वार्षिक मांग है, जबकि घरेलू उत्पादन इस मांग का केवल 50% पूरा करता है, जिससे शेष 50% को पूरा करने के लिए आयात पर भारी निर्भरता पैदा होती है।
- ख. विषय देशों से आयात में आधार वर्ष (2019-20) से पीओआई तक 5% की गिरावट आई। टेक्रोवा का खुद के आयात संबंधित देशों से लगभग 3-4% था, जो यह दर्शाता है कि आयात से नुकसान नहीं हो रहा है।
- ग. पीओआई के दौरान, महामारी के वर्षों (2020-21 और 2021-22) के दौरान गिरावट के बाद आयात की मात्रा सामान्य हो गई। उत्पादक/निर्यातक अनुरोध करते हैं कि इन महामारी के वर्षों को विश्लेषण से बाहर रखा जाए, 2019-20 को तुलना के लिए आधार वर्ष के रूप में उपयोग किया जाए।
- घ. उत्पादक/निर्यातक का तर्क है कि पीओआई के दौरान आयात में किसी भी वृद्धि को वास्तविक वृद्धि के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि पूर्व-महामारी के स्तर पर वापसी के रूप में देखा जाना चाहिए।
- ङ. भारत में महत्वपूर्ण मांग-आपूर्ति अंतर निर्यातकों को मूल्य निर्धारण पर काफी लाभ उठाने की अनुमति देता है, जिससे यह संभावना नहीं है कि सभी निर्यातक पाटन में संलग्न हैं या सब्सिडी विशेष रूप से भारतीय बाजार पर लक्षित है।
- च. पीओआई के दौरान चीन और जापान से आयात की कीमतों में काफी वृद्धि हुई, जबकि आयात की उतराई कीमत घरेलू बिक्री मूल्य की तुलना में तेजी से बढ़ी। उदाहरण के लिए, 2019-20 से 2022-23 तक, चीन से लैंडिड की कीमत 217 रुपये/वर्गमीटर (इंडेक्स 100) से बढ़कर 311 रुपये/वर्गमीटर (इंडेक्स 145) हो गई, जबकि घरेलू कीमतें केवल इंडेक्स 100 से बढ़कर 133 हो गईं।
- छ. कीमतों में कमी नगण्य है, क्योंकि पाटन रोधी शुल्क (एडीडी) के साथ लैंडिड कीमतें घरेलू कीमतों से अधिक हैं। उत्पादक/निर्यातक का तर्क है कि आयात से कोई मूल्य प्रभाव नहीं है जो घरेलू उद्योग को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।
- ज. कीमत कम करने और क्षति मार्जिन एक ही सीमा के भीतर हैं, यह दर्शाता है कि आयात महत्वपूर्ण नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। यदि शुद्ध बिक्री प्राप्ति (एनएसआर) और गैर-हानिकारक मूल्य (एनआईपी) बराबर हैं, तो इसका मतलब है कि आयात मूल्य हानिकारक नहीं है।
- झ. घरेलू उद्योग का यह दावा कि आयात अपनी कीमतों को कम करता है, आयात की बढ़ती भूमि मूल्य के विपरीत है, जिसने घरेलू मूल्य वृद्धि को पीछे छोड़ दिया है।
- ञ. आयात की मूल्य वृद्धि में 43% से अधिक और घरेलू मूल्य में केवल 32% की वृद्धि को देखते हुए, उद्योग के अंडरकटिंग के दावे निराधार दिखाई देते हैं।
- ट. उत्पादक/निर्यातक प्रस्तुत करता है कि उत्पाद प्रकारों में व्यापक मूल्यांकन लागू करने के बजाय अधिक दानेदार मूल्यांकन प्राप्त करने के लिए उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन) स्तर पर मूल्य क्षति का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
- ठ. क्रिसिल रिपोर्ट टेक्रोवा के लिए एक मजबूत फाइनैशियल स्थिति दिखाती है, जिसमें वित्तीय 2023 में 35% वर्ष-दर-वर्ष राजस्व वृद्धि और 2024 में "स्थिर" से "सकारात्मक" तक बेहतर दृष्टिकोण है।

- ड. वित्तीय 2022 में टेक्नोवा की 38% की राजस्व वृद्धि को कोविड के बाद बाजार को फिर से खोलने से समर्थन दिया गया था, स्थिर कमोडिटी की कीमतों और मूल्य निर्धारण लचीलेपन के कारण और सुधार की उम्मीदों के साथ.
- ढ. टेक्नोवा को एक विविध ग्राहक आधार, मजबूत नकदी उपार्जन, कम उत्तोलन और उच्च व्याज कवरेज प्राप्त है, जो क्षति के दावों का खंडन करता है।
- ण. अपने एनएसआर को लगातार बढ़ाने के बावजूद, घरेलू उद्योग घाटे का दावा करता है, जो उत्तरदाताओं ने आयात के बजाय कुप्रबंधन या आंतरिक अक्षमताओं को जिम्मेदार ठहराया है।
- त. फेडरेशन का दावा है कि टेक्नोवा अनुचित व्यापार प्रथाओं को संबोधित करने के बजाय मार्जिन में सुधार के लिए व्यापार उपचारात्मक उपायों का उपयोग कर रहा है। कंपनी का वित्तीय डेटा भौतिक क्षति के अपने दावों का खंडन करता है।
- थ. टेक्नोवा का मजबूत वित्तीय प्रदर्शन, जैसा कि क्रिसिल रिपोर्ट में परिलक्षित होता है, यह बताता है कि संभावित क्षति के दावे अतिरंजित हैं, और निरंतर सुरक्षा का उद्देश्य लाभ मार्जिन को बढ़ाना हो सकता है।
- द. उत्तरदाताओं का तर्क है कि लाभप्रदता और वित्तीय स्थिरता में वृद्धि के बावजूद, घरेलू उद्योग ने अपनी क्षमता का विस्तार नहीं किया है या उत्पादन के मुद्दों को संबोधित नहीं किया है, जिससे आयात पर निर्भरता जारी है।
- ध. घरेलू उत्पादन प्रिंटिंग प्लेटों की कुल बाजार मांग का केवल लगभग 50% पूरा करता है, और घरेलू उद्योग ने क्षमता विस्तार योजनाओं के दावों के बावजूद अपनी क्षमता का विस्तार नहीं किया है।
- न. उत्पादक/निर्यातक नोट करते हैं कि पूर्व वर्षों की तुलना में पीओआई के दौरान पीयूसी का घरेलू उत्पादन काफी बढ़ गया, जो वित्त वर्ष 2020-21 में 68 इंडेक्स पॉइंट से बढ़कर पीओआई के दौरान 93 इंडेक्स पॉइंट हो गया. इससे पता चलता है कि घरेलू उद्योग केवल व्यापार सुरक्षा पर भरोसा किए बिना उत्पादन में सुधार करने में सक्षम है।
- प. पीओआई के दौरान प्रति कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि हुई, जो वित्त वर्ष 2020-21 में 68 सूचकांक बिंदुओं से बढ़कर पीओआई के दौरान 94 सूचकांक अंक हो गई, जो परिचालन दक्षता को दर्शाती है।
- फ. पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग के लिए इन्वेंटरी स्तर में लगभग 45% की गिरावट आई, जो क्षति के दावों का खंडन करता है।
- ब. क्षमता विस्तार के दावों के बावजूद, घरेलू उद्योग ने घरेलू मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन को पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ाया है, जिससे आयात पर निर्भरता बढ़ गई है।
- भ. उत्तरदाताओं का तर्क है कि गैर-हानिकारक मूल्य (एनआईपी) की गणना में डीजीटीआर द्वारा उपयोग की जाने वाली पूंजी नियोजित (आरओसीई) पर 22% रिटर्न फुलाया जाता है और वर्तमान बाजार वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करता है, जैसे कि कम व्याज और कॉर्पोरेट कर दरें।
- म. सीस्टेट के फैसलों ने 22% आरओसीई की तर्कसंगतता के बारे में चिंता जताई है, यह सुझाव देते हुए कि गैर-पाटन अवधि के दौरान अर्जित वास्तविक लाभ का उपयोग NIP की गणना के लिए किया जाना चाहिए।
- य. यूरोपीय संघ गैर-पाटन अवधि के दौरान अर्जित मुनाफे के आधार पर उचित रिटर्न निर्धारित करने की प्रथा का पालन करता है, जिसे डीजीटीआर को अपनाने पर विचार करना चाहिए।
- कक. उत्पादक/निर्यातक प्रस्तुत करता है कि नियोजित पूंजी के ऋण और निवल मूल्य घटकों दोनों पर एक समान 22% आरओसीई लागू करने से घरेलू उद्योग के लिए अत्यधिक लाभ मार्जिन होता है, क्षति और मूल्य कम बिक्री गणना विकृत होती है।
- खख. आवेदक द्वारा प्रस्तुत आयात आंकड़ों में विसंगतियां हैं, विशेष रूप से चीन से मात्रा के संबंध में, जो क्षति के दावों को विकृत करता है। उत्पादक/निर्यातक अनुरोध करता है कि अधिक सटीक विश्लेषण प्रदान करने के लिए टेक्नोवा के स्वयं के आयात को समग्र आयात मात्रा से बाहर रखा जाए।

- गग. गैर-विषयक देशों के माध्यम से छल करने का घरेलू उद्योग का दावा निराधार है, क्योंकि गैर-विषयक देशों से आयात न्यूनतम रहते हैं।
- घघ. घरेलू उद्योग का तर्क है कि शून्य शुल्क आयात से नुकसान हो रहा है, लेकिन उत्तरदाताओं का तर्क है कि ये आयात अंतिम निष्कर्षों के आधार पर गैर-हानिकारक हैं।
- ङङ. घरेलू उद्योग उत्पादन लागत में वृद्धि का दावा करता है, लेकिन एल्यूमीनियम की कीमतों में गिरावट (उत्पादन का एक प्रमुख घटक) इस दावे का खंडन करती है।
- चच. फेडरेशन का तर्क है कि एनएसआर में वृद्धि और घटती लागत के बावजूद घरेलू उद्योग की घाटे को सही ठहराने में असमर्थता आंतरिक अक्षमताओं या कुप्रबंधन का सुझाव देती है, न कि आयात से संबंधित क्षति।
- छछ. यह भी आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता को चीन से विकृत कीमतों से लाभ होता है क्योंकि यह स्वयं अपने कच्चे एल्यूमीनियम का लगभग 60-70% चीन से प्राप्त करता है, शेष अन्य क्षेत्रों से आता है। इसके अलावा, चीन से कच्चे माल के आयात की कीमतें यूरोपीय संघ की तुलना में कम हैं।
- जज. घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य और आयात के उतराई तक के मूल्य के बीच तुलना अनुपयुक्त है क्योंकि आयात के विपरीत घरेलू कीमत में काफी बिक्री और वितरण लागत शामिल होती है।
- झझ. आयातक ने आरोप लगाया है कि याचिकाकर्ता यह बताने में विफल रहा है कि एलएमई की कीमतों से जुड़े होने के बावजूद पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि (पीओआई) के दौरान बिक्री की लागत में कमी क्यों नहीं आई है।
- ञञ. उपयोगकर्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता के दावा किए गए नुकसान को फुलाया जाता है, जैसा कि क्रेडिट एजेंसी की रिपोर्ट में उजागर किए गए आर्थिक कारकों से स्पष्ट है।
- टट. टेक्नोवा ने आयात पर पाटन रोधी शुल्क के बावजूद दाम नहीं बढ़ाने की रणनीति तैयार की है। नतीजतन, भविष्य में भी कर्तव्य अप्रभावी रहेगा।
- ठठ. क्षति, यदि कोई हो, आंतरिक प्रतिस्पर्धा के कारण है, विशेष रूप से एक नए निर्माता, एचएल प्रिंटिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से, जिसका उत्पादन पीओआई के दौरान 3.3 गुना बढ़ गया।
- डड. पीओआई के दौरान आवेदक की निर्यात बिक्री में 22% की गिरावट ने निश्चित लागत में वृद्धि की, जिससे किसी भी संभावित क्षति में योगदान हुआ।
- ढढ. आवेदक की इन्वेंट्री में आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में लगभग 45% की गिरावट आई है, जो कोई क्षति या पुनरावृत्ति की संभावना नहीं दर्शाता है।
- णण. प्रति कर्मचारी आवेदक की उत्पादकता वित्त वर्ष 2020-21 में 68 सूचकांक बिंदुओं से बढ़कर पीओआई के दौरान 94 सूचकांक अंक हो गई।
- तत. आवेदक के पीयूसी उत्पादन में पिछले दो वर्षों की तुलना में पीओआई के दौरान काफी वृद्धि हुई है। पीयूसी उत्पादन वित्त वर्ष 2020-21 में 68 सूचकांक बिंदुओं से बढ़कर पीओआई के दौरान 93 सूचकांक अंक हो गया।
- थथ. कोडक प्रस्तुत करता है कि उत्पाद विषम और अंतर-गैर-प्रतिस्थापन योग्य है, उत्पादन की लागत, उत्पादन प्रक्रिया और मशीन-विशिष्ट अंतिम उपयोग में अंतर के कारण। कोडक प्राधिकरण से भारित औसत आधार यानी पीसीएन स्तर पर मूल्य क्षति करने का अनुरोध करता है।
- दद. टेक्नोवा ने कुल राजस्व में 70% से अधिक का योगदान देने के बावजूद विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के लिए महत्वपूर्ण नुकसान की सूचना दी है, जिससे चिंता बढ़ गई है कि खर्च पीयूसी को असमान रूप से आवंटित किया जा सकता है, अन्य उत्पादों के लिए नुकसान और मुनाफे को बढ़ा सकता है।
- धध. टेक्नोवा पीएस प्लेटों अवसंरचनात्मक लागत के साथ जारी है। इसके अलावा, कंपनी उस समय टेक्नोवा द्वारा उठाए जा रहे सभी निश्चित लागतों को उठाना जारी रखती है। चूंकि कंपनी उन निश्चित लागतों को उठाना जारी रखती है, इसलिए यह स्पष्ट है कि उन सभी निश्चित लागतों को अब डिजिटल प्लेटों से चार्ज किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप डिजिटल प्लेटों के उत्पादन की लागत में वृद्धि हुई है।

- नन. यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक उद्योग के पीयूसी उत्पादन में पिछले दो वर्षों की तुलना में जांच की अवधि (पीओआई) में काफी वृद्धि हुई है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि आवेदक का पीयूसी उत्पादन वित्त वर्ष 2020-21 में 68 सूचकांक बिंदुओं से बढ़कर पीओआई के दौरान 93 सूचकांक अंक हो गया।
- पप. प्रति कर्मचारी आवेदक की उत्पादकता वित्त वर्ष 2020-21 में 68 सूचकांक बिंदुओं से बढ़कर पीओआई के दौरान 94 सूचकांक अंक हो गई।
- फफ. आवेदक की इन्वेंट्री में आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में लगभग 45% की गिरावट आई है, जो कोई क्षति या पुनरावृत्ति की संभावना नहीं दर्शाता है।
- बब. आवेदक की शुद्ध बिक्री वसूली (एनएसआर) गैर-हानिकारक मूल्य (एनआईपी) से अधिक है, जो क्षति या क्षति जारी रहने की संभावना का सुझाव देती है।
- भभ. पीओआई के दौरान आवेदक की निर्यात बिक्री में 22% की गिरावट ने निश्चित लागत में वृद्धि की, जिससे किसी भी संभावित क्षति में योगदान हुआ।
- मम. प्राधिकरण को निम्नलिखित की भी जांच करनी चाहिए: (i) क्या टेकनोवा की कच्चे माल की कीमतें वैश्विक कीमतों के साथ तुलनीय हैं या कीमतें कंपनी द्वारा दर्ज किए गए दीर्घकालिक अनुबंधों से प्रभावित थीं जब एल्यूमीनियम की कीमतें चरम पर थीं। प्राधिकरण से अनुरोध है कि दीर्घावधि संविदाओं के कारण मालसूची में हुई हानि के मामले में मालसूची का पुनर्मूल्यांकन किया जाए (ii) गैर-हानिकारक मूल्य, उत्पादन लागत और अन्य आथक अनुद्धेदमीटरों की गणना के लिए मासिक एल्युमिनियम खरीद मूल्य पर विचार करें (iii) प्रत्येक संयंत्र स्तर पर विभिन्न पीसीएन के लिए उत्पादन लागत में परिलक्षित एल्युमिनियम की कीमतों की तुलना करें।
- यय. सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 14 और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, लोडिंग, अनलोडिंग और हैंडलिंग शुल्क निर्धारण योग्य मूल्य का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसलिए, कोडक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भुगतान किए गए इन शुल्कों को माल के उतरा मूल्य की गणना के लिए शामिल किया जाना चाहिए। मूल जांच में, डीजीटीआर ने भू-मूल्य की गणना के लिए हैंडलिंग शुल्क शामिल नहीं किया था क्योंकि इच्छुक पार्टियों ने वास्तविक हैंडलिंग शुल्क की तुलना में नोशनल हैंडलिंग शुल्क की सूचना दी थी। तथापि, वर्तमान जांच में केआईपीएल ने वास्तविक लोडिंग/अनलोडिंग/हैंडलिंग प्रभार दिए हैं और इसे लैंडेड मूल्य में शामिल किया जाना चाहिए।

ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण

81. घरेलू उद्योग ने क्षति और कारण लिंक के संबंध में निम्नलिखित प्रस्तुतियां की हैं:

- क. पाटनरोधी नियमावली के नियम 23(3) में कहा गया है कि पाटनरोधी नियमावली का नियम 11 घरेलू उद्योग को हुई भौतिक क्षति का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए सूर्यास्त समीक्षा पर लागू होता है।
- ख. आयातों के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए, घरेलू उद्योग ने पीयूसी के लिए मात्रा में क्षति, मूल्य क्षति और आथक मानदंडों पर निष्पादन के संबंध में संगत सूचना उपलब्ध कराई है।
- ग. घरेलू उद्योग यह भी स्पष्ट करता है कि प्राधिकरण ने पीयूसी के संबंध में कंपनी की क्षति और लाभप्रदता के संबंध में प्रासंगिक जानकारी को विधिवत सत्यापित किया है।
- घ. आधार वर्ष से पीओआई में आयात की मात्रा में मामूली गिरावट देखी गई है। इस कमी को पाटन रोधी कर्तव्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसने संबंधित देशों से आयात को कुछ हद तक रोक दिया है, विशेष रूप से चीन जन. गण. और ताइवान के अलावा अन्य देशों से। घरेलू उद्योग का कहना है कि जहां अन्य देशों से आयात में कमी आई है, वहीं चीन जन. गण. और ताइवान से आयात में इंजरी अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।
- ङ. पीओआई के दौरान आयात स्तर ने पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई है, विशेष रूप से वित्त वर्ष 2021-22 में।

- च. घरेलू उद्योग यह प्रस्तुत करता है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में संबंधित वस्तुओं का आयात आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में समान रहा है। पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद उत्पादन की तुलना में आयात में कोई गिरावट नहीं देखी गई।
- छ. मांग के संबंध में विषय आयात आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में समान रहा है। तथापि, चीन जनसंपर्क से आयात का हिस्सा आधार वर्ष में 31% से बढ़कर पीओआई में 33% हो गया है।
- ज. यह ध्यान दिया जा सकता है कि पिछले वर्ष यानी 2021-22 की तुलना में पीओआई में घरेलू उत्पादन और मांग दोनों के संबंध में आयात विषय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- झ. यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि उत्पादन के संबंध में चीन जन. गण. से विषय वस्तुओं का आयात आधार वर्ष की तुलना में बढ़ गया है। वर्ष 2019-20 में चीन जन. गण. से आयात घरेलू उद्योग के उत्पादन का लगभग 46% था, जो पीओआई में बढ़कर 49% हो गया है।
- ञ. इन देशों से आयात घरेलू उद्योग के घरेलू बिक्री मूल्य से कम मूल्यों पर हो रहे हैं जिससे इसके बिक्री मूल्य में भारी कमी आ रही है और घरेलू उद्योग को क्षति पहुंच रही है। इन घटती कीमतों ने सीधे तौर पर नुकसान में वृद्धि की है।
- ट. भारत में आयात अहानिकारक कीमतों की तुलना में काफी कम मूल्य पर हो रहे हैं और इसलिए घरेलू उद्योग को गंभीर और वास्तविक क्षति हो रही है। ऐसे कम मूल्य वाले आयातों ने उचित बिक्री मूल्य प्राप्त करने से रोककर घरेलू उद्योग के निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।
- ठ. मूल्य दमन घरेलू उद्योग की बिक्री मूल्य की लागत में परिवर्तन के प्रभाव को प्रतिबिंबित करने में असमर्थता है। मूल्य दमन घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्यों में परिवर्तन की तुलना में लागत में परिवर्तन के बीच एक डेल्टा है।
- ड. घरेलू उद्योग के लिए बनाने और बेचने की लागत में काफी वृद्धि हुई है, अर्थात्, आधार वर्ष 2019-20 की तुलना में पीओआई में 41 अनुक्रमित बिंदुओं तक। इसी अवधि के दौरान, घरेलू उद्योग संबंधित देशों से आयातों के कारण पीयूसी के बिक्री मूल्य में इसकी लागत में वृद्धि के अनुरूप वृद्धि नहीं कर सका। इसके अलावा, पाटित आयातों के कारण पीओआई में मूल्य में काफी वृद्धि हुई है।
- ढ. चीन जन. गण. से आयात का बाजार हिस्सा पिछले वर्ष की तुलना में आधार वर्ष में 31% से बढ़कर पीओआई में 33% और पीओआई में 12% हो गया है।
- ण. विषय वस्तुओं की मांग में पर्याप्त वृद्धि के बावजूद पिछले वर्ष की तुलना में पीओआई में घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में 9% की कमी आई है।
- त. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में भी आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में कमी देखी गई है।
- थ. चीन जनगण और ताईवान को छोड़कर अन्य देशों की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है, जिसका मुख्य कारण पाटनरोधी शुल्क लगाना है।
- द. पीयूसी के उत्पादन में गिरावट की तुलना में घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में काफी तेज गति से गिरावट आई है। यह स्पष्ट रूप से संबंधित देशों, विशेष रूप से चीन जनगण से निरंतर डंप किए गए आयातों के कारण है।
- ध. घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में विषय वस्तुओं की मांग में पर्याप्त वृद्धि के बावजूद गिरावट आई।
- न. आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग में भी गिरावट आई है।
- प. प्रतिदिन उत्पादकता आधार वर्ष में 100 सूचकांक अंकों से घटकर जांच अवधि में 93 सूचकांक अंकों पर आ गई है। कर्मचारियों की संख्या में भी 2 सूचकांक अंकों की कमी आई है।
- फ. इसी समय, कर्मचारियों को वेतन में आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में 11 अनुक्रमित अंकों की वृद्धि हुई।
- ब. संबंधित देशों से निरंतर और लगातार डंप किए गए आयातों से घरेलू उद्योग के सभी वित्तीय निष्पादन संकेतकों जैसे पीबीआईटी, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर आय में उल्लेखनीय गिरावट आई है।

- भ. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग का घाटा दुगुने से भी अधिक हो गया है। घरेलू उद्योग की हानियों में आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में 315 अनुक्रमित बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। यह मुख्यतः संबद्ध देशों, विशेष रूप से चीन जनगण से निर्यातकों द्वारा लिए गए मूल्य निर्धारण संबंधी पर्याप्त दबाव के कारण है।
- म. घरेलू उद्योग को क्षति अवधि के दौरान नकद हानि हुई और पीओआई में इसमें तेजी आई है।
- य. नियोजित पूंजी पर रिटर्न में आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में 220 अनुक्रमित अंकों की गिरावट आई है।
- कक. आधार वर्ष 2019-20 की तुलना में पीओआई में तैयार माल के भंडार का स्तर काफी बढ़ गया है।
- खख. पाटित किए गए आयातों के कारण घरेलू उद्योग के पीयूसी व्यवसाय के वित्तीय प्रदर्शन में स्पष्ट रूप से गिरावट आई है। पीयूसी घरेलू उद्योग के लिए एक बड़े उत्पाद पोर्टफोलियो का हिस्सा है, और वित्तीय प्रदर्शन में गिरावट ने प्रतिस्पर्धी दरों पर पूंजी आकर्षित करने की घरेलू उद्योग की समग्र क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।
- गग. चीनी निर्यातकों ने श्रीलंका और स्पेन के रूप में आयात की उत्पत्ति की गलत घोषणा करके पाटन रोधी शुल्क का अपवंचन किया, जिससे कम कीमत वाले सामानों की एक महत्वपूर्ण आमद हुई जिसने घरेलू उद्योग को गंभीर रूप से प्रभावित किया। इस छल ने कर्तव्यों के लाभों को शून्य कर दिया।
- घघ. घरेलू उद्योग की क्षमता विस्तार योजनाओं में कोविड-19 महामारी से और देरी हुई, जिसने कम मांग, लॉकडाउन और वित्तीय दबावों सहित अप्रत्याशित चुनौतियों को लाया, जिससे उन्हें कर्तव्यों का पूरा लाभ उठाने से रोका गया।
- ङङ. कुछ पार्टियों ने तर्क दिया कि वे गैर-हानिकारक मूल्य (एनआईपी) से ऊपर उत्पाद बेच रहे हैं और उन्हें घरेलू उद्योग के लिए हानिकारक नहीं माना जाना चाहिए। घरेलू उद्योग ने इस बात पर सहमति जताई कि उचित मूल्य वाले आयात हानिकारक नहीं हैं, लेकिन इस बात पर प्रकाश डाला गया कि संबंधित देशों से आयात की पर्याप्त मात्रा एनआईपी से नीचे की कीमतों पर डंप की जा रही है, जिससे काफी नुकसान हो रहा है।
- चच. जबकि गैर-हानिकारक आयात मौजूद हैं, घरेलू उद्योग ने इस बात पर जोर दिया कि हानिकारक कीमतों पर पाटित किए गए आयात कीमतों को कम करके, बाजार हिस्सेदारी को कम करके और लाभप्रदता को कम करके घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। प्राधिकरण को इन हानिकारक आयातों के प्रभाव को अवश्य पहचानना चाहिए।
- छछ. कुछ इच्छुक पार्टियों का तर्क है कि वर्तमान जांच में कोई वॉल्यूम प्रभाव नहीं है और कोविड-2019 के कारण वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के डेटा को खारिज करते हुए, जांच की अवधि (पीओआई) में आयात मात्रा की तुलना वित्त वर्ष 2019-20 से करने का सुझाव देते हैं। घरेलू उद्योग का कहना है कि इस तरह के विश्लेषण से मूल्यांकन में कमी आएगी, क्योंकि पाटन रोधी शुल्क आयात को रोकते हैं, और पीओआई के दौरान आयात की मात्रा वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में काफी बढ़ गई है।
- जज. कुछ पार्टियों का तर्क है कि घरेलू उद्योग ने 3-4% विषय आयात आयात करके अपनी क्षति पहुंचाई। घरेलू उद्योग इस दावे का खंडन करते हुए स्पष्ट करता है कि आयात मात्रा की गणना अपने स्वयं के आयात को छोड़कर की जाती है।
- झझ. इच्छुक पार्टियों का तर्क है कि आयात ने कीमतों को प्रभावित नहीं किया है। हालांकि, घरेलू उद्योग दर्शाता है कि चीनी आयात की कीमतें लगातार अपनी शुद्ध बिक्री प्राप्ति से कम रही हैं, जिससे महत्वपूर्ण मूल्य दमन हुआ है। हालांकि घरेलू लागत में 23% की वृद्धि हुई, घरेलू कीमतों में केवल 17% की वृद्धि हुई, जो दबी हुई चीनी कीमतों के प्रभाव को उजागर करती है।
- ञञ. कपूर का तर्क है कि कोडक चाइना और लकी से आयात की कीमत में पाटन रोधी शुल्क शामिल होना चाहिए और उनकी पुनर्विक्रय कीमतों की तुलना करनी चाहिए। घरेलू उद्योग यह कहते हुए इसे खारिज करता है कि पाटन रोधी शुल्क के बिना लैंडिड कीमतों की गणना करना और उनकी तुलना घरेलू कीमतों से करना एक मानक प्रथा है, जो पहले से ही प्रासंगिक लागतों के लिए जिम्मेदार हैं।
- टट. कुछ पक्षों ने लंदन मेटल एक्सचेंज (एलएमई) एल्यूमीनियम की कीमतों में कमी का हवाला देते हुए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत में 26% की वृद्धि दर्ज की है। घरेलू उद्योग का तर्क है कि (i) प्रदान की गई जानकारी अविश्वसनीय है, (ii) एलएमई पर एल्यूमीनियम का सीएसपी बढ़ गया है, और (iii) लागत में वृद्धि प्रीमियम

और खरीद लागत के कारण है, जिसे प्राधिकरण द्वारा ऑन-साइट निरीक्षण के दौरान सत्यापित किया गया है।

- ठठ. एआईएफएमपी और कपूर टेकनोवा के वित्तीय प्रदर्शन को दिखाने वाली क्रिसिल रिपोर्ट पर भरोसा करते हैं, लेकिन घरेलू उद्योग का तर्क है कि रिपोर्ट में टेकनोवा के समग्र व्यवसाय को शामिल किया गया है, न कि केवल डीओपीपी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पाटन रोधी कर्तव्यों को हटाने से घरेलू उद्योग को नुकसान की पुष्टि करते हुए महत्वपूर्ण आयात और प्रतिस्पर्धा हुई।

ज.3 प्राधिकरण द्वारा समीक्षा

82. एडी नियम, 1995 के अनुबंध II के साथ पठित एडी नियम, 1995 के नियम 11 में प्रावधान है कि क्षति निर्धारण में उन कारकों की जांच शामिल होगी जो घरेलू उद्योग को क्षति का संकेत दे सकते हैं, "... पाटित आयातों की मात्रा, घरेलू बाजार में समान वस्तुओं की कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए..."। इसके अलावा, मूल्यों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए यह जांच करना आवश्यक समझा जाता है कि क्या भारत में इसी प्रकार की वस्तु के मूल्य की तुलना में पाटित आयातों द्वारा मूल्य में काफी कमी की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा मूल्यों को काफी हद तक कम करने अथवा मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए है। जो अन्यथा एक महत्वपूर्ण डिग्री के लिए हुआ होगा।
83. नियमावली के नियम 23 में यह प्रावधान है कि समीक्षा के मामले में नियम 6,7,8,9, 10, 11, 16, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों के साथ परिवर्तन लागू होंगे। यदि घरेलू उद्योग के कार्य-निष्पादन से यह पता चलता है कि चालू क्षति अवधि के दौरान उसे कोई क्षति नहीं पहुंची है तो प्राधिकरण यह निर्धारित करेगा कि क्या वर्तमान शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
84. क्षति और कारण लिंक के संबंध में जांच के दौरान घरेलू उद्योग और अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण और प्राधिकरण द्वारा प्रासंगिक समझे जाने की जांच की जाती है और प्रासंगिक मानदंडों के तहत नीचे संबोधित किया जाता है।
85. प्राधिकरण नोट करता है कि यह आवश्यक नहीं है कि क्षति के सभी अनुछेद मीटर गिरावट दिखाते हैं। कुछ अनुछेद मीटर गिरावट दिखा सकते हैं, जबकि कुछ अन्य नहीं दिखा सकते हैं। प्राधिकरण घरेलू उद्योग के वित्तीय अनुछेद मीटरों का मूल्यांकन करने के लिए सभी क्षति मानदंडों पर विचार करता है। प्राधिकरण ने घरेलू उद्योग और अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और तर्कों पर विचार करते हुए क्षति संबंधी मानदंडों की निष्पक्ष जांच की है।
86. प्रोफार्मा IV-क में निहित क्षति संबंधी आंकड़ों को ऐसे विलम्बित चरण में बदलने के लिए विभिन्न इच्छुक पार्टियों के आरोपों के संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि प्रोफार्मा IV-क में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए परिवर्तन सत्यापन के दौरान पहचाने गए सुधारों के कारण हैं, जो प्रकृति में बहुत कम हैं और समग्र क्षति मूल्यांकन को प्रभावित नहीं करते हैं। इसके अलावा, प्राधिकरण नोट करता है कि घरेलू उद्योग द्वारा किए गए परिवर्तन वर्तमान समीक्षा में क्षति के आकलन को भौतिक रूप से नहीं बदलते हैं। प्राधिकरण ने अद्यतन आंकड़ों को रिकॉर्ड पर लिया है और वर्तमान अंतिम निष्कर्षों के उद्देश्य से इस पर भरोसा किया है।
87. प्राधिकरण नोट करता है कि आयात माप की विभिन्न इकाइयों में किया गया है, जिसमें एसक्यूएम, केजी, टुकड़े और मामले शामिल हैं। आयात की मात्रा मानक परिवर्तन मानदण्ड अर्थात् 132 वर्ग मीटर प्रति किग्रा के आधार पर एसक्यूएम में निर्धारित की गई है। जहां तक एसक्यूएम अथवा केजी में आयात नहीं किए जाने का संबंध है, उनकी मात्रा को उत्पादों के आयात लेन-देन विवरण में दर्शाई गई सूचना (मात्रा, आयाम आदि) के आधार पर परिवर्तित किया गया है। छांटे गए डीजी सिस्टम्स डाटा पर वर्तमान अंतिम निष्कर्षों में क्षति के मूल्यांकन के उद्देश्य से विचार किया गया है।

88. इच्छुक पक्षों के इस दावे के संबंध में प्राधिकरण कि गैर-हानिकारक मूल्य (एनआईपी) की गणना में डीजीटीआर द्वारा प्रयुक्त 22% नियोजित पूंजी रिटर्न (आरओसीई) बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है और वर्तमान बाजार वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करता है, जैसे कि कम ब्याज और कॉर्पोरेट कर की दरें, नोट करती है कि 22% नियोजित पूंजी दर (आरओसीई) को सभी पाटन रोधी जांचों में मानक अभ्यास के रूप में लगातार लागू किया जाता है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि मेरिनो पैनल उत्पादों के मामले में एलडी सीईएसटीएटी ने 22% आरओसीई लागू करने के डीजीटीआर के अभ्यास को बरकरार रखा।

क्षति का संचयी मूल्यांकन

89. डब्ल्यूटीओ पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.3 और एडी नियमावली के अनुलग्नक II के अनुच्छेद (iii) में प्रावधान है कि ऐसे मामलों में जहां एक से अधिक देशों से किसी उत्पाद के आयात की एक साथ पाटनरोधी जांच की जा रही है, प्राधिकरण ऐसे आयातों के प्रभाव का संचयी रूप से आकलन करेगा, यदि वह यह निर्धारित करता है कि:
- क. प्रत्येक देश से आयात के संबंध में स्थापित पाटन का मार्जिन निर्यात मूल्य के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया दो प्रतिशत से अधिक है और प्रत्येक देश से आयात की मात्रा समान वस्तु के आयात का तीन प्रतिशत (या अधिक) है या जहां अलग-अलग देशों का निर्यात तीन प्रतिशत से कम है, आयात सामूहिक रूप से समान वस्तु के आयात के सात प्रतिशत से अधिक के लिए जिम्मेदार है; और
 - ख. आयातित वस्तुओं और इसी प्रकार की घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है।
90. प्राधिकरण नोट करता है कि इन देशों से आयात की मात्रा एडी नियमों के तहत निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक है।
91. यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या आयातित वस्तुओं और ऐसी घरेलू वस्तुओं के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयातों के प्रभाव का संचयी मूल्यांकन उपयुक्त है, निम्नलिखित अनुच्छेद मीटरों की जांच की गई है
- क. विभिन्न पार्टियों द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद लेख की तरह हैं और गुणों में तुलनीय हैं
 - ख. घरेलू स्तर पर उत्पादित उत्पाद और आयातित उत्पाद विनिमय हैं। उपभोक्ता घरेलू उत्पादों और आयातित उत्पादों का परस्पर उपयोग कर रहे हैं और निर्यातक और घरेलू उद्योग ने एक ही उत्पाद को ग्राहकों के एक ही सेट को बेचा है।
 - ग. घरेलू उत्पाद और आयातित उत्पाद के बीच सीधी प्रतिस्पर्धा होती है और आयातित उत्पादों के बीच परस्पर प्रतिस्पर्धा होती है।
 - घ. विषय देशों से आयात मूल्य एक दूसरे के साथ चलते रहे हैं।
92. प्राधिकरण नोट करता है कि घरेलू उद्योग ने सबूत दिए हैं कि संबंधित देशों के घरेलू उत्पादक और निर्यातक ग्राहकों की एक ही श्रेणी को 'समान' उत्पाद बेचते हैं, और दोनों एक ही बाजार में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। दोनों उत्पादों का उपभोक्ताओं द्वारा परस्पर उपयोग किया जा रहा है। डीजी सिस्टम डाटा के माध्यम से भी प्राधिकरण द्वारा इसका पता लगाया गया है।
93. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण घरेलू उद्योग पर संबंधित देशों से विचाराधीन उत्पाद के पाटित आयातों के प्रभावों का संचयी मूल्यांकन करना उपयुक्त समझता है।
94. प्राधिकरण ने नीचे दिए गए अनुच्छेद में घरेलू उद्योग की स्थिति पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच की है।

ज.3.1 मांग का आकलन

95. प्राधिकरण ने वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए, भारत में विचाराधीन उत्पाद की मांग या स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग और अन्य भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी स्रोतों से आयात के योग के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार आकलित मांग नीचे सारणी में दी गई है।

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
विषय देशों से आयात	वर्गमीटर	1,38,48,618	62,84,725	67,27,717	1,23,85,703

	अनुक्रमित	100	45	49	89
आयात गैर-विषय देश	वर्गमीटर	6,56,716	10,82,464	19,61,069	19,17,453
	अनुक्रमित	100	165	299	292
कुल आयात	वर्गमीटर	1,45,05,334	73,67,190	86,88,785	1,43,03,156
	अनुक्रमित	100	51	60	99
घरेलू उद्योग की बिक्री	वर्गमीटर	***	***	***	***
	अनुक्रमित	100	73	95	94
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री	वर्गमीटर	***	***	***	***
	अनुक्रमित	100	23,100	1,73,463	1,67,345
कुल मांग/खपत	वर्गमीटर	***	***	***	***
	अनुक्रमित	100	66	86	98

96. यह ध्यान दिया जाता है कि 2019-20 की तुलना में 2020-21 में विषय वस्तुओं की मांग में गिरावट आई थी, लेकिन इसके बाद 2021-22 और पीओआई में वृद्धि हुई। हालांकि, जांच अवधि के दौरान मांग काफी हद तक स्थिर रही है। वर्ष 2020-21 और 2021-22 में संबंधित वस्तुओं की मांग में गिरावट कोविड-19 महामारी के कारण है।

ज.3.2 संबद्ध देशों से आयात का मात्रा प्रभाव

97. आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकरण को यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में आयात में निरपेक्ष रूप से अथवा उत्पादन अथवा खपत के सापेक्ष उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। क्षति विश्लेषण के उद्देश्य से, प्राधिकरण ने डीजी सिस्टम से प्राप्त लेनदेन वार आयात डेटा पर भरोसा किया है।

क. आयात में सापेक्ष वृद्धि

98. क्षति की अवधि के दौरान विषय देशों से विषय वस्तुओं के आयात की मात्रा और घरेलू उद्योग के उत्पादन और संबंधित वस्तुओं की मांग के संबंध में जांच की अवधि निम्नानुसार है:

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
याचिकाकर्ता के उत्पादन के संबंध में आयात					
विषय देश	%	***	***	***	***
	श्रेणी	40-50	20-30	20-30	40-50
गैर-विषय देश	%	***	***	***	***
	श्रेणी	0-10	0-10	0-10	0-10
कुल आयात	%	***	***	***	***
	श्रेणी	40-50	30-40	30-40	40-50

देश में मांग के संबंध में आयात					
विषय देश	%	***	***	***	***
	श्रेणी	30-40	20-30	10-20	20-30
गैर-विषय देश	%	***	***	***	***

	श्रेणी	0-10	0-10	0-10	0-10
कुल आयात	%	***	***	***	***
	श्रेणी	30-40	30-40	30-40	30-40

ख. आयात में पूर्ण वृद्धि

99. क्षति की अवधि के दौरान विषय देशों से विषय वस्तुओं के आयात की मात्रा और विषय वस्तुओं की पूर्ण शर्तों में जांच की अवधि निम्नानुसार है:

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
विषय देशों से आयात					
-चीन	वर्गमीटर	1,20,02,862	46,81,170	52,84,813	1,16,11,633
-जापान	वर्गमीटर	10,44,526	6,36,933	1,38,105	25,889
-दक्षिण कोरिया	वर्गमीटर	5,53,851	8,62,020	11,68,832	50,953
-ताइवान	वर्गमीटर	2,33,646	1,04,602	1,35,967	6,97,228
-वियतनाम	वर्गमीटर	13,733	-	-	-
विषय देशों से कुल आयात	वर्गमीटर	1,38,48,618	62,84,725	67,27,717	1,23,85,703
	अनुक्रमित	100	45	49	89
गैर-विषय देशों से आयात	वर्गमीटर	6,56,716	10,82,464	19,61,069	19,17,453
	अनुक्रमित	100	165	299	292
कुल आयात	वर्गमीटर	1,45,05,334	73,67,190	86,88,785	1,43,03,156
		100	51	60	99

100. यह देखा गया है कि:

- क. आधार वर्ष 2019-20 की तुलना में पीओआई में संबंधित देशों से आयात की मात्रा में गिरावट आई है। वर्ष 2020-21 और 2021-22 में आयात मात्रा में गिरावट कोविड 19 महामारी के कारण है।
- ख. ताइवान से आयात आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में बढ़ा है जबकि चीन जनसंपर्क से आयात में मामूली गिरावट आई है। इसी अवधि के दौरान, अन्य विषय देशों से आयात में गिरावट आई है।
- ग. यद्यपि विषय वस्तुओं की मांग में आधार वर्ष से मामूली गिरावट देखी गई है, गैर-विषयक देशों के अलावा अन्य आयातों में वृद्धि हुई है।
- घ. घरेलू उद्योग के उत्पादन की तुलना में अधीन देशों से आयात ***% से घटकर ***% हो गया है।

ज.3.3 विषयगत देशों से आयात का मूल्य प्रभाव

101. संबंधित देशों से आयातों के मूल्य प्रभाव के संबंध में, यह विश्लेषण किया जाना आवश्यक है कि क्या भारत में ऐसे उत्पादों की कीमत की तुलना में कथित आयातों द्वारा महत्वपूर्ण मूल्य कम कटौती की गई है, या क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को कम करने या मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा सामान्य पाठ्यक्रम में होता। अधीन देशों से आयातों के कारण घरेलू उद्योग के मूल्यों पर पड़ने वाले प्रभाव की मूल्य कम कटिंग, मूल्य में कमी और मूल्य अवसाद, यदि कोई हो, के संदर्भ में जांच की गई है।

क. मूल्य अंडरकटिंग

102. मूल्य कम कटौती का निर्धारण करने के लिए, व्यापार के समान स्तर पर उत्पाद के अवतरित मूल्य और घरेलू उद्योग के औसत बिक्री मूल्य, सभी छूटों और करों के निवल के बीच तुलना की गई है। घरेलू उद्योग की कीमतें एक्स-फैक्ट्री स्तर पर निर्धारित की गई थीं:

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
घरेलू उद्योग का एनएसआर	आईएनआर/वर्गमीटर	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	100	114	133
विषयगत देशों से प्राप्त मूल्य	आईएनआर/वर्गमीटर	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	114	133	141
मूल्य अंडरकटिंग	%	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	(6.07)	(25.86)	46.25
मूल्य अंडरकटिंग	% - श्रेणी	20-40%	ऋणात्मक	ऋणात्मक	40-50

103. यह देखा गया है कि वर्ष 2021-22 को छोड़कर क्षति की अवधि में सकारात्मक कीमत कम हो रही है, जहां थोड़ी नकारात्मक कीमत कम है। यह ध्यान दिया जाता है कि पीओआई में मूल्य अंडरकटिंग वर्ष 2020-21 से पीओआई तक बढ़ गई है।

ख. मूल्य दमन/अवसाद

104. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या आयातों के प्रभाव से मूल्यों में काफी कमी आती है अथवा मूल्य वृद्धि, जो अन्यथा सामान्य स्थिति में होती, को रोका जा सकता है, प्राधिकरण ने क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग (प्रत्यक्ष बिक्री उपरिव्ययों को छोड़कर फैक्ट्री स्तर पर) की लागतों और मूल्यों में परिवर्तनों की जांच की है।

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
बनाने और बेचने की लागत	आईएनआर/वर्गमीटर	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	96	115	142
घरेलू बिक्री मूल्य	आईएनआर/वर्गमीटर	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	100	114	133
लैंडेड प्राइस	आईएनआर/वर्गमीटर	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	114	133	141

105. प्राधिकरण नोट करता है कि घरेलू उद्योग ने आयात से मूल्य दबाव का अनुभव किया। जैसा कि ऊपर दी गई तालिका से स्पष्ट है, घरेलू उद्योग का विक्रय मूल्य बनाने और बेचने की लागत से लगातार कम रहा है। आधार वर्ष की तुलना में पीओआई में बनाने और बेचने की लागत और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर बढ़ गया है।

106. कुछ इच्छुक पार्टियों के इस दावे के संबंध में कि घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्री की लागत लंदन मेटल एक्सचेंज (एलएमई) के अनुसार एल्युमिनियम के मूल्यों में परिवर्तन के अनुरूप नहीं बढ़ी है, घरेलू उद्योग ने यह कहा है कि एलएमई पर उद्धृत मूल्य आधार धातु के मूल्य हैं। लिथोग्राफिक एल्युमिनियम काँयल में रूपांतरण लागत, धातु प्रीमियम, ऊर्जा अधिभार आदि जैसे अतिरिक्त प्रभार शामिल हैं।

1. ज.3.4 घरेलू उद्योग के आर्थिक मानदंड

107. एडी नियमों की आवश्यकता है कि क्षति के निर्धारण में घरेलू उत्पादकों पर आयात किए गए विषय की परिणामी क्षति की एक वस्तुनिष्ठ जांच शामिल होगी। ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में, प्राधिकृत व्यापारी नियमावली में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में बिक्री में वास्तविक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और सूचकांकों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन शामिल होगा। लाभ, आउटपुट, बाजार हिस्सेदारी, उत्पादकता, निवेश पर वापसी या क्षमता का उपयोग; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, नकदी प्रवाह, इन्वेंटरी, रोजगार, मजदूरी, विकास, पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव। तदनुसार, क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के निष्पादन की जांच की गई है।

क. उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री की मात्रा

108. क्षति अवधि के दौरान क्षमता, उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन नीचे दिया गया था -

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
क्षमता	वर्गमीटर	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	100	100	100
उत्पादन	वर्गमीटर	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	68	91	96
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	68	89	93
घरेलू बिक्री	वर्गमीटर	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	73	95	94

109. यह देखा गया है कि:

क. आधार वर्ष 2019-20 की तुलना में पीओआई में पीयूसी के उत्पादन में गिरावट आई है। इसके अलावा, प्राधिकरण नोट करता है कि वर्ष 2020-21 और 2021-22 में उत्पादन की तुलना में पीओआई में पीयूसी का उत्पादन काफी बढ़ गया है।

ख. आधार वर्ष 2019-20 की तुलना में पीओआई में घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में गिरावट आई है। प्राधिकरण नोट करता है कि घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग 100% से अधिक है, हालांकि घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि यह निरंतर प्रक्रिया सुधार और बाधाओं को दूर करके अपने उत्पादन में सुधार करने में सक्षम रहा है।

ग. आधार वर्ष 2019-20 की तुलना में पीओआई में घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री में गिरावट आई है।

ख. बाज़ार हिस्सेदारी

110. आयातों और घरेलू उद्योग के बाज़ार हिस्से की निम्नानुसार जांच की गई है -

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
विषय देशों से आयात	वर्गमीटर	1,38,48,618	62,84,725	67,27,717	1,23,85,703
-चीन	वर्गमीटर	1,20,02,863	46,81,170	52,84,812	1,16,11,632
-जापान	वर्गमीटर	10,44,526	6,36,933	1,38,105	25,889
-दक्षिण कोरिया	वर्गमीटर	5,53,851	8,62,020	11,68,832	50,953
-ताइवान	वर्गमीटर	2,33,646	1,04,602	1,35,967	6,97,228
-वियतनाम	वर्गमीटर	13,733	-	-	-
गैर-विषय देशों से आयात	वर्गमीटर	6,56,716	10,82,464	19,61,069	19,17,453
कुल आयात	वर्गमीटर	1,45,05,334	73,67,190	86,88,785	1,43,03,156
घरेलू उद्योग	वर्गमीटर	***	***	***	***
अन्य उत्पादकों की बिक्री	वर्गमीटर	***	***	***	***
कुल मांग	वर्गमीटर	***	***	***	***
कुल मांग	अनुक्रमित	100	66	86	98
बाज़ार हिस्सेदारी					
विषय देशों से आयात	%	***	***	***	***
	अनुक्रमित	100	69	57	91
-चीन	%	***	***	***	***
	अनुक्रमित	100	59	51	99
-जापान	%	***	***	***	***
	अनुक्रमित	100	93	15	3
-दक्षिण कोरिया	%	***	***	***	***
	अनुक्रमित	100	236	246	9
-ताइवान	%	***	***	***	***
	अनुक्रमित	100	68	68	305
-वियतनाम	%	***	***	***	***
	अनुक्रमित	100	-	-	-
गैर विषय देशों से आयात	%	***	***	***	***
	अनुक्रमित	100	250	348	298
कुल आयात	%	***	***	***	***
	अनुक्रमित	100	77	70	101

	%	***	***	***	***
घरेलू उद्योग	अनुक्रमित	100	110	110	96
	%	***	***	***	***
समर्थक की बिक्री	अनुक्रमित	100	35,043	2,02,335	1,70,881
कुल मांग	%	100%	100%	100%	100%

111. प्राधिकरण नोट करता है कि घरेलू उद्योग ने पिछले वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में अपना बाजार हिस्सा खो दिया है जबकि इसी अवधि के दौरान संबंधित देशों की बाजार हिस्सेदारी ***% से बढ़कर ***% हो गई है।

ग. सूची

112. क्षति की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची स्थिति नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
प्रारंभिक इन्वेंट्री	वर्गमीटर	***	***	***	***
समापन इन्वेंट्री	वर्गमीटर	***	***	***	***
औसत इन्वेंट्री	वर्गमीटर	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	91	55	55

113. यह ध्यान दिया जाता है कि क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की सूची में गिरावट आई है।

घ. लाभप्रदता, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर वापसी

114. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग के नियोजित पूंजी पर लाभ, नकद लाभ और वापसी नीचे दी गई तालिका में दी गई है:

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
ब्याज और कर से पहले लाभ/(हानि) (पीबीआईटी)	आईएनआर लाख में	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	(100)	(146)	(216)	(391)
ब्याज और कर से पहले लाभ/(हानि) (पीबीआईटी)	आईएनआर/वर्गमीटर	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	(100)	(200)	(228)	(417)
नकद लाभ/(घाटा)	आईएनआर	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	(100)	(280)	(597)	(2,010)
नकद लाभ/(घाटा)	आईएनआर/वर्गमीटर	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	(100)	(384)	(632)	(2,142)
नियोजित पूंजी	आईएनआर	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	101	104	129
नियोजित पूंजी पर वापसी	%	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	(100)	(144)	(208)	(302)

115. प्राधिकरण नोट करता है कि घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में और गिरावट आई है। यह ध्यान दिया जाता है कि क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की सूची में गिरावट आई है। आधार वर्ष की तुलना में लाभ, नकद लाभ और पूंजी पर वापसी में और गिरावट आई है। घरेलू उद्योग नियोजित पूंजी पर नकारात्मक प्रतिलाभ के साथ नकद हानि उठा रहा है।

116. विभिन्न इच्छुक पक्षों के इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग के प्रदर्शन पर कर्तव्यों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, प्राधिकरण नोट करता है कि घरेलू उद्योग लागत में वृद्धि के अनुरूप अपनी कीमतों में वृद्धि करने में सक्षम नहीं रहा है।

ड. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

117. प्राधिकरण ने रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता से संबंधित सूचना की जांच की है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
प्रति दिन उत्पादकता	वर्गमीटर/दिन	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	68	89	93
प्रयोग	संख्या	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	101	102	98
वेतन	आईएनआर लाख में	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	83	105	114

118. यह ध्यान दिया जाता है कि क्षति की अवधि में कर्मचारियों की संख्या स्थिर रही है। क्षति की अवधि में प्रति दिन उत्पादकता में गिरावट आई है, हालांकि, जांच की अवधि में मजदूरी में वृद्धि हुई है।

2. ज.3.5 पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

119. प्राधिकरण नोट करता है कि घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में इसके पीयूसी व्यवसाय के संबंध में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग को नुकसान हुआ और साथ ही नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में नकारात्मक गिरावट दर्ज की गई। इस प्रकार, आयातों ने घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

झ. क्षति के मार्जिन की मात्रा

120. विचाराधीन उत्पाद का गैर-हानिकारक मूल्य जांच की अवधि के लिए उत्पादन लागत से संबंधित सत्यापित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर निर्धारित किया गया है। क्षति माजन की गणना करने के लिए संबंधित देशों से अवतरण मूल्य की तुलना करने के लिए गैर-हानिकारक मूल्य पर विचार किया गया है। गैर-हानिकारक मूल्य निर्धारित करने के लिए, घरेलू उद्योग द्वारा क्षति की अवधि में कच्चे माल के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। उपयोगिताओं के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया गया है। क्षति की अवधि में उत्पादन क्षमता का सबसे अच्छा उपयोग करने पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादन लागत के लिए कोई असाधारण या गैर-आवर्ती खर्च नहीं लिया जाता है। विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (यानी औसत शुद्ध अचल संपत्ति और औसत कार्यशील पूंजी) पर एक उचित रिटर्न (पूर्व-कर @ 22%) को गैर-हानिकारक मूल्य पर पहुंचने के लिए पूर्व-कर लाभ के रूप में अनुमति दी गई थी।

121. कुछ इच्छुक पार्टियों ने उत्पादन लागत और गैर-हानिकारक मूल्य तथा घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई क्षति के निर्धारण के लिए अपनाई गई आबंटन पद्धतियों की जांच करने का तर्क दिया है। इस संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि इसने घरेलू उद्योग द्वारा किए गए क्षति के दावों के साथ-साथ गैर-हानिकारक मूल्य की गणना करते समय लागत के आबंटन सहित घरेलू उद्योग के रिकार्डों की जांच और सत्यापन किया है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। पीयूसी को गैर-पीयूसी उत्पादों की ढांचागत लागत के आबंटन पर चिंताओं के संबंध में, प्राधिकरण ने किए गए आबंटनों की जांच की है और एनआईपी की गणना के लिए उचित रूप से लागत की

अनुमति दी है। प्राधिकरण ने गैर-हानिकारक मूल्य की गणना के लिए अनुलग्नक-III में निर्धारित सिद्धांतों का पालन किया है जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

122. संबंधित देशों के सहकारी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए लैंडेड मूल्य उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर निर्धारित किया गया है। प्राधिकरण ने संबंधित देशों के सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अवतरण मूल्य निर्धारित किया है।
123. कुछ इच्छुक पार्टियों ने यह दावा किया कि भू-अवतरण मूल्य की गणना के प्रयोजन से हैंडलिंग, लोडिंग, अनलोडिंग प्रभारों पर विचार किया जाना चाहिए। प्राधिकरण ने संबंधित माल के कर निर्धारण योग्य मूल्य के आधार पर अवतरण मूल्य की गणना की है जो प्राधिकरण द्वारा अपनाई जा रही सतत प्रक्रिया के अनुरूप है। प्राधिकरण द्वारा यथा परिकलित उतराई तक की कीमत नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है।
124. प्राधिकरण द्वारा निर्धारित पीसीएन के लिए ऊपर के अनुसार निर्धारित अवतरित मूल्य और गैर-हानिकारक मूल्य के आधार पर, उत्पादकों/निर्यातकों के लिए भारित औसत क्षति माजन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया गया है और इसे नीचे तालिका में दिया गया है:

क्षति मार्जिन तालिका

क्र.सं.	निर्माता	एनआईपी	लैंडेड प्राइस	क्षति मार्जिन	क्षति मार्जिन	श्रेणी
		अमरीकी डालर/वर्ग मीटर	अमरीकी डालर/वर्ग मीटर	अमरीकी डालर/वर्ग मीटर	%	%
1	चीन जन. गण.					
क	लकी हुआगुआंग ग्राफिक्स कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	30-40
ख	कोडक चीन ग्राफिक संचार कं, लिमिटेड	***	***	***	***	ऋणात्मक
ग	फुजीफिल्म प्रिंटिंग प्लेट (चीन) कं, लिमिटेड	***	***	***	***	0-10
घ	अनहुइ स्ट्रांग स्टेट न्यू मटेरियल्स कं, लिमिटेड	***	***	***	***	10-20
ड	हुआंगशान जिन रुइताई प्रौद्योगिकी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	20-30
च	चोंगकिंग हुआफेंग डि जेट प्रिंटिंग मटेरियल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	30-40
छ	कोई अन्य	***	***	***	***	30-40
2	कोरिया गण. जन.	***	***	***	***	
क.	जेइल सी एंड पी कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***	20-30
ख.	कोई अन्य	***	***	***	***	20-30
3	जापान	***	***	***	***	
क.	फुजीफिल्म कॉर्पोरेशन	***	***	***	***	10-20
ख.	कोई अन्य	***	***	***	***	20-30
4	ताइवान	***	***	***	***	

क.	सभी	***	***	***	***	30-40
5	वियतनाम	***	***	***	***	
क.	सभी	***	***	***	***	30-40

3.

4. **अ. कारण लिंक और गैर-एट्रिब्यूशन विश्लेषण**5. **अ.1 अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए प्रस्तुतियाँ**

125. विभिन्न इच्छुक पार्टियों ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

- क. घरेलू उद्योग को हुई क्षति आंतरिक प्रतिस्पर्धा के कारण हुई है।
- ख. एक नए निर्माता, एचएल प्रिंटिच सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2020-21 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया।
- ग. एचएल प्रिंटिच सॉल्यूशंस प्रा. लिमिटेड वित्त वर्ष 2020-21 में अपने उत्पादन को 100 सूचकांक अंक से बढ़ाकर जांच अवधि के दौरान 431 सूचकांक अंक कर दिया, जो लगभग 3.3 गुना की वृद्धि है।
- घ. अन्य उत्पादकों की घरेलू बिक्री आधार वर्ष में 100 सूचकांक अंक से बढ़कर पीओआई के दौरान 167,345 सूचकांक अंक हो गई।
- ङ. आवेदक को जो क्षति लगी है, वह अन्य घरेलू उत्पादकों, विशेष रूप से नए प्रवेशी, एचएल प्रिंटिच सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की मूल्य निर्धारण रणनीतियों के कारण है।
- च. आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान आवेदक के पीयूसी की निर्यात बिक्री में लगभग 22% की गिरावट आई, जिससे प्रति यूनिट निश्चित लागत बढ़ गई। निर्यात बिक्री में इस गिरावट के कारण आवेदक को कोई क्षति पहुंची है।
- छ. आवेदक ने दिसंबर 2012 से लगभग 11.5 वर्षों तक शुल्क सुरक्षा का आनंद लिया है। क्षति, यदि कोई हो, आवेदक द्वारा कुप्रबंधन और खराब व्यावसायिक निर्णयों के कारण है।
- ज. उत्तरदाताओं का अनुरोध है कि प्राधिकरण आवेदक को हुई किसी भी क्षति को चीन जन. गण. और जापान से आयात के लिए जिम्मेदार न ठहराए, क्योंकि अन्य कारक अनुभव किए गए किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार हैं।
- झ. घरेलू उद्योग ने मौखिक सुनवाई के दौरान दावा किया कि वह विचाराधीन उत्पाद का प्रमुख उत्पादक और निर्यातक है और निर्यात बाजारों में कीमत प्रतिस्पर्धी है।
- ञ. यह भारत में घरेलू उद्योग के प्रदर्शन के बारे में चिंता पैदा करता है, जहां यह निर्यात बाजारों में मूल्य प्रतिस्पर्धी होने के साथ-साथ डंप किए गए आयात के कारण क्षति का दावा करता है।
- ट. घरेलू उद्योग को इस पर ध्यान देना चाहिए कि वह निर्यात बाजारों में प्रतिस्पर्धी क्यों है लेकिन अपने घरेलू बाजार में संघर्ष कर रहा है।
- ठ. चीनी पाटन और बड़ी उत्पादन क्षमता के घरेलू उद्योग के दावे घरेलू स्तर पर क्षति का दावा करते हुए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता पर सवाल उठाते हैं।
- ड. घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना क्षति की अवधि के दौरान निर्यात की मात्रा में गिरावट दर्शाती है।
- ढ. घरेलू बिक्री कीमतों और निर्यात बिक्री कीमतों में रुझान क्षति की अवधि के दौरान समान रहे हैं।
- ण. क्षति, यदि कोई हो, आंतरिक प्रतिस्पर्धा के कारण है, विशेष रूप से एक नए निर्माता, एचएल प्रिंटिच सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से, जिसका उत्पादन पीओआई के दौरान 3.3 गुना बढ़ गया। नई घरेलू उत्पादक की मर्मज्ञ मूल्य निर्धारण नीति आवेदक को किसी भी क्षति का वास्तविक कारण है।

- त. याचिकाकर्ता ने जानबूझकर अन्य बाहरी कारकों की अनदेखी की है जो इसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे कि रूस-यूक्रेन युद्ध।

6. ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण

126. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

- क. सूर्यास्त की समीक्षा में, अधिकारियों को यह निर्धारित करना होगा कि क्या पाटन रोधी कर्तव्यों को हटाने से पाटन जारी रहेगी या फिर से शुरू हो जाएगी और घरेलू उद्योग को नुकसान होगा। पाटन और क्षति के बीच कारण लिंक को फिर से स्थापित करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि सूर्यास्त की समीक्षा पाटन और क्षति की निरंतरता या पुनरावृत्ति की संभावना पर ध्यान केंद्रित करती है।
 - ख. मेक्सिको मामले से अमेरिका-ओसीटीजी में डब्ल्यूटीओ के फैसले और भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मामलों (ऋषिरूप पॉलिमर्स और यूनियन ऑफ इंडिया बनाम कुम्हो पेट्रोकेमिकल्स) सहित कई फैसले इस बात की पुष्टि करते हैं कि सूर्यास्त समीक्षा केवल यह आकलन करती है कि क्या पाटन रोधी शुल्क वापस लेने से पाटन और क्षति फिर से शुरू हो जाएगी, न कि पाटन नए सिरे से मौजूद है या नहीं।
 - ग. मौजूदा उपायों के बावजूद, घरेलू उद्योग लगातार पाटन से क्षति के महत्वपूर्ण जोखिम में बना हुआ है। ऐतिहासिक पैटर्न से संकेत मिलता है कि कर्तव्यों को हटाने से पाटन में तेजी आएगी और आगे नुकसान होगा।
 - घ. यह दावा गलत है कि टेकनोवा अप्रचलित बुनियादी ढांचे से पीयूसी के उत्पादन की लागत को जिम्मेदार ठहरा रही है। केवल पीयूसी उत्पादन से सीधे जुड़ी लागतों की सूचना दी जाती है।
 - ङ. तर्क है कि नए निर्माता, जैसे कि एचएल प्रिंटक, घरेलू उद्योग के लिए प्रतिस्पर्धा पैदा कर रहे हैं, खारिज कर दिए गए हैं। एचएल प्रिंटक की बाजार हिस्सेदारी न्यूनतम है और घरेलू उद्योग के प्रदर्शन पर इसका कोई प्रभाव नहीं है।
 - च. यह दावा कि निर्यात घाटे के कारण घरेलू उद्योग घायल हुआ है, अप्रासंगिक है, क्योंकि क्षति का विश्लेषण विशेष रूप से घरेलू बिक्री से संबंधित है। टेकनोवा की निर्यात बिक्री उसके कुल कारोबार के एक छोटे हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है और इसका वित्तीय प्रदर्शन पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है।
 - छ. जबकि महामारी के दौरान मांग में गिरावट आई थी, अधीन देशों से आयात में कमी के कारण घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में थोड़ा सुधार हुआ। हालांकि, जैसे ही स्थितियाँ सामान्य हुईं, डंप किए गए आयात फिर से बढ़ गए, जिससे पीओआई के दौरान बिक्री में गिरावट आई।
 - ज. कुप्रबंधन या खराब व्यावसायिक निर्णयों के कारण क्षति के दावे साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं हैं। घरेलू उद्योग ने प्रतिस्पर्धात्मकता बनाए रखने के लिए लगातार विवेकपूर्ण निर्णय लिए हैं और इस क्षति के लिए प्रत्यक्ष रूप से तीव्र पाटन जिम्मेदार है।
- झ. संघर्ष ने आपूर्ति शृंखलाओं को बाधित किया है और विश्व स्तर पर लागत में वृद्धि की है, लेकिन इसने जांच में सभी पक्षों को समान रूप से प्रभावित किया है। संघर्ष ने पाटन पैटर्न को प्रभावित नहीं किया, क्योंकि आयात की कीमतें उत्पादन लागत के समान दर से नहीं बढ़ीं, यह दर्शाता है कि भू-राजनीतिक मुद्दों की परवाह किए बिना पाटन जारी रही।

7. ज.3 प्राधिकरण द्वारा समीक्षा

127. इन नियमों के अनुसार, प्राधिकरण को, अन्य बातों के साथ-साथ, पाटित आयातों के अलावा किन्हीं ज्ञात कारकों, जिनसे घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा है, की जांच करनी होती है ताकि इन अन्य कारकों द्वारा हुई क्षति को पाटित आयातों के कारण न माना जा सके। जबकि वर्तमान समीक्षा एक सनसेट समीक्षा है और मूल जांच में कारण लिंक की पहले ही जांच की जा चुकी है, प्राधिकरण ने जांच की कि क्या अन्य ज्ञात सूचीबद्ध कारकों के कारण घरेलू उद्योग को नुकसान हुआ है या होने की संभावना है। विशेष रूप से, प्राधिकरण ने यह भी जांच की है कि क्या शुल्कों को हटाने से घरेलू उद्योग को क्षति की निरंतरता/पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

128. तीसरे देशों से आयात की मात्रा और मूल्य: प्राधिकरण नोट करता है कि अधीन देशों के अलावा अन्य देशों से आयात नगण्य हैं। इसलिए घरेलू उद्योग को लगी क्षति का कारण तीसरे देशों से आयात नहीं हो सकता।
129. मांग और खपत के पैटर्न में संकुचन: प्राधिकरण नोट करता है कि संबंधित वस्तुओं की मांग मामूली गिरावट के साथ स्थिर रही है। अतः विषयगत वस्तुओं की मांग में कमी से आयात घरेलू उद्योग को क्षति का कारण नहीं हो सकता। इसके अलावा, प्राधिकरण नोट करता है कि विचाराधीन उत्पाद की खपत के पैटर्न में कोई भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ है, जिसके लिए घरेलू उद्योग को हुई क्षति को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
130. प्रतिस्पर्धा की शर्तें और व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं: कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथा या प्रतिस्पर्धा की शर्तें नहीं हैं जो घरेलू उद्योग को प्रभावित कर सकती हैं। घरेलू उत्पादकों के बीच पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि घरेलू उद्योग सहित घरेलू उत्पादक विषय देशों से आयातों से प्रतिस्पर्धा का सामना करते हैं।
131. प्रौद्योगिकी का विकास: किसी भी इच्छुक पक्ष ने प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण बदलावों को प्रदर्शित करने के लिए कोई सबूत प्रस्तुत नहीं किया है जो घरेलू उद्योग को नुकसान पहुंचा सकता था।
132. कंपनी के अन्य उत्पादों का निष्पादन: प्राधिकरण नोट करता है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों का प्रदर्शन घरेलू उद्योग को नुकसान का संभावित कारण प्रतीत नहीं होता है। किसी भी घटना में, प्राधिकरण ने केवल क्षति के आकलन के उद्देश्य से पीयूसी के प्रदर्शन पर विचार किया है।
133. निर्यात निष्पादन: प्राधिकरण ने घरेलू उद्योग के क्षति विश्लेषण के लिए केवल घरेलू परिचालनों के प्रदर्शन पर विचार किया है। इसके अलावा, प्राधिकरण नोट करता है कि घरेलू उद्योग के निर्यात बहुत सीमित हैं, इसलिए, रूस-यूक्रेन वेयर जैसे बाहरी कारण घरेलू उद्योग को नुकसान का कारण नहीं हो सकते हैं।
134. घरेलू उद्योग द्वारा मूल्य निर्धारण रणनीति और अन्य प्रबंधन निर्णय: प्राधिकरण नोट करता है कि इच्छुक पार्टियों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने खराब मूल्य निर्धारण रणनीतियों को अपनाया है जिसके परिणामस्वरूप लाभप्रदता का नुकसान हुआ है। इस संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि घरेलू उद्योग डंप किए गए आयातों के दबाव में जूझ रहा है जो घरेलू उद्योग की कीमतों को दबा रहे हैं। पाटित किए गए आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच एक कारणात्मक संबंध है।

8. ट. पाटन और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना

9. ट.1 अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए प्रस्तुतियाँ

135. विभिन्न इच्छुक पार्टियों ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

- क. फेडरेशन का तर्क है कि यदि शुल्क वापस ले लिया जाता है तो क्षति की पुनरावृत्ति की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि वर्तमान पाटन रोधी शुल्क (एडीडी) शासन के तहत टेक्रोवा के भौतिक और वित्तीय प्रदर्शन में काफी सुधार हुआ है।
- ख. क्षति की संभावना के बारे में आवेदक के दावे निराधार हैं, क्योंकि वे त्रुटिपूर्ण तर्क पर भरोसा करते हैं। निर्यातक देशों में अतिरिक्त क्षमताओं का मात्र अस्तित्व वैश्विक मांग-आपूर्ति गतिशीलता पर विचार किए बिना क्षति की पुनरावृत्ति को स्वचालित रूप से उचित नहीं ठहराता है।
- ग. आवेदक का यह दावा कि भारतीय बाजार आकर्षक मूल्य है, कम आयात कीमतों के उसके दावे के विपरीत है। मांग-आपूर्ति के अंतर वाले बाजार में, विदेशी विक्रेता तार्किक रूप से प्रीमियम चार्ज करेंगे। इसके अतिरिक्त, आवेदक ने अपने क्षति के दावों का समर्थन करने के लिए इन्वेंट्री और मूल्य परिदृश्यों पर पर्याप्त डेटा प्रदान नहीं किया है।
- घ. अकेले क्षति और पाटन का अस्तित्व स्वचालित रूप से निरंतर या आवर्तक क्षति की संभावना का संकेत नहीं देता है। यह दिखाया जाना चाहिए कि क्षति आयात के कारण होती है। यदि क्षति अन्य कारकों से उपजी है, तो आयात से निरंतर क्षति के दावे को कायम नहीं रखा जा सकता है।

ड. हालांकि क्षति की संभावना को प्रमाणित करने के लिए कोई सख्त प्रारूप नहीं है, प्राधिकरण द्वारा पिछले मामलों में कुछ मापदंडों पर विचार किया गया है, जैसा कि 12 दिसंबर, 2017 को व्यापार सूचना संख्या 4/5/2017-डीजीएडी में उल्लिखित है। इन मापदंडों में शामिल हैं:

- पीओआई के दौरान और तीन साल पहले विषय देशों में विचाराधीन उत्पाद की कुल और अधिशेष क्षमता
- उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा भारत के अलावा अन्य देशों को किए जाने वाले निर्यात की मात्रा और कीमतें
- विषय देशों में उत्पादकों/निर्यातकों का निर्यात उन्मुखीकरण
- पाटन रोधी शुल्क वापस लेने के बाद निर्यात के लिए भारतीय बाजार को क्यों लक्षित किया जाएगा, इसका औचित्य

च. याचिकाकर्ता ने इन प्रमुख मापदंडों पर जानकारी नहीं दी है। इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि एडीडी को हटाने के बाद भारतीय बाजार निर्यात के लिए पसंदीदा गंतव्य क्यों होगा, न ही भारतीय बाजार के आकर्षण की पुष्टि की गई है।

छ. अमेरिका में अपीलीय निकाय - संक्षारण प्रतिरोधी स्टील सनसेट रिव्यू ने कहा कि सकारात्मक साक्ष्य के बिना अनुमानों का उपयोग करना ठोस साक्ष्य के आधार पर निर्धारण करने के दायित्व के साथ असंगत हो सकता है। इस प्रकार, निरंतर या आवर्तक पाटन की संभावना का ठीक से आकलन करने के लिए एक दृढ़ साक्ष्य नींव की आवश्यकता होती है।

ज. घरेलू उद्योग का दावा है कि संबंधित देशों, विशेष रूप से चीन में उत्पादकों के पास महत्वपूर्ण अतिरिक्त क्षमता है। तथापि, केवल अधिशेष क्षमता से ही पाटन अथवा क्षति की संभावना सिद्ध नहीं होती है। यह प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि इस क्षमता को भारतीय बाजार में कैसे निर्देशित किया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान से एनिलिन जैसे पिछले मामलों ने दिखाया है कि अधिशेष क्षमता आगे औचित्य के बिना संभावना साबित करने के लिए अपर्याप्त है।

झ. याचिकाकर्ता ब्राजील, दक्षिण कोरिया, चीनी ताइपे और यूरोपीय संघ सहित अन्य देशों द्वारा चीन पर लगाए गए पाटन रोधी कर्तव्यों का संदर्भ देता है। हालांकि, अन्य देशों द्वारा शुल्क लगाने का स्वतः यह अर्थ नहीं है कि उत्पाद को भारतीय बाजार में भेज दिया जाएगा।

ञ. घरेलू उद्योग अपनी निरंतर क्षति के लिए आयात को जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन शुल्क लगाने के बावजूद इसका प्रदर्शन खराब हुआ है। यह इंगित करता है कि क्षति अन्य कारकों के कारण होने की संभावना है, आयात नहीं, जैसा कि पिछले सबमिशन में विस्तृत है।

ट. कंपनियों ने चीन में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के दावों को खारिज कर दिया, उच्च क्षमता उपयोग का प्रमाण प्रदान किया। उन्होंने तर्क दिया कि क्षमता का अस्तित्व मात्र भारतीय बाजार के लिए एक आसन्न खतरे के बराबर नहीं है।

10. ट.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण

136. विभिन्न इच्छुक पार्टियों ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

- क. संबद्ध देशों से पीयूसी का आयात लगातार डंप किया जा रहा है। यह तथ्य कि आयात लगातार पाटित किया जा रहा है और घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहा है, डंपिंग और क्षति के जारी रहने की संभावना को स्थापित करने के लिए पर्याप्त है।
- ख. पाटित किए गए आयात संबंधित देशों से महत्वपूर्ण मात्रा में आते रहते हैं। यदि शुल्क वापस ले लिया जाता है, तो संबंधित देशों से लगातार डंप किए गए आयात की प्रबल संभावना है।
- ग. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद घरेलू उद्योग को मूल्य और मात्रा संबंधी क्षति का सामना करना पड़ रहा है।

- घ. पिछले चार वर्षों में वित्तीय और आर्थिक प्रदर्शन में काफी गिरावट आई है।
- ङ. घरेलू उद्योग कम कीमतों पर उत्पाद बेचने के लिए मजबूर है, जिससे लाभप्रदता काफी प्रभावित होती है।
- च. पाटनरोधी शुल्कों के बावजूद निरंतर लाभप्रदता बनाए नहीं रखी गई है।
- छ. नियोजित पूंजी पर रिटर्न (आरओसीई) नकारात्मक है और 22% की बेंचमार्क दर से बहुत कम है।
- ज. सकारात्मक मूल्य अंडरकटिंग, मूल्य अंडरसेलिंग, मूल्य अवसाद और मूल्य दमन है, जैसा कि याचिका के भाग VI में विस्तृत है।
- झ. झूठी वापस लेने पर क्षति जारी रहने और खराब होने की आशंका है।
- ञ. 2018 में, प्राधिकरण ने चीन जन. गण. के खिलाफ कर्तव्यों को जारी रखने की सिफारिश नहीं की, जिससे कम समय में घरेलू उद्योग को नुकसान में काफी वृद्धि हुई।
- ट. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के उत्पादन के लिए चीन जन. गण. में पर्याप्त अतिरिक्त और निष्क्रिय क्षमताएं मौजूद हैं।
- ठ. चीन जन. गण. की स्थापित क्षमता 1025 मिलियन वर्गमीटर से अधिक है, जबकि घरेलू मांग केवल 180-200 मिलियन वर्गमीटर अनुमानित है।
- ड. लगभग 825 मिलियन वर्गमीटर की अतिरिक्त क्षमता निर्यात बाजारों की ओर निर्देशित है।
- ढ. विषय वस्तुओं के लिए भारत का बाजार आकार लगभग 45 मिलियन वर्गमीटर वार्षिक है।
- ण. चीन जन. गण. में अतिरिक्त क्षमता भारत की कुल घरेलू मांग से लगभग 20 गुना अधिक है।
- त. यदि शुल्क वापस ले लिया जाता है, तो चीन जन. गण. की अतिरिक्त क्षमता का उपयोग भारत में निर्यात बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।
- थ. राज्य के हस्तक्षेप के कारण चीन का एल्यूमीनियम बाजार विकृत है, जैसा कि 2019 और 2024 की ओईसीडी रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है।
- द. चीन ने निरंतर राज्य समर्थन के माध्यम से उच्च इनपुट लागत और कम एल्यूमीनियम कीमतों का प्रबंधन किया है।
- ध. चीन की टैरिफ संरचना डाउनस्ट्रीम एल्यूमीनियम गतिविधियों का समर्थन करती है, जिसमें उच्च निर्यात शुल्क और प्राथमिक एल्यूमीनियम निर्यात पर अपूर्ण वैट छूट होती है।
- न. चीन एल्यूमीनियम निर्माताओं और पीयूसी उत्पादकों को तरजीही ऋण, कर प्रोत्साहन और सब्सिडी वाली ऊर्जा की कीमतें प्रदान करता है।
- प. यह उत्पादन लागत को कम करता है और वैश्विक बाजार में एल्यूमीनियम की अधिकता की ओर जाता है, जिससे अन्य देशों के उत्पादक प्रभावित होते हैं।
- फ. इन बाजार विकृतियों ने घरेलू उद्योग के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा की हैं।
- ब. चीन जन. गण. में लगातार राज्य हस्तक्षेप और बाजार विकृतियों से घरेलू उद्योग को निरंतर पाटन और क्षति की संभावना बढ़ जाती है।
- भ. चीनी निर्यातक व्यापार कदाचार में संलग्न हैं, जैसे कि ट्रांसशिपमेंट और मूल की झूठी घोषणाएं (उदाहरण के लिए, चीन जन. गण. के बजाय श्रीलंका या स्पेन के रूप में मूल की घोषणा)।
- म. ये कदाचारों भारतीय बाजार में पाटित उत्पादों की भरमार कर देते हैं जिससे घरेलू उद्योग कमजोर होता है।
- य. विषयगत वस्तुओं के आयातों का मूल्य घरेलू मूल्यों की तुलना में काफी कम है।
- कक. अन्य देशों में बढ़ती मांग और पाटनरोधी उपायों से भारत संबद्ध देशों के निर्यातकों के लिए एक आकर्षक बाजार बन गया है।

- खख. ब्राजील, दक्षिण कोरिया, ताइवान, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ सहित विभिन्न न्यायालयों ने चीन जन. गण. से डिजिटल प्लेटों पर पाटन रोधी शुल्क लगाया है, जो चीन की पाटन प्रथाओं की वैश्विक मान्यता को उजागर करता है और कर्तव्यों को वापस लेने पर भारत को पुनर्निर्देशित अतिरिक्त उत्पादन की संभावना को बढ़ाता है।
- गग. पाटन रोधी शुल्क के अभाव में आयात और पाटन में वृद्धि होने की संभावना है।
- घघ. ब्राजील, दक्षिण कोरिया, ताइवान, अमेरिका और यूरोपीय संघ में पाटन रोधी उपायों से भारत में चीनी पाटन का खतरा बढ़ जाता है।
- ङङ. पाटन रोधी कर्तव्यों के बिना, भारत अनुचित कीमतों पर डंप किए गए डिजिटल प्लेटों के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बन जाएगा, जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर रूप से नुकसान होगा।
- चच. व्यापार नोटिस जांच के लिए दिशानिर्देश के रूप में काम करते हैं लेकिन कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं। विशेष रूप से निरंतर या आवर्ती पाटन और क्षति की संभावना स्थापित करने के मामलों में, घरेलू उद्योग के पास गोपनीय जानकारी तक पहुंच नहीं हो सकती है, जैसे कि विदेशी उत्पादकों की अधिशेष क्षमता। लक्ष्य घरेलू उद्योग के लिए यह विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण प्रदान करना है कि शुल्क समाप्त होने पर निरंतर/आवर्ती पाटन का एक आसन्न खतरा है।
- छछ. घरेलू उद्योग ने सबूत दिया कि पीयूसी के लिए चीन की कुल स्थापित क्षमता 1025 मिलियन वर्गमीटर से अधिक है, घरेलू मांग केवल 180-200 मिलियन वर्गमीटर है, जिससे निर्यात बाजारों के लिए समर्पित लगभग 825 मिलियन वर्गमीटर से अधिक है। इसके विपरीत, भारत का बाजार आकार केवल 45 मिलियन वर्गमीटर सालाना है, जिससे चीन की अतिरिक्त क्षमता भारत की कुल मांग का लगभग 20 गुना है।
- जज. हालांकि पीयूसी में एक समर्पित एचएस टैरिफ कोड का अभाव है, जिससे तीसरे देश के निर्यात डेटा प्रदान करना मुश्किल हो जाता है, घरेलू उद्योग ने स्थापित किया कि विषय देश निर्यात-उन्मुख हैं और विश्व स्तर पर अनुचित प्रथाओं को अपनाते हैं। ब्राजील, ताइवान, कोरिया गण. जन. और अमेरिका जैसे देशों ने चीन से डीओपीपी आयात पर शुल्क लगाया है।
- झझ. घरेलू उद्योग ने दिखाया है कि यदि पाटन रोधी शुल्क हटा दिए जाते हैं, तो भारत चीन से कम कीमत वाली, डंप की गई डिजिटल प्लेटों के लिए एक प्रमुख लक्ष्य होगा, क्योंकि अन्य क्षेत्राधिकार चीनी उत्पादकों के लिए अव्यवहार्य हो जाते हैं।
- ञञ. जेडल ने स्वीकार किया कि संयंत्र बंद होने के कारण क्षति की अवधि के दौरान इसका निर्यात न्यूनतम था। हालांकि नई क्षमताओं के साथ जेआईएल भारत को निर्यात बढ़ा सकती है बशर्ते पाटन रोधी शुल्क हटा दिया जाए।
- टट. घरेलू उद्योग का तर्क है कि यदि पाटन रोधी शुल्क वापस ले लिया जाता है, तो भारत चीनी आयात के लिए पाटन ग्राउंड बनने का जोखिम उठाता है, विशेष रूप से पर्याप्त पाटन और क्षति मार्जिन को देखते हुए जो मौजूदा कर्तव्यों के बावजूद बना हुआ है।
- ठठ. चीन का सरकारी समर्थित एल्युमीनियम बाजार अपने उत्पादकों को अनुचित लाभ देता है और उन्हें भारत सहित वैश्विक प्रतिस्पर्धियों को कमजोर करने की अनुमति देता है। ब्राजील, दक्षिण कोरिया और अमेरिका जैसे अन्य देशों ने इस खतरे से निपटने के लिए चीनी निर्यात के खिलाफ पाटन रोधी उपाय किए हैं।
- डड. पाटन रोधी सुरक्षा के बिना, भारत डंप किए गए आयात में वृद्धि की चपेट में आ जाएगा, घरेलू उद्योग को पहले से ही नुकसान उठाना पड़ रहा है और सस्ते, निम्न-गुणवत्ता वाले आयात के साथ बाजार को अस्थिर कर रहा है।
- ढढ. किसी भी इच्छुक पक्ष ने निरंतर या आवर्ती पाटन और क्षति की संभावना के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत तथ्यों पर विवाद नहीं किया है।

11. ट.3 प्राधिकरण द्वारा समीक्षा

137.वर्तमान समीक्षा चीन जन. गण., कोरियाई गण. जन., जापान, ताइवान और वियतनाम से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर लगाए गए पाटन रोधी शुल्क की एक सनसेट समीक्षा है। एडी नियमों के तहत, प्राधिकरण को यह निर्धारित करना होता है कि क्या मौजूदा शुल्क की समाप्ति से घरेलू उद्योग को पाटन जारी रहने या फिर से होने और क्षति लगने की संभावना है।

138.प्राधिकरण ने धारा 9क (5), नियम 23 के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं और नियम नियमावली के अनुबंध-II (vii) के संदर्भ में भौतिक क्षति के खतरे से संबंधित मानदंडों और इच्छुक पार्टियों द्वारा रिकार्ड में लाए गए अन्य संगत कारकों पर विचार करते हुए क्षति के जारी रहने अथवा पुनरावृत्ति की संभावना की जांच की है।

139.इस तरह के संभावना विश्लेषण का संचालन करने के लिए कोई विशिष्ट तरीके उपलब्ध नहीं हैं। हालांकि, नियमों के अनुलग्नक II के खंड (vii) में, अन्य बातों के साथ-साथ, उन कारकों के लिए प्रावधान है, जिन पर विचार किया जाना आवश्यक है, अर्थात्,

- क. भारत में पाटित आयातों की वृद्धि की महत्वपूर्ण दर पर्याप्त रूप से बढ़े हुए आयात की संभावना को दर्शाती है।
- ख. निर्यातक की क्षमता में पर्याप्त स्वतंत्र रूप से प्रयोज्य अथवा आसन्न पर्याप्त वृद्धि होनी चाहिए जो किसी अतिरिक्त निर्यात को समाहित करने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजारों में पाटित निर्यातों में पर्याप्त वृद्धि की संभावना का संकेत देती है।
- ग. क्या आयात उन कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर महत्वपूर्ण निराशाजनक या दबाने वाला प्रभाव पड़ेगा और आगे आयात की मांग में वृद्धि होगी; और
- घ. वस्तु की सूची की जांच की जा रही है

140.प्राधिकरण ने, अन्य बातों के साथ-साथ, उपर्युक्त अपेक्षाओं और निम्नलिखित अनुच्छेद मीटरों पर विचार किया है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में पाटन की पुनरावृत्ति होने की संभावना है और यदि हां, तो क्या इससे घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण ने घरेलू उद्योग और अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई सभी संगत सूचना की जांच की है।

पाटित आयात में वृद्धि की महत्वपूर्ण दर

141.प्राधिकरण नोट करता है कि जबकि पीयूसी का समग्र आयात स्थिर रहा है, वर्ष 2020-21 और 2021-22 में किए गए आयात की तुलना में पीओआई में विषय देशों से आयात में काफी वृद्धि हुई है। विषय देशों से आयात नीचे दी गई तालिका में दिए गए हैं:

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
विषय देश	वर्गमीटर	1,38,48,619	62,84,725	67,27,716	1,23,85,702
	अनुक्रमित	100	45	49	89

142.प्राधिकरण ने नोट किया है कि 30 जनवरी, 2020 से पाटन रोधी शुल्क प्रभावी थे, जो वर्ष 2019-20 के अधिकांश समय के लिए लागू नहीं थे। प्राधिकरण ने नोट किया है कि पाटन रोधी शुल्क लगाए जाने के बाद भी आयात में उल्लेखनीय वृद्धि जारी है। नतीजतन, यदि इन शुल्कों को समाप्त होने दिया जाता है, तो संबंधित देशों से आयात में वृद्धि की काफी संभावना है।

निरंतर और मौजूदा पाटन और क्षति

143.प्राधिकारी ने नोट किया है कि जांच की वर्तमान अवधि में विचाराधीन उत्पाद का आयात पाटन रोधी शुल्क के बावजूद डंप की गई कीमतों पर किया गया है। यह भी नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर रिटर्न के संबंध में काफी गिरावट आई है। यह भी देखा गया है कि संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को कम कर रहे हैं।

अधिशेष और डिस्पोजेबल क्षमता

144. इच्छुक पार्टियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर, प्राधिकरण नोट करता है कि विषय देशों (विशेष रूप से चीन जन. गण. से) में पीयूसी का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त और निष्क्रिय क्षमताएं हैं। घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि चीन जनगण में कुल स्थापित क्षमता 1025 मिलियन वर्गमीटर से अधिक है, जबकि देश में कुल मांग केवल 180-200 मिलियन वर्गमीटर होने का अनुमान है। लगभग 825 मिलियन वर्गमीटर की अतिरिक्त क्षमता निर्यात बाजारों के लिए समर्पित है। अतिरिक्त क्षमता भारतीय मांग का लगभग 20 गुना है। प्राधिकरण नोट करता है कि किसी भी इच्छुक पक्ष ने घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावों के विपरीत कोई जानकारी या सबूत नहीं दिया है।

145. इसके अलावा, संबंधित देशों के निर्यातकों द्वारा दायर प्रश्नावली प्रतिक्रिया का विश्लेषण निम्नानुसार दिखाता है:

विवरण	इकाई	चीन जन. गण. से निर्यातक	जापान के निर्यातक	कोरिया गण. जन. के निर्यातक	कुल
स्थापित क्षमता	वर्गमीटर	***	***	***	***
उत्पादन	वर्गमीटर	***	***	***	***
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
कुल बिक्री	वर्गमीटर	***	***	***	***
निर्यात बिक्री	वर्गमीटर	***	***	***	***
अधिशेष क्षमता	वर्गमीटर	***	***	***	***
निर्यात अभिविन्यास - निर्यात बिक्री का कुल बिक्री से अनुपात	%	40-50%	50-60%	40-50%	50-60%

146. जैसा कि ऊपर से देखा जा सकता है,

- क. उत्पादकों और निर्यातकों के पास कुल भारतीय मांग की तुलना में कहीं अधिक क्षमता है। इसके अलावा, सहभागी उत्पादकों और निर्यातकों के पास उपलब्ध अप्रयुक्त क्षमता भारतीय मांग का लगभग ***% है।
- ख. उत्पादक और निर्यातक अत्यधिक निर्यातोन्मुख हैं और कुल बिक्री का लगभग ***% -***% संबंधित देशों से निर्यात किया जाता है। इन निर्यातों को भारत की ओर मोड़ा जा सकता है।

विभिन्न देशों द्वारा शुल्क लगाना

147. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि विभिन्न देशों ने चीन जन. गण. और अन्य देशों के खिलाफ पीयूसी पर पाटन रोधी शुल्क लगाया है। इसका विवरण निम्नानुसार है:

- क. ब्राजील: ब्राजील ने 4 मई, 2021 को चीन जन. गण., चीनी ताइपे, यूएसए, यूरोपीय संघ और यूके से आयातित पीयूसी पर पांच साल की अवधि के लिए निश्चित पाटन रोधी शुल्क बढ़ा दिया है। शुल्क 0.19 - 2.38 अमरीकी डालर
- ख. दक्षिण कोरिया: दक्षिण कोरिया ने 25 अक्टूबर, 2022 को चीन जन. गण. से आयातित पीयूसी पर पाटन रोधी शुल्क पांच साल की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। शुल्क 8.78 - 10.32% से लेकर है।

- ग. चीनी ताइपे: 25 मई, 2023 को, चीनी ताइपे के वित्त मंत्रालय ने चीन जन. गण. में उत्पन्न या आयात किए गए पीयूसी पर पाटन रोधी जांच शुरू की। जून 2024 में, चीनी ताइपे ने चीन जन. गण. से आयात पर शुल्क लगाया। शुल्क 13.52% - 76.89% तक है।
- घ. संयुक्त राज्य अमेरिका: संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रारंभिक रूप से निर्धारित किया है कि अमेरिका को डीओपीपी के चीनी निर्यात को डंप और सब्सिडी दोनों दी जा रही है। प्रारंभिक सीवीडी शुल्क 38.5 - 231.98% के बीच है, जबकि प्रारंभिक पाटन रोधी शुल्क 164.30-477.59% तक है। इसके अलावा, अमेरिका जापान से आयात के खिलाफ पाटन रोधी जांच कर रहा है।

148. प्राधिकरण ने पाया कि संबद्ध देशों के निर्यातक और उत्पादक पाटन रोधी शुल्क लागू होने के बावजूद भारत में पीयूसी की पाटन कर रहे हैं। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि पाटन व्यवहार से यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि पाटन रोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में, संबद्ध देशों के उत्पादक/निर्यातक भारत में उत्पाद का पाटन जारी रखेंगे।

आयात का दमन और निराशाजनक प्रभाव

149. जैसा कि क्षति के आकलन से देखा गया है, संबंधित देशों से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों को दबाने के साथ-साथ घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य को कम कर रहा है। नीचे दी गई तालिका से भी यही स्पष्ट है:

विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	2021-22	पीओआई
बनाने और बेचने की लागत	आईएनआर/वर्गमीटर	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	96	115	142
घरेलू बिक्री मूल्य	आईएनआर/वर्गमीटर	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	100	114	133
लैंड ड्राइस	आईएनआर/वर्गमीटर	228	259	304	323
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	114	133	141
मूल्य अंडरकटिंग	%	***	***	***	***
सामान्य प्रवृत्ति	अनुक्रमित	100	(6.07)	(25.86)	46.25
मूल्य अंडरकटिंग	% - श्रेणी	20-40%	ऋणात्मक	ऋणात्मक	40-50%

150. यह देखा गया है कि जांच अवधि में, संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत से कम है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि उपायों की समाप्ति के साथ, आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर महत्वपूर्ण निराशाजनक या दमनकारी प्रभाव पड़ेगा।

151. जांच की अवधि के बाद: प्राधिकारी नोट करते हैं कि कुछ हितबद्ध पक्षों ने प्राधिकारी से वर्तमान समीक्षा में जांच की अवधि के बाद के आंकड़ों का आकलन करने का अनुरोध किया है। यह नोट किया जाता है कि चूंकि पाटन जारी रहने और क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना को स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं, इसलिए जांच की अवधि के बा

ठ. भारतीय उद्योग हित और अन्य मुद्दे

12. ठ.1 अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए प्रस्तुतियाँ

152. इच्छुक पार्टियों ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

क. फेडरेशन का तर्क है कि प्रिंटिंग प्लेटों के लिए भारतीय बाजार में मांग-आपूर्ति का महत्वपूर्ण अंतर सभी स्रोतों द्वारा निरंतर पाटन के आरोप को आर्थिक रूप से असंभव बनाता है। भारत में प्रिंटिंग प्लेटों का कुल बाजार

सालाना लगभग 48 मिलियन वर्गमीटर है, जिसमें सीटीसीपी डिजिटल ऑफसेट प्लेट्स के लिए 18.5 मिलियन वर्गमीटर, थर्मल डिजिटल ऑफसेट प्लेट्स के लिए 13 मिलियन वर्गमीटर, केमिकल-फ्री प्लेट्स के लिए 7 मिलियन वर्गमीटर और प्रोसेस-लेस प्लेट्स के लिए 1.5 मिलियन वर्गमीटर शामिल हैं। घरेलू निर्माता केवल 20-25 मिलियन वर्गमीटर का उत्पादन कर सकते हैं, जो लगभग 50% मांग को कवर करता है, जिससे उपयोगकर्ता उद्योग को शेष आवश्यकता के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। यह मांग-आपूर्ति अंतर निर्यातकों को भारतीय बाजार में कीमतें निर्धारित करने में एक फायदा देता है, जिससे यह संभावना नहीं है कि सभी निर्यातक पाटन का सहारा लेंगे या सरकारें निर्यात को सब्सिडी देंगी, जैसा कि आवेदक द्वारा दावा किया गया है। चल रही मांग-आपूर्ति के अंतर के कारण, पाटन रोधी या एंटी-सब्सिडी शुल्क लगाने या जारी रखने से लागत में वृद्धि और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करके उपयोगकर्ता मुद्रण उद्योग को नुकसान होगा।

- ख. घरेलू उद्योग, विशेष रूप से टेक्नोवा, नियमित गुणवत्ता और आपूर्ति व्यवधान के मुद्दों का सामना करता है। टेक्नोवा की प्लेटों के साथ स्पॉट मुद्दों, अस्तर के मुद्दों और संवेदनशीलता विविधताओं जैसी समस्याओं की सूचना दी गई है। इसके विपरीत, आयातित प्लेटें लगातार गुणवत्ता प्रदान करती हैं, जिससे वे विश्वसनीय प्रिंटिंग आउटपुट चाहने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतर हो जाते हैं। इन मुद्दों और स्पष्ट मांग-आपूर्ति अंतर के बावजूद, टेक्नोवा सहित घरेलू उत्पादकों ने उत्पादन बढ़ाने या उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण प्रयास नहीं किए हैं।
- ग. टेक्नोवा, अगफा के साथ साझेदारी में, घरेलू मांग को पूरा करने के लिए गुणवत्ता बनाए रखने या उत्पादन का विस्तार करने में विफल रही है, जबकि प्रतिबंध चीन जैसे देशों के उत्पादकों को भारतीय बाजार में प्रवेश करने से रोकते हैं।
- घ. पाटन रोधी कर्तव्यों को जारी रखने से आयात की लागत बढ़ाकर प्रिंटिंग और प्रकाशन कंपनियों सहित पीयूसी पर निर्भर उद्योगों के लिए लागत बढ़ सकती है। इस लागत वृद्धि के परिणामस्वरूप मुद्रित सामग्री, पैकेजिंग और संबंधित उत्पादों के लिए उच्च कीमतें हो सकती हैं, जो अंततः उपभोक्ताओं को दी जाएंगी।
- ङ. उंची कीमतें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मुद्रण और प्रकाशन क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता को कम कर सकती हैं और कम मार्जिन पर काम करने वाले उद्योगों में लाभ मार्जिन को नुकसान पहुंचा सकती हैं।
- च. कर्तव्यों को बनाए रखने से स्थापित आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित किया जा सकता है, विशेष रूप से तंग मार्जिन वाली कंपनियों के लिए जो डीओपीपी की सस्ती और स्थिर आपूर्ति पर निर्भर करती हैं।
- छ. यदि घरेलू उत्पादन मांग को पूरा नहीं कर सकता है, तो पाटन रोधी कर्तव्यों के कारण बड़ी हुई लागत उत्पादन में देरी, उत्पादन में कमी या उपयोगकर्ता उद्योग के लिए लाभप्रदता में कमी का कारण बन सकती है। व्यापक आर्थिक प्रभाव पर भी विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रिंटिंग और पैकेजिंग उद्योग भारत में रोजगार और सहायक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। एमएसएमइ, विशेष रूप से, उच्च इनपुट लागत के साथ संघर्ष करेंगे, जिससे उनकी वित्तीय स्थिरता और विकास की संभावनाओं को खतरा होगा।
- ज. कर्तव्यों की निरंतरता से डीओपीपी पर निर्भर डाउनस्ट्रीम उद्योगों के लिए परिचालन लागत में वृद्धि हो सकती है, आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर सकती है और व्यापक अर्थव्यवस्था को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। उत्पादक/निर्यातक का तर्क है कि मांग-आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए आयात पर चल रही निर्भरता आवश्यक है, और एडीडी लगाने से घरेलू उद्योग के संघर्षों के मूल कारणों को संबोधित किए बिना डाउनस्ट्रीम उद्योग को नुकसान पहुंचता है।
- झ. चीनी निर्माताओं द्वारा उत्पादित डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेटें बेहतर गुणवत्ता की हैं, बिना तकनीकी मुद्दों के टेक्नोवा के उत्पादों के साथ सामना करना पड़ता है, जो पुरानी तकनीक का उपयोग करते हैं।
- ञ. प्रिंटिंग उद्योग में रन-लेंथ के आधार पर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन शामिल हैं। बड़ी मात्रा में (जैसे, समाचार पत्र) के लिए लंबे समय तक चलता है जहां प्लेट लागत परिचालन व्यय का एक छोटा हिस्सा है। ब्रोशर और कैटलॉग जैसे प्रिंट वॉल्यूम के लिए मध्यम चलता है, जो पारंपरिक ऑफसेट प्रिंटिंग की उच्च सेटअप लागत को सही नहीं ठहरा सकता है। ऑन-डिमांड या सीमित मात्रा (जैसे, बिजनेस कार्ड) के लिए शॉर्ट रन, जहां प्लेट की लागत कुल व्यय का 85% तक हो सकती है, जिससे मूल्य परिवर्तन प्रभावशाली हो सकते हैं।

- ट. डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेटों पर पाटन रोधी शुल्क लगाने से कच्चे माल की लागत में वृद्धि और पहले से ही मूल्य-संवेदनशील बाजार में लाभ मार्जिन को निचोड़कर पैकेजिंग प्रिंटिंग उद्योग को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया गया है।
- ठ. बड़ी हुई लागत प्लेट व्यूरो और प्री-प्रेस घरों को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, जो डिजिटल ऑफसेट प्लेटों पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं। कर्तव्यों का अधिरोपण उनकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करता है।
- ड. स्थानीय निर्माताओं की रक्षा करना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह दावा कि इस क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के लिए पाटन रोधी शुल्क जारी रखना महत्वपूर्ण है, निराधार है।

13. ठ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण

153. इच्छुक पार्टियों ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं:

- क. पाटन रोधी कर्तव्यों को जारी रखने से डाउनस्ट्रीम उद्योगों पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा, जिसमें 20% औसत शुल्क अखबार, वाणिज्यिक और पैकेजिंग प्रिंटिंग जैसे क्षेत्रों में प्रिंट जॉब की औसत लागत का केवल 0.5% से 1.5% होगा। कर्तव्यों का विरोध करने वाले किसी भी उपयोगकर्ता ने कर्तव्यों से किसी भी प्रतिकूल सार्वजनिक हित प्रभाव का प्रदर्शन नहीं किया है।
- ख. शुल्कों को जारी न रखने से घरेलू उद्योग बंद हो जाएगा, जो प्रिंटिंग क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के लिए महत्वपूर्ण है, जो मीडिया, प्रकाशन और पैकेजिंग जैसे उद्योगों के लिए आवश्यक है।
- ग. डीओपीपी बाजार में अक्सर तत्काल आवश्यकताएं होती हैं, खासकर समाचार पत्रों और पैकेजिंग जैसे क्षेत्रों में। आयात पर भरोसा देरी, गुणवत्ता के मुद्दों और मूल्य अस्थिरता के जोखिमों का परिचय देता है, जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अस्वीकार्य हैं।
- घ. घरेलू उद्योग ने तत्काल मांगों को कुशलतापूर्वक पूरा करने की अपनी क्षमता साबित की है, जैसा कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान देखा गया है।
- ड. लॉकडाउन के दौरान, वैश्विक आपूर्ति शृंखला बाधित हो गई थी, लेकिन घरेलू स्तर पर उत्पादित डीओपीपी की उपलब्धता के कारण भारतीय समाचार पत्र उद्योग ने कार्य करना जारी रखा।
- च. आयात अनुपलब्ध होने के कारण, राष्ट्र घरेलू निर्माताओं पर निर्भर था, राष्ट्रीय सुरक्षा और आवश्यक सेवाओं की निरंतरता के लिए एक मजबूत घरेलू उद्योग के महत्व का प्रदर्शन करता है।
- छ. डीओपीपी के रणनीतिक महत्व के बावजूद, घरेलू उद्योग कृत्रिम रूप से कम कीमतों पर बेचे जा रहे पाटित किए गए आयात के कारण जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा है।
- ज. ये आयात घरेलू विनिर्माताओं की कीमतों को काफी कम कर रहे हैं, जिससे घरेलू उद्योग के लिए परिचालन जारी रखना आर्थिक रूप से अव्यवहार्य हो गया है।
- झ. घरेलू संयंत्रों के बंद होने से नौकरियों का काफी नुकसान होगा और भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर हो जाएगा।
- ञ. यह भविष्य की आपात स्थितियों का जवाब देने की भारत की क्षमता को खतरे में डाल देगा जिसके लिए त्वरित और विश्वसनीय आपूर्ति की आवश्यकता होती है।
- ट. यह सुनिश्चित करने के लिये कि भारत इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रहे, जो संकट के दौरान राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है, यह महत्वपूर्ण है कि प्राधिकरण डीओपीपी आयात पर पाटन रोधी शुल्क जारी रखे।
- ठ. पार्टियों ने तर्क दिया कि आयातित प्लेटों को लगातार गुणवत्ता के कारण पसंद किया जाता है, जबकि घरेलू प्लेटों में अक्सर गुणवत्ता के मुद्दे होते हैं। घरेलू उद्योग ने नोट किया कि टेक्नोवा की सबसे कम अस्वीकृति दरों में से एक है और इस बात पर जोर दिया कि पाटन रोधी कर्तव्यों का उद्देश्य उचित मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करना है, उत्पाद की गुणवत्ता के आधार पर प्रतिस्पर्धा को सीमित नहीं करना है।

14. 3.3 प्राधिकरण द्वारा समीक्षा

154. प्राधिकरण ने इस बात पर विचार किया कि क्या एडीडी के विस्तार से लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए, प्राधिकरण ने जांच की कि क्या जांच के तहत उत्पाद के आयात पर पाटन रोधी शुल्क का विस्तार बड़े सार्वजनिक हित के खिलाफ होगा। यह निर्धारण घरेलू उद्योग, आयातकों और उत्पाद के उपभोक्ताओं सहित विभिन्न पक्षों के रिकॉर्ड और हितों पर जानकारी पर विचार करने पर आधारित है।
155. प्राधिकरण ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य इच्छुक पार्टियों सहित सभी इच्छुक पार्टियों से विचार आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की है ताकि वर्तमान जांच के संबंध में प्रासंगिक जानकारी प्रदान की जा सके, जिसमें उनके संचालन पर पाटन रोधी कर्तव्यों के संभावित प्रभाव भी शामिल हैं। प्राधिकरण ने अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न देशों से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्त किए गए उत्पाद की विनिमयता, उपभोक्ताओं की छोटों को बदलने की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्कों के प्रभाव, ऐसे कारकों के संबंध में सूचना मांगी है जिनसे पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण नई स्थिति में समायोजन में तेजी आने अथवा विलंब होने की संभावना है।
156. यह नोट किया जाता है कि सामान्यतः पाटनरोधी उपायों का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित की जा सके जो देश के सामान्य हित में है। प्राधिकरण यह मानता है कि पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखने से विचाराधीन उत्पाद के मूल्य स्तर के साथ-साथ भारत में संबंधित वस्तुओं का उपयोग करके विनिर्मित अन्य डाउनस्ट्रीम उत्पादों पर प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि, पाटन रोधी उपायों को लागू करने से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपायों को जारी रखने से संबंधित देशों से कम कीमत वाले आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की गिरावट को रोका जा सकेगा और विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ताओं को विकल्पों की व्यापक उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
157. यह भी दावा किया गया है कि देश में मांग और आपूर्ति में अंतर है। हालांकि, प्राधिकरण नोट करता है कि मांग-आपूर्ति अंतर पाटन को उचित नहीं ठहराता है। प्राधिकरण नोट करता है कि पाटन रोधी शुल्क आयात को अवरुद्ध करने के लिए नहीं लगाया जाता है, बल्कि घरेलू बाजार में एक स्तर का खेल मैदान बनाने के लिए लगाया जाता है। पीयूसी का उपयोगकर्ता उद्योग उचित मूल्य पर आयात जारी रख सकता है। प्राधिकरण नोट करता है कि प्रयोक्ता उद्योग के लिए व्यवहार्य घरेलू उद्योग (घरेलू उत्पादन के 95% से अधिक के लिए एकमात्र बड़ा उत्पादक होने के नाते) का अस्तित्व आवश्यक है ताकि आयात पर अत्यधिक निर्भर होने से बचा जा सके जिससे आपूर्त श्रृंखला व्यवधान की उच्च संभावना हो।
158. इच्छुक पार्टियों ने दावा किया है कि घरेलू रूप से निर्मित उत्पादों में स्पॉट मुद्दे, अस्तर के मुद्दे और संवेदनशीलता भिन्नता आदि जैसे गुणवत्ता के मुद्दे हैं। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उद्योग में इसकी अस्वीकृति दर सबसे कम है और इस संबंध में प्रासंगिक आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। प्राधिकरण नोट करता है कि पाटनरोधी उपायों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी उत्पादों, चाहे वे घरेलू हों या आयातित, का उचित मूल्य निर्धारण किया जाए और अनुचित प्रतिस्पर्धा के माध्यम से घरेलू उद्योग को कमजोर न किया जाए। पाटन रोधी कर्तव्यों का उद्देश्य खेल के मैदान को समतल करना और बाजार की अखंडता की रक्षा करना है, घरेलू और विदेशी दोनों उत्पादकों को अनुचित व्यापार प्रथाओं में संलग्न किए बिना उच्च मानकों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
159. प्राधिकरण नोट करता है कि इच्छुक पार्टियों ने यह प्रदर्शित नहीं किया है कि विषय वस्तुओं की कीमतों ने उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव कैसे डाला है। दूसरी ओर, घरेलू उद्योग ने मात्रात्मक सूचना प्रस्तुत की है जिसमें यह दर्शाया गया है कि प्रयोक्ता उद्योग पर पाटनरोधी शुल्कों का प्रभाव न्यूनतम होगा। घरेलू उद्योग ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान प्रचलित पाटन रोधी शुल्क (20% की औसत दर मानते हुए) समाचार पत्र मुद्रण खंड, वाणिज्यिक मुद्रण खंड और पैकेजिंग प्रिंटिंग सेगमेंट जैसे प्रमुख अंतिम उपयोग खंडों में प्रिंट जॉब की औसत लागत में केवल 0.5% से 1.5% की लागत वृद्धि में अनुवाद करता है। रिकॉर्ड पर दी गई जानकारी से, प्राधिकरण नोट करता है कि पाटन रोधी झूटी का प्रभाव विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ताओं पर बहुत कम है।

160. घरेलू उद्योग अपनी विनिर्माण क्षमता की सीमा तक हिंडालको से अपना मुख्य कच्चा माल (लिथो ग्रेड एल्यूमीनियम काँडल) खरीदता है। प्राधिकरण नोट करता है कि घरेलू उद्योग द्वारा पीयूसी के उत्पादन में किसी भी गिरावट से लिथो ग्रेड एल्यूमीनियम काँडल के लिए हिंडालको के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि घरेलू उद्योग देश में संबंधित वस्तुओं का एकमात्र बड़ा निर्माता है। प्राधिकरण यह भी नोट करता है कि हिंडालको ने पीयूसी के आयात पर पाटन रोधी शुल्क लगाने के लिए घरेलू उद्योग को समर्थन दिया है।

ढ. पोस्ट प्रकटीकरण विश्लेषण

161. प्राधिकरण ने 20 सितंबर 2024 को सभी इच्छुक पक्षों को केंद्र सरकार को अंतिम सिफारिशें करने के लिए विचाराधीन सभी आवश्यक तथ्यों से युक्त प्रकटीकरण विवरण प्रसारित किया। इच्छुक पक्षों को 25 सितंबर 2024 तक प्रकटीकरण विवरण पर अपनी टिप्पणियाँ दाखिल करने का निर्देश दिया गया। प्राधिकरण ने प्रासंगिक समझी गई सीमा तक इन अंतिम निष्कर्षों में इच्छुक पक्षों द्वारा की गई सभी प्रकटीकरण-पश्चात टिप्पणियों की जांच की है। कोई भी प्रस्तुतिकरण जो केवल पिछले प्रस्तुतिकरण का पुनरुत्पादन था और जिसकी प्राधिकरण द्वारा पर्याप्त रूप से जांच की गई थी, उसे संक्षिप्तता के लिए दोहराया नहीं गया है।

ढ.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण:

162. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित प्रस्तुत किए हैं

- क. आवेदक ने इच्छुक पक्षों द्वारा किए गए दावों का खंडन किया है कि उन्होंने भविष्य में क्षमता विस्तार में 400 करोड़ रुपये निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई थी। आवेदक ने स्पष्ट किया कि 400 करोड़ रुपये इस अवधि तक विनिर्माण सुविधाओं में किए गए संचयी निवेश थे, न कि भविष्य की प्रतिबद्धता। उनका तर्क है कि एक बार समान अवसर बहाल हो जाने पर, आगे निवेश किया जाएगा।
- ख. आवेदक का तर्क है कि श्रीलंका और स्पेन से गलत घोषित आयात, जो वास्तव में चीनी मूल के हैं, को प्राधिकरण के क्षति मूल्यांकन में शामिल किया जाना चाहिए। उनका दावा है कि इन आयातों को बाहर करने से क्षति का विश्लेषण बिगड़ जाता है और चीनी निर्यातक पाटन रोधी ड्यूटी से बचने के लिए ट्रांसशिपमेंट जैसे व्यापार कदाचार में संलग्न हैं।
- ग. आवेदक हुआंगशान जिनरुइताई और चोंगकिंग हुआफेंग जैसे उत्पादकों को अलग से ड्यूटी मार्जिन देने के प्राधिकरण के फैसले से असहमत है। टेकनोवा का तर्क है कि शुल्क की अवशिष्ट दर को इन उत्पादकों तक बढ़ाया जाना चाहिए, प्राधिकरण के पिछले अभ्यास का हवाला देते हुए अन्य सूर्यास्त समीक्षाओं में जहां नए उत्पादकों पर समान दर लागू की गई थी।

ढ.2 अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा प्रस्तुतियाँ-

163. अन्य इच्छुक पार्टियों ने निम्नलिखित प्रस्तुत किया है:

- क. जेइल सी एंड पी कंपनी लिमिटेड का तर्क है कि परिशिष्ट 8 में प्रति इकाई लागत में त्रुटियों के कारण डंपिंग मार्जिन (80-90%) की गलत गणना की गई थी। उनका दावा है कि इन्वेंट्री समायोजन को बाहर करने से बेची गई वस्तुओं की लागत बढ़ गई है और वे पुनर्गणना का अनुरोध करते हैं। वे प्राधिकरण द्वारा उनके इन्वेंट्री समायोजन दावे को अस्वीकार करने पर भी विवाद करते हैं, यह बताते हुए कि यह उत्पादन और बिक्री मात्रा के बीच अंतर को दर्शाता है, समायोजन नहीं। वे सटीक लागत प्रतिनिधित्व के लिए पुनर्विचार का अनुरोध करते हैं।
- ख. कपूर इमेजिंग ने लकी हुआगुआंग ग्राफिक्स कंपनी लिमिटेड और कोडक (चीन) ग्राफिक कम्युनिकेशंस कंपनी लिमिटेड को उनकी संबद्धता के बावजूद अलग-अलग डंपिंग और क्षति मार्जिन आवंटित करने के निर्णय को चुनौती दी। उनका तर्क है कि, स्थापित अभ्यास के अनुरूप, संबद्ध कंपनियों के पास एक संक्षिप्त मार्जिन होना चाहिए (यानी, दोनों कंपनियों के लिए एक संयुक्त मार्जिन) कपूर का मानना है कि अलग-अलग मार्जिन प्रदान करने का निर्णय पूर्व मामलों के साथ असंगत है और अनुरोध करता है कि निष्पक्षता के लिए मार्जिन को समेकित किया जाए।
- ग. कपूर इमेजिंग ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान अस्थायी गिरावट को छोड़कर उत्पाद की मांग स्थिर बनी हुई है। उनका तर्क है कि जांच की अवधि (पीओआई) के दौरान विषय देशों से आयात में

- गिरावट आई है। इसके बावजूद, घरेलू उद्योग क्षति का दावा करता है, जिसे कपूर विवाद करते हैं, जोर देकर कहते हैं कि उद्योग के खराब प्रदर्शन के लिए आयात जिम्मेदार नहीं है।
- घ. कपूर इमेजिंग ने प्रस्तुत किया कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में लगातार गिरावट आई है, जिसमें पीवीआईटी (ब्याज और करों से पहले लाभ), नकद लाभ और पूंजी नियोजित (आरओसीई) पर वापसी जैसे मैट्रिक्स में कमी शामिल है। उनका तर्क है कि पाटन रोधी कर्तव्यों से सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि घरेलू उद्योग का वित्तीय प्रदर्शन खराब हो गया है, इसका मतलब यह है कि आयात क्षति का कारण नहीं है। कपूर का सुझाव है कि घरेलू उद्योग के अपने खराब व्यावसायिक निर्णय, जिसमें इसकी मूल्य निर्धारण रणनीति भी शामिल है, को दोष देने की अधिक संभावना है।
- ङ. चोंगकिंग हुआफेंग ने प्राधिकरण के निर्णय पर आपत्ति जताई कि दोनों सहकारी निर्यातकों, जैसे चोंगकिंग हुआफेंग और गैर-सहकारी उत्पादकों के लिए समान डंपिंग मार्जिन और क्षति मार्जिन लागू किया जाए। यह व्यापार उपचार जांच के लिए परिचालन प्रथाओं के मैनुअल को संदर्भित करता है, जो सुझाव देता है कि सहकारी निर्यातकों को सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए गैर-सहकारी संस्थाओं की तुलना में कम शुल्क प्राप्त करना चाहिए। इसलिए, कंपनी चोंगकिंग हुआफेंग के लिए कम दर का अनुरोध करती है।
- च. अन्य इच्छुक पक्ष गैर-हानिकारक मूल्य (एनआईपी) की गणना में व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) द्वारा उपयोग किए जाने वाले 22% आरओसीई को चुनौती देते हैं। उनका तर्क है कि यह दर पुरानी है, जिसे 1987 में स्थापित किया गया था जब आर्थिक स्थिति (ब्याज दरें और कॉर्पोरेट टैक्स) काफी भिन्न थीं, जिससे कीमतें बढ़ गईं और घरेलू उद्योग के लिए अनुचित सुरक्षा हुई। इच्छुक पार्टियों ने ब्रिजस्टोन के फैसले का उल्लेख किया है और वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर कम, अधिक यथार्थवादी आरओसीई का उपयोग करने का सुझाव दिया है।
- छ. ईस्टमैन कोडक ने प्रस्तुत किया कि प्राधिकरण ने एक अन्य निर्यातक, अनहुई स्ट्रॉन्ग स्टेट न्यू मैटेरियल्स कंपनी के लिए शून्य क्षति मार्जिन पाया है, जिसका अर्थ है कि कोई पाटन रोधी शुल्क लागू नहीं किया जाएगा। ईस्टमैन कोडक ने इस दृढ़ संकल्प पर चिंता जताई, संदेह है कि टेकनोवा कर्तव्यों से बचने के लिए अस्थायी रूप से बढ़ी हुई कीमतों पर अनहुई स्ट्रॉन्ग से उत्पादों का आयात कर सकता है।
- ज. ईस्टमैन कोडक पाटन रोधी उपायों के संभावित परिधि को रोकने के लिए अनहुई स्ट्रॉन्ग के मार्जिन के पुनर्मूल्यांकन का अनुरोध करता है।
- झ. इच्छुक पार्टियों ने तर्क दिया है कि यह स्पष्ट नहीं है कि आवेदक ने डेटा आयात और क्षति को उचित रूप से अलग किया है या नहीं।
- ञ. इंटरटेड पार्टियों ने तर्क दिया है कि टेकनोवा द्वारा आयात का यह स्तर पर्याप्त है। इसके अलावा, पार्टियों ने दावा किया है कि ये आयात "कभी-कभी" अनुचित हैं। पार्टियों ने तर्क दिया है कि टेकनोवा को नियमों के तहत पात्र घरेलू उद्योग नहीं माना जा सकता है।
- ट. क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना का ठीक से विश्लेषण नहीं किया गया है। उनका तर्क है कि प्राधिकरण ने पोस्ट-पीओआई डेटा का विश्लेषण नहीं किया है।
- ठ. जनहित मूल्यांकन में, इच्छुक पार्टियों ने प्रस्तुत किया है कि प्राधिकरण ने उपयोगकर्ता उद्योग द्वारा उठाई गई चिंताओं को कम कर दिया है, जिसमें मांग-आपूर्ति अंतर, गुणवत्ता के मुद्दे और उपयोगकर्ता उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। प्राधिकरण उपयोगकर्ता उद्योग की तुलना में टेकनोवा (घरेलू उद्योग) को कच्चे माल की एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता, हिंडालको पर संभावित प्रभाव के बारे में अधिक चिंतित है।
- ड. कोडक इंडिया ने अनुरोध किया कि विभिन्न प्रकार की डिजिटल प्लेटों (थर्मल, वायलेट और सीटीसीपी प्लेट्स) के लिए अलग-अलग शुल्क लगाए जाने चाहिए, क्योंकि उनकी कीमत और बाजार की गतिशीलता अलग-अलग है। इसके अलावा, कोडक ने प्रस्तुत किया कि प्राधिकरण ने इन श्रेणियों के लिए शुल्क का एक संदर्भ मूल्य रूप निर्धारित किया है, और कोडक अनुरोध करता है कि वर्तमान समीक्षा में उसी पद्धति को लागू किया जाए।

ढ.3 प्राधिकरण द्वारा समीक्षा

164. अपने इन्वेस्ट्री समायोजन दावे की अस्वीकृति के कारण डंपिंग मार्जिन की गलत गणना के बारे में जेइल के तर्क के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि जेइल ने परिशिष्ट 8 में उत्पादन की लागत *** के आरडब्ल्यू / एसक्यूएम का दावा किया है। प्राधिकारी ने मामूली समायोजन के साथ इसे अपना लिया है और इसका उपयोग कंपनी के लिए सामान्य मूल्य की गणना करने के लिए किया गया था। प्रकटीकरण विवरण जारी करने के बाद कंपनी ने दावा किया है कि परिशिष्ट 7 और 8 में दावा किए गए कॉर्पोरेट ओवरहेड्स चीन से खरीदे गए और घरेलू बाजार में बेचे

गए विषयगत सामानों से संबंधित हैं। हालांकि, कंपनी द्वारा अपने दावे को पुष्ट करने के लिए कोई सहायक दस्तावेजी साक्ष्य प्रदान नहीं किए गए थे। उपर्युक्त के मद्देनजर, प्राधिकारी ने कंपनी के मूल प्रश्नावली प्रतिक्रिया के साथ-साथ डेस्क सत्यापन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार दावे को ध्यान में रखते हुए उत्पादन की लागत निर्धारित की है।

165. इच्छुक पार्टियों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग ने कोई निवेश नहीं किया है जैसा कि मूल जांच में दावा किया गया है। जवाब में, घरेलू उद्योग ने स्पष्ट किया कि उसने पीयूसी के उत्पादन के लिए 400 करोड़ रुपये का संचयी निवेश किया है, जैसा कि मूल जांच में जारी 15 मई, 2020 के अंतिम निष्कर्षों के पैरा 18 (डी) में स्वीकार किया गया है। उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर, प्राधिकरण नोट करता है कि घरेलू उद्योग ने संयंत्र और मशीनरी में *** लाख रुपये का निवेश किया है, जो लंबित स्थापना में पूंजीगत कार्य का हिस्सा है। यह निवेश भविष्य में अपनी क्षमताओं का विस्तार करने के लिए घरेलू उद्योग के इरादे को इंगित करता है।
166. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि श्रीलंका और स्पेन से आयात की मात्रा गलत घोषित की गई है और उचित क्षति मूल्यांकन के लिए विषय देश की मात्रा में शामिल किया जाना चाहिए। प्राधिकरण नोट करता है कि गलत घोषणा का मुद्दा वर्तमान समीक्षा जांच के दायरे में नहीं है। इसलिए, इस तरह के आयातों को अधीन देशों के साथ संचयी करना अनुचित है। घरेलू उद्योग ऐसे आयातों के विरुद्ध परिवंचनारोधी जांच दर्ज करा सकता है।
167. लकी और कोडक के लिए कर्तव्यों के संयोजन पर इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए सबमिशन के संबंध में, प्राधिकरण निम्नलिखित नोट करता है:
 - उपलब्ध जानकारी के आधार पर, कोडक चीन के अधिकांश शेयरों को मूल जांच के पीओआई के बाद लकी द्वारा अधिग्रहित किया गया था।
 - लकी और कोडक चीन अलग-अलग कानूनी संस्थाओं के रूप में काम करना जारी रखते हैं। जबकि लकी ने कोडक चीन का नियंत्रण ग्रहण किया है, दोनों कंपनियां अलग-अलग प्रबंधन के तहत काम करती हैं और अलग-अलग विनिर्माण सुविधाएं रखती हैं।
168. प्राधिकरण नोट करता है कि उसने मूल जांच में स्वामित्व में बदलाव के मुद्दे पर विचार किया था, जिसमें प्राधिकरण ने स्वीकार किया कि लकी ने पीओआई के बाद कोडक चीन का अधिग्रहण किया था। प्राधिकरण ने कहा कि *विलय के बाद बनने वाली इकाई के निर्यात मूल्य निर्धारण व्यवहार का मूल्यांकन संबंधित नियमों/प्रक्रिया के अनुसार किसी भी इच्छुक पक्ष द्वारा दायर किए जाने पर समीक्षा जांच के तहत किया जा सकता है।* इस संबंध में, प्राधिकरण ने इस समीक्षा के लिए जांच की अवधि में दोनों संस्थाओं के मूल्य व्यवहार की तुलना मूल जांच से की है। प्राधिकरण नोट करता है कि लकी और कोडक चीन के लिए मूल्य व्यवहार मूल जांच के समान है, और इसलिए, मूल जांच में उनके लिए गणना की गई मार्जिन को इस समय किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है।
169. इसे देखते हुए, प्राधिकरण मूल जांच में लगाए गए कोडक चाइना और लकी को अलग-अलग शुल्क देना उचित समझता है।
170. प्राधिकरण सभी पाटनरोधी जांचों में मानक पद्धति के रूप में नियोजित पूंजी की 22% दर (आरओसीई) को लगातार लागू करता है। ब्रिजस्टोन मामले में एलडी सीईएसटीएटी की टिप्पणियां मूल्य अंडरसेलिंग का निर्धारण करने में 22% आरओसीई के उपयोग के लिए विशिष्ट थीं, न कि गैर-हानिकारक मूल्य (एनआईपी) की गणना में इसकी उपयुक्तता। इसके अलावा, ब्रिजस्टोन निर्णय एडी नियमों के अनुलग्नक-III की शुरुआत से पहले का है, अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा इस पर निर्भरता प्रदान करना अनुचित है। बाद के मेरिनो पैनेल उत्पाद मामले में, सीस्टेट ने 22% आरओसीई लागू करने के डीजीटीआर के अभ्यास को बरकरार रखा।

171. अनहुई स्ट्रॉन्ग के लिए निर्धारित नकारात्मक क्षति मार्जिन और डंपिंग मार्जिन पर इच्छुक पार्टियों के विवाद के संबंध में, प्राधिकरण ने की गई गणनाओं की समीक्षा की है और विनिमय दर में सुधार किया है। संशोधित डंपिंग और इंजरी मार्जिन उपरोक्त तालिकाओं में परिलक्षित होता है।
172. कई इच्छुक पक्षों ने तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग को नुकसान आयात के कारण नहीं बल्कि कुछ अन्य कारकों के कारण है क्योंकि पाटन रोधी शुल्क लगाने के बावजूद घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में गिरावट जारी है। इस संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि उसने क्षति के मापदंडों के साथ-साथ पूर्वगामी पैराग्राफ में विस्तार से गैर-एट्रिब्यूशन के मापदंडों की जांच की है। इसलिए, संक्षिप्तता के लिए यहां इसकी पुनरावृत्ति नहीं की जा रही है।
173. डेटा के पृथक्करण पर इच्छुक पार्टियों के विवाद के संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि उसने डीजी सिस्टम्स से आयात डेटा का विश्लेषण और पृथक्करण किया है और घरेलू उद्योग के रिकॉर्ड से क्षति डेटा को सत्यापित किया है।
174. विभिन्न इच्छुक पार्टियों ने तर्क दिया है कि देश में आयात मांग, आपूर्ति अंतर के कारण है। इस संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि मांग-आपूर अंतर शुल्क न लगाने का आधार नहीं हो सकता है, जैसा कि माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने एनओसीआईएल लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में भी निर्णय दिया था। भारत सरकार।
175. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयातों पर पक्षकारों के तर्क और इसकी स्थिति के संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि उसने वर्तमान निष्कर्षों के पूर्वगामी पैराग्राफ में घरेलू उद्योग द्वारा किए गए आयातों के साथ-साथ एडी नियमों के तहत इसकी स्थिति की विस्तार से जांच की है।
176. प्राधिकरण नोट करता है कि संभावना का आकलन करने के लिए एडी नियमों के तहत पोस्ट-पीओआई जानकारी अनिवार्य रूप से निर्धारित नहीं है। प्राधिकरण ने जांच के दौरान इच्छुक पार्टियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर संभावना के मानदंडों की जांच की है।
177. जनहित पर प्रस्तुतियों के संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि बड़े पैमाने पर जनता के हित का आकलन करना आवश्यक है जिसमें अपस्ट्रीम उद्योग, घरेलू उद्योग के साथ-साथ उपयोगकर्ता उद्योग भी शामिल हैं। इच्छुक पार्टियों का यह दावा कि प्राधिकरण ने केवल कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता पर प्रभाव पर विचार किया है, तथ्यात्मक रूप से गलत है। प्राधिकरण ने प्रयोक्ता उद्योग सहित आम जनता के हित पर शुल्कों के प्रभाव की जांच की है और शुल्कों के प्रभाव की मात्रा निर्धारित की है। प्राधिकरण ने कुछ प्रयोक्ताओं द्वारा यह स्वीकार करते हुए किए गए प्रस्तुतीकरण का भी संज्ञान लिया है कि व्यवहार्य घरेलू आपूर्तिकर्ता की निरंतर उपस्थिति जनहित में होगी।
178. जहां तक कर्तव्य के रूप में परिवर्तन पर पक्षों के प्रस्तुतीकरण का संबंध है, प्राधिकरण मानता है कि उपायों के रूप को मामला-दर-मामला आधार पर देखा जाना आवश्यक है। न तो अधिनियम की धारा 9 ए (5) और न ही नियमों के नियम 23 समीक्षा के चरण में फॉर्म के किसी विशेष रूप या संशोधन को निर्धारित या प्रतिबंधित करता है। तदनुसार। प्राधिकरण कर्तव्यों के एक ही रूप अर्थात् कर्तव्यों के निश्चित रूप को जारी रखना उचित समझता है।

ढ. निष्कर्ष

179. सभी इच्छुक पक्षों द्वारा किए गए सबमिशन और उसमें उठाए गए मुद्दों की जांच करने और रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि:
- क. मौजूदा पाटन रोधी शुल्क लगाने की अवधि को पांच वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाने के लिए सनसेट समीक्षा आरंभ करने के लिए आवेदन टेक्नोवा इमेजिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया था।

- ख. आवेदक पाटनरोधी नियमों के नियम 2(बी) के तहत एक पात्र घरेलू उद्योग है और भारतीय उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा इसका है। इसलिए, आवेदक वर्तमान जांच के उद्देश्य के लिए घरेलू उद्योग है।
- ग. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स है।
- घ. विचाराधीन उत्पाद के दायरे में तीन प्रकार की डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेटें शामिल हैं, अर्थात्,
- i. थर्मल प्लेट्स;
 - ii. बैंगनी प्लेटें;
 - iii. सीटीसीपी/यूवी सीटीपी प्लेट्स
- ङ. पानी रहित सीटीपी प्लेटों को पीयूसी के दायरे से बाहर रखा गया है।
- च. चूंकि चीन जनगण के किसी भी उत्पादक ने बाजार अर्थव्यवस्था उपचार के लिए अनुरोध दायर नहीं किया है, इसलिए चीन जनगण को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना गया है और सामान्य मूल्य का निर्धारण भारत में देय मूल्य के आधार पर किया गया है जो घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत पर आधारित है।
- छ. निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य को ध्यान में रखते हुए, संबंधित देशों से संबंधित वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन सकारात्मक है।
- ज. पिछले वर्ष की तुलना में भारत में विषय वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है। विशेष रूप से पिछले वर्षों की तुलना में पाटन रोधी शुल्क लागू होने के बावजूद भारत में आयात की मात्रा में वृद्धि हुई है। ऐसे आयातों की कम कटौती हो रही है और घरेलू उद्योग के मूल्यों पर इसका निराशाजनक प्रभाव पड़ रहा है। कम कीमत वाले आयात के कारण घरेलू उद्योग को कोई नुकसान हुआ है।
- झ. मूल्य कम करने और दबाने के परिणामस्वरूप नकारात्मक लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर वापसी हुई है।
- ञ. पाटन जारी रहने और इसके परिणामस्वरूप प्रभावी पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति के मामले में घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचने की संभावना है। यह निम्नलिखित से स्पष्ट है।
- घरेलू उद्योग की कीमतें विषय आयातों से दबी हुई और कम पाई गईं।
 - संबद्ध देशों के उत्पादकों ने पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद भारत में प्रदूषण नियंत्रण रेखा की डम्पिंग जारी रखी है।
 - विषय देशों के साथ-साथ संबद्ध देशों के सहयोगी उत्पादकों के साथ अधिशेष डिस्पोजेबल क्षमताएं।
 - चीन के उत्पादक ब्राजील, दक्षिण कोरिया, ताइवान और यूएसए से विषयगत वस्तुओं के आयातों पर व्यापार उपचारात्मक उपायों का सामना कर रहे हैं। शुल्कों की समाप्ति की स्थिति में, इन देशों को किए जाने वाले निर्यातों का विपथन भारत में किए जाने की संभावना है।
- ट. भारत में आयात घरेलू उद्योग के गैर-हानिकारक मूल्य से कम मूल्य पर किए गए हैं। पाटन रोधी शुल्क की समाप्ति के मामले में, आयात मूल्य कम होने की संभावना है।
- ठ. पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखना जनहित में है। यह निम्नलिखित से स्पष्ट है:
- उपयोगकर्ता उद्योग की लागत पर शुल्कों का प्रभाव नगण्य है जो उपयोगकर्ता खंड के आधार पर 0.5% से 1.5% की सीमा में है।
 - चूंकि घरेलू उद्योग ही संबंधित वस्तुओं का एकमात्र बड़ा विनिर्माता है, इसलिए घरेलू उद्योग विनिर्माण प्रचालनों पर कोई प्रभाव अपस्ट्रीम उद्योग को भी प्रभावित करेगा।
 - पाटनरोधी शुल्क देश में आयात पर रोक नहीं लगाता है बल्कि पाटित किए गए आयातों और घरेलू विनिर्माताओं के बीच समान अवसर सुनिश्चित करता है। व्यवहार्य घरेलू उद्योग यह सुनिश्चित करता है कि प्रयोक्ता उद्योग पूर्णतया आयातों पर निर्भर न रहे।

- भारतीय उद्योग ने भारत में क्षमता वृद्धि के लिए निवेश किया है जो स्थापना के लिए लंबित है।

ण. सिफारिशें

180. प्राधिकरण नोट करता है कि जांच शुरू की गई थी और सभी इच्छुक पक्षों को अधिसूचित किया गया था और घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों, उपयोगकर्ताओं और अन्य इच्छुक पक्षों को डंपिंग, क्षति और कारण लिंक के पहलुओं और घरेलू उद्योग को डंपिंग और क्षति की संभावना के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था।
181. इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि यदि मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों को समाप्त करने की अनुमति दी जाती है तो पाटन और क्षति की संभावना का सकारात्मक साक्ष्य है, प्राधिकरण का विचार है कि संबंधित देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात पर लागू पाटनरोधी शुल्क को आगे जारी रखा जाना अपेक्षित है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर स्थापित किया गया है, नामित प्राधिकारी संबंधित देशों से संबंधित वस्तुओं के आयात पर पाटन रोधी शुल्क के विस्तार की सिफारिश करना उचित समझता है। तदनुसार, संबंधित देशों के उत्पादकों के लिए पाटनरोधी शुल्कों की सिफारिश नीचे दी गई शुल्क सारणी के अनुसार की जाती है।
182. इस प्रकार, पाटनरोधी नियमावली के नियम 4(घ) और नियम 17(1)(ख) में निहित प्रावधानों के अनुसार, प्राधिकारी मौजूदा पाटनरोधी शुल्कों को जारी रखने की सिफारिश करते हैं, ताकि घरेलू उद्योग के लिए पाटन और क्षति की संभावना को समाप्त किया जा सके। इसके अलावा, प्राधिकारी का मानना है कि नए उत्पादक/निर्यातक, जिन्होंने मूल जांच में भाग नहीं लिया था और जिन्होंने वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच में पहली बार भाग लिया है, के लिए पाटनरोधी शुल्क की अलग-अलग दर की सिफारिश नहीं की जा सकती। तदनुसार, विषयगत देशों में मूलतः उत्पन्न या वहां से निर्यातित विषयगत वस्तुओं के सभी आयातों पर, केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच (5) वर्षों के लिए नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर निश्चित पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की जाती है।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	टैरिफ शीर्षक	माल का विवरण	मूल देश	निर्यात का देश	निर्माता	कुल धनराशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	8442.50, 3701.3000, 3704.0090, 3705.1000, 7606.1190, 7606.9190, 7606.9290	डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	लकी हुआगुआंग ग्राफिक्स कंपनी लिमिटेड	0.55	वर्गमीटर	यूएसडी
2.	-वही-	डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	कोडक चाइना ग्राफिक कम्युनिकेशंस कंपनी लिमिटेड	शून्य	वर्गमीटर	यूएसडी
3.	-वही-	डिजिटल ऑफसेट	चीन जन. गण.	चीन जन. गण.	फुजीफिल्म प्रिंटिंग प्लेट	शून्य	वर्गमीटर	यूएसडी

		प्रिंटिंग प्लेट्स		सहित कोई भी देश	(चीन) कं, लिमिटेड			
4.	-वही-	डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	अनहुइ स्ट्रांग स्टेट न्यू मटेरियल्स कं, लिमिटेड	0.60	वर्गमीटर	यूएसडी
5.	-वही-	डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के अलावा कोई भी निर्माता	0.77	वर्गमीटर	यूएसडी
6.	-वही-	डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	कोई अन्य देश	चीन जन. गण.	कोई भी निर्माता	0.77	वर्गमीटर	यूएसडी
7.	-वही-	डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	कोरिया गण. जन.	कोरिया गण. जन. सहित कोई भी देश	जेइल सी एंड पी कंपनी लिमिटेड	0.15	वर्गमीटर	यूएसडी
8.	-वही-	डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	कोरिया गण. जन.	कोरिया गण. जन. सहित कोई भी देश	क्रमांक (7) के अलावा कोई भी निर्माता	0.37	वर्गमीटर	यूएसडी
9.	-वही-	डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	कोई अन्य देश	कोरिया गण. जन.	कोई भी निर्माता	0.37	वर्गमीटर	यूएसडी
10.	-वही-	डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	जापान	जापान सहित कोई भी देश	फुजीफिल्म कॉर्पोरेशन	0.13	वर्गमीटर	यूएसडी
11.	-वही-	डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	जापान	जापान सहित कोई भी देश	क्रमांक (10) के अलावा कोई भी निर्माता	0.27	वर्गमीटर	यूएसडी
12.	-वही-	डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	कोई अन्य देश	जापान	कोई भी निर्माता	0.27	वर्गमीटर	यूएसडी
13.	-वही-	डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	ताइवान	ताइवान सहित कोई भी	कोई भी निर्माता	0.41	वर्गमीटर	यूएसडी

				देश				
14.	-वही-	डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	कोई अन्य देश	ताइवान	कोई भी निर्माता	0.41	वर्गमीटर	यूएसडी
15.	-वही-	डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	वियतनाम	वियतनाम सहित कोई भी देश	कोई भी निर्माता	0.60	वर्गमीटर	यूएसडी
16.	-वही-	डिजिटल ऑफसेट प्रिंटिंग प्लेट्स	कोई अन्य देश	वियतनाम	कोई भी निर्माता	0.60	वर्गमीटर	यूएसडी

***क्रेडिट कार्ड, सुरक्षा कार्ड आदि जैसे विशेष सामग्रियों पर मुद्रण के लिए उपयोग किए जाने वाले जलरहित सीटीपी प्लेटों को छोड़कर, कागज पर नहीं*

त. आगे की प्रक्रिया

183. इस सिफारिश से उत्पन्न होने वाले केन्द्र सरकार के आदेश के विरुद्ध अधिनियम के संगत उपबंधों के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील की जाएगी।

दर्पण जैन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

New Delhi, the 28th September, 2024

FINAL FINDINGS

Case No. AD(SSR)- 08/2023

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of “Digital Offset Printing Plates” (DOPP) originating in or exported from China PR, Japan, Korea RP, Vietnam, and Taiwan.

F. No. 7/20/2023 -DGTR - Having regard to the Customs Tariff Act 1975 as amended from time to time and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (“**AD Rules**”).

A. BACKGROUND OF THE CASE

1. The Designated Authority (hereinafter referred to as “the Authority”) received an application from TechNova Imaging Systems (P) Limited (hereinafter referred to as the “**applicant**” or the “**domestic industry**”) seeking initiation of a sunset review of the anti-dumping duty imposed on imports of Digital Offset Printing Plates (hereinafter to be referred to as “**DOPP**” or the “**subject goods**” or “**product under consideration**” or the “**PUC**”), originating in or exported from China PR, Korea RP, Japan, Taiwan and Vietnam (hereinafter referred to as the “**subject countries**”).
2. The original investigation concerning imports of the subject goods from the subject countries was initiated by the Authority vide Notification No. 6/7/2019-DGTR dated 16.05.2019. The Authority issued the preliminary findings vide notification no., F. No.6/7/2019-DGTR dated 3.10.2019 recommending imposition of provisional anti-dumping duties on imports of the PUC from the subject countries for a period of six months. The ministry of finance vide notification no., 02/2020 – Customs (ADD) dated January 30, 2020 imposed the provisional anti-dumping duty.
3. Thereafter, the Final Findings were issued by the Authority vide Notification No. 6/7/2019-DGTR dated 15.05.2020, recommending the imposition of definitive anti-dumping duties. On the basis of the said recommendation, definitive anti-dumping duties were imposed by the Central Government vide Custom Notification No.21/2020-Customs (ADD) dated 29.07.2020 on the imports of the subject goods, originating in or exported from subject countries. The current anti-dumping duties are in force up to 29.01.2025.
4. On the basis of the duly substantiated application by the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of prima facie evidence submitted by the applicant substantiating the likelihood of dumping and consequent injury to the domestic industry, and in accordance with Rule 23(1B) of the Rules, the Authority initiated the investigation on 30.09.2023 to review the need for continued imposition of the duties in force in respect of the subject goods, originating in or exported from the subject countries, and to examine whether the expiry of existing anti-dumping duty is likely to lead continuation or recurrence of dumping and consequent injury to the domestic industry.

B. PROCEDURE

5. The following procedure has been followed with regard to this investigation:
 - a. The Authority notified the embassies of the subject countries in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Rule 5(5) of the AD Rules.
 - b. The Authority issued a public notice dated September 30, 2022, published in the Gazette of India Extraordinary, initiating the anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject countries.
 - c. The Authority sent a copy of the initiation notification on 20.10.2023, to the embassies of the subject countries in India, the known producers and exporters from the subject countries, the known importers/users of the subject imports and other interested parties, as per the information provided by the applicant. The interested parties were requested to provide relevant information in the form and manner prescribed in the initiation notifications and make their submissions known in writing within the time limits prescribed in the initiation notification.
 - d. The Authority also provided a copy of the non-confidential version of the application filed by the applicant to the known producers/exporters, known importers/users and to the embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the AD Rules, 1995 through its email dated 20.10.2023.
 - e. The embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from their countries to submit their responses to the questionnaire within the time limit prescribed by the initiation notification. The embassies of the subject countries were also sent a copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters along with the names and addresses of the known producers /exporters from the subject countries.
 - f. The Authority sent questionnaires to the following known producers/exporters in the subject country in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:
 - i. Kodak (China) Graphic Communications, China PR
 - ii. Shanghai Strong States Printing Equipment Co., Ltd. , China PR
 - iii. Lucky Huaguang Graphics Co., China
 - iv. Fujifilm Printing Plate (China) Co., Ltd. , China PR
 - v. Mylan Printing Media Corporation
 - vi. Top High Image Corporate
 - vii. Jeil C&P Co., Ltd., Korea RP

- viii. Fujifilm Corporation, Japan
- g. In response to the above notification, the following producers/ exporters from the subject countries have submitted the exporter questionnaire response:
- i. Lucky Huaguang Graphics Co., Ltd
 - ii. Kodak (China) Graphic Communications Company Ltd.
 - iii. Anhui Strong State New Materials Co., Ltd.
 - iv. Huangshan Jinruitai Technology Co., Ltd.
 - v. Zhejiang Jinruitai New Material Co. Ltd.
 - vi. Chongqing Huafeng Di Jet Printing Material Co., Ltd
 - vii. Fujifilm Corporation
 - viii. Fujifilm Printing Plate (China) Co., Ltd.
 - ix. Fujifilm Graphic Solutions Corporation
 - x. Fujifilm (China) Investment Co., Ltd.
 - xi. Eastman Kodak Company
 - xii. Jeil C&P Co. Ltd
- h. The producers/exporters from the subject countries who have not submitted the questionnaire response or have not cooperated in the investigation have been treated as non – cooperative in the investigation.
- i. The Authority also sent questionnaires to the known importers/users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules.
- j. The following importers/users submitted the importer/user questionnaire responses:
- i. Kapoor Imaging Pvt. Ltd.
 - ii. Ganpati Imperial India
 - iii. Fujifilm India Private Limited
 - iv. Kodak India Private Limited (KIPL)
 - v. ART Printing House Pvt. Ltd.
 - vi. CEI Print Pack Pvt Ltd.
 - vii. CEI Print Solutions Pvt. Ltd
 - viii. Exquisite Print and Pack Pvt Ltd
 - ix. Saraswati Print Factory Pvt Ltd.
 - x. Printouch
 - xi. Screen Point Systems
 - xii. Trio Plate System

- xiii. Sri Priyan Graphics
 - xiv. VPR Digital & Cards
 - xv. Blue Star Printers
 - xvi. Sudarsan Graphics Private Limited
 - xvii. Printline Systems - C.T.P BUERO
 - xviii. Maa Images
 - xix. Printline Systems - The Print House
 - xx. Scan Graphic System
 - xxi. Bhagyam Binding Works
 - xxii. Colour Solutions
 - xxiii. Kal Publications Private Limited
 - xxiv. Thomson Press
 - xxv. Nippon Color
- k. Additionally, an association from India, namely, All India Federation of Master Printers (“AIFMP”) participated in the investigation.
- l. On December 1, 2023, the Authority conducted a discussion on the methodology to be adopted for Product Control Numbers (“PCN”) in the subject investigation. The Authority, based on the information submitted by the interested parties, finalized the PCN methodology in the subject investigation *vide* notification dated January 12, 2024. Thereafter, interested parties were provided time until January 31, 2024, to file a response to the questionnaires circulated by the Authority.
- m. The Directorate General of Systems & Data Management (DG Systems) was requested to provide transaction-wise details of the imports of the subject goods for the past injury investigation period and the period of investigation. The same was received by the Authority and considered for the purpose of the present investigation.
- n. In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, 1995 the Authority provided an opportunity to the interested parties for presenting their views orally regarding the subject investigation through a public hearing held on August 19, 2024. The interested parties who presented their views in the oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any. The interested parties were further directed to share the non-confidential version of the written submissions submitted by them with the other interested parties.
- o. The first public hearing was held on August 19, 2024 followed by the written submission and rejoinder of the views expressed orally. However, due to the

appointment of the new Designated Authority, the Authority provided opportunity to the interested parties to present its views orally followed by submissions in writing pursuant to the judgement of the Hon'ble Supreme Court in the matter of 'Automotive Tyre Manufacturers' Association (ATMA) vs. Designated Authority, delivered in Civil Appeal No. 949 of 2006 on 07-01-2011. Accordingly, the Authority held another public hearing on September 12, 2024. The interested parties who presented their views in the 2nd oral hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally, followed by rejoinder submissions, if any. The interested parties were further directed to share the non-confidential version of the written submissions submitted by them with the other interested parties.

- p. The Authority made available the non-confidential version of the submissions made by the various interested parties. A list of all the interested parties was uploaded on the DGTR website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all the other interested parties
- q. The non-injurious price (hereinafter referred to as the 'NIP') has been determined based on the cost of production and reasonable profits of the subject goods in India, based on the information furnished by the Domestic Industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure III to the AD Rules, 1995 so as to ascertain whether anti-dumping duties lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the Domestic Industry.
- r. The Authority, during the course of the investigation, satisfied itself as to the accuracy of the information supplied by the interested parties, which forms the basis of this final findings, to the extent possible and verified the data documents submitted by the domestic industry and the interested parties to the extent considered relevant, practicable and necessary.
- s. The information submitted by the Domestic Industry has been examined and verified during on site-verification as well as table verification to the extent deemed necessary and has been relied upon for the present final findings.
- t. The examination and verification of the information submitted by the cooperating producers/exporters from the subject countries was also carried out to the extent deemed necessary and have been relied upon for the purpose of the present final findings
- u. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is 1st April 2022 to 31st March 2023 (12 months). The injury examination period is from 1st April

2019 - 31st March 2020, 1st April 2020 - 31st March 2021, 1st April 2021 - 31st March 2022, and the POI.

- v. The Authority made available the non-confidential version of the evidence presented by various interested parties on mutual basis in the manner prescribed through Trade Notice no. 10/2018 dated 7th September 2018. The information/submissions provided by the interested parties on a confidential basis were examined concerning the sufficiency of such confidentiality claims. On being satisfied concerning the sufficiency of the confidentiality claims filed by the interested parties, the Authority has considered such information/submissions as confidential. In case of non-acceptance of confidentiality claims, the interested parties were directed to submit the non-confidential version of the same and circulate it to the other interested parties.
- w. Wherever an interested party has refused access to or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the present final findings on the basis of the facts available.
- x. The Authority has considered all the arguments raised and information provided by all the interested parties at this stage, to the extent the same are supported with evidence and considered relevant to the present investigation.
- y. A disclosure statement containing the essential facts of the investigation which have formed the basis of the final findings was issued to the interested parties on 20th September, 2024 and the interested parties were allowed time up to 25th September, 2024 to comment on the same. The comments to disclosure statement received from the interested parties have been considered, to the extent found relevant and non-repetitive, in this final finding notification.
- z. ‘****’ in this final finding represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under Rule 7 of AD Rules, 1995.
- aa. The exchange rate for the POI adopted by the Authority for the subject investigation is 1 US \$= Rs. 81.06.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

C.1 Submissions made by the other interested parties

- 6. The other interested parties have made the following submissions with respect to the product under consideration:

- a. The description of the PUC in the original anti-dumping investigation and the application for the sunset review clearly state that polyester plates are not included within the scope of the PUC. However, as can be seen from the domestic industry's product catalogue, it manufactures large varieties of Polyester-based digital printing plates.
- b. The present investigation is a sunset review, and the scope of the product under consideration remains the same as defined by the Authority in the original investigation.
- c. The product under consideration consists of three types: (i) Thermal plates; (ii) Violet plates; and (iii) CtCP/UV CtP plates. The Authority has classified these three types as different PCNs (Product Control Numbers) based on differences in cost and price.
- d. In the original investigation, interested parties argued that the domestic industry does not produce certain product types: (i) Double Layer CtCP plates; (ii) Negative working UV CtP plates; (iii) Other variants of Process-less Plates (i.e., Violet and UV CtP) on a commercial scale; (iv) Chem-free UV CtP plates on a commercial scale.
- e. The Authority previously considered that if there is commercial demand, and whether TechNova has the capacity to produce these product types. Despite demand for these product types, Technova has not made any sales of these products and is unable to manufacture them. The Authority should critically examine whether these product types were ever produced by the domestic industry.
- f. The products involved are heterogeneous, with different production costs and processes. The price injury should be evaluated at the PCN level rather than applying a broad assessment across product types.
- g. It should also be investigated if Technova's self-imports include these product types, which would indicate that TechNova is importing products it cannot produce. The domestic industry should be required to disclose the types of products being imported and the reasons for importing them, allowing interested parties to make effective comments.
- h. The PUC includes various products, and the Domestic Industry does not produce the full range of the product scope. Instead, it relies on imports for products that it does not manufacture.

C.2 Submissions made on behalf of the Domestic Industry

7. The following submissions have been made on behalf of the Domestic Industry with regards to the product under consideration:
 - a. Digital Plates are used in the printing industry for transferring data as an image (dot patterns or text) onto paper or on non-absorbent substrates like tin sheets, poly films, etc. In the printing process using Digital Offset Printing Plates, the digital workflow enables direct transfer of an image from a ‘computer to the plate’ (CtP) using lasers unlike the analog workflow that requires an intermediary film to transfer the image.
 - b. The PUC is freely importable into India and is not subject to any import restriction.
 - c. Digital Offset Printing Plates are made from high-purity litho-grade aluminium coils coated with a chemical coating. Digital Offset Printing Plates may be either positive (non-exposed area forms image) or negative (exposed area forms image) working plates.
 - d. The coating components, also known as ‘sensitizers’, vary for different types of plates. Based on the coating components and laser type of plate setters, the Digital Offset Printing Plates may be broadly classified into three categories, namely Thermal, Violet and CtCP/UV CtP (Computer-to-Conventional Plate) based on their application.
 - e. All types of Digital Offset Printing Plates, in all dimensions, are covered within the scope of the product under consideration, except waterless CtP plates.
 - f. The description of the subject goods and their use has not undergone any change since the conclusion of the Original anti-dumping Investigation.
 - g. The Authority finalized the product scope after assessing products manufactured by the Domestic Industry, imports of the product, and the end-use and substitutability of domestic and imported products. This being a sunset review, the scope of the product under consideration must be maintained, as was confirmed in the Original anti-dumping Investigation.
 - h. The Digital Offset Printing Plates produced by the Domestic Industry is alike in all respects to the to the imported digital offset printing plates from the subject countries. The end-use, technical characteristics, and physical characteristics of the imported goods are comparable with the PUC produced by the Domestic Industry.
 - i. The Domestic Industry submitted that to the best of their knowledge, there are no known differences between the imported subject goods and the goods produced by the Domestic Industry.

- j. Therefore, the products being imported into India are alike in all respects to the products produced by the Domestic Industry.
- k. The Domestic Industry argues that the issues raised have already been resolved in the original investigation and should not be revisited during the sunset review. The scope of the review is fixed and was finalized by a January 12, 2024 notification, following input from interested parties. No new product specifications or evidence have been provided to support claims of exclusion, so the original scope must be relied upon.
- l. The Domestic Industry can manufacture Double Layer - Thermal (Elite) and Violet plates and has the capacity to produce double-layer UV CtCP plates, as confirmed during the original investigation.
- m. The Domestic Industry manufactures negative working UV CtCP plates, as previously established.
- n. The Domestic Industry clarifies it produces violet chem-free plates but notes that no players in the market, including itself, manufacture violet process-free plates or process-free UV CtCP plates. The Domestic Industry can produce chem-free UV CtP plates, though the costs are significantly higher, leading to low commercial demand in India.
- o. One of the interested party argued that the Domestic Industry has imported products it cannot produce is rejected. TechNova has not imported any of the products in question, and all products imported by TechNova are also produced by the company, making Kapoor's claims baseless.
- p. The scope of the PUC does not contain polyester plates.

C.3 Examination by the Authority

- 8. The product under consideration in the present investigation is Digital Offset Printing Plates.
- 9. This being a sunset review investigation, the scope of the PUC remains the same as that in the original investigation. The PUC in the original investigation was defined as under:

The product under consideration is "Digital Offset Printing Plates". Digital offset printing plates are used in the printing industry to transfer data as an image onto paper or on non-absorbent substrates like tin sheets, poly films, etc. In the printing process using Digital Offset Printing Plates, the digital workflow

enables direct transfer of the image from a 'computer to the plate' (CtP) using lasers, unlike the analog workflow that requires an intermediary film to transfer the image. Digital Plates are made from high-purity litho-grade aluminium coils coated with a chemical coating. Digital Offset Printing Plates may be either positive (non-exposed area forms image) or negative (exposed area forms image) working plates. The range includes plates that require chemicals for processing the plates; and environmentally friendly ones that require no chemicals or water for processing. The coating formulations vary for different types of plates. There are three types of digital offset printing plates, namely,

- i. Thermal Plates;*
- ii. Violet Plates;*
- iii. CtCP/UV CtP Plates.*

The Authority has taken note of post-disclosure comments and holds that all types of Digital Offset Printing Plates in all dimensions and thicknesses are covered within the scope of the product under consideration. However, waterless CtP plates are excluded from the scope of the PUC for reasons elaborated above.

10. The Authority notes that certain interested parties have argued that in the original investigation, the Authority included Double Layer CtCP plates, Negative working UV CtP plates, Other variants of Process-less Plates (i.e., Violet and UV CtP), and Chem-free UV CtP plates within the PUC since the domestic industry demonstrated no commercial demand for these products. However, they should now be excluded from the scope of the PUC, since the domestic industry continues not to produce these products.
11. A meeting on scope of PUC/PCN was held by the Authority on December 1, 2023 wherein no submissions were made by the interested parties with respect to exclusion of products from the scope of the investigation. Pursuant to submissions received from the interested parties the Authority has vide its communication dated January 12, 2024, clarified the scope of the PUC and PCN methodology to be followed for the present investigation as under:

S No	PCN Parameter	Code
1	Computer to Conventional Plates (CtCP) / UV Computer to Plate (UV CtP)	C
2	Thermal Plates	T
3	Violet Plates	V

12. The Authority also notes that the interested parties have failed to provide any evidence to demonstrate that these products are not 'like' domestically produced products. Further, the Authority has examined the issues of exclusions of various types of products from the scope of the investigation in the original investigation, and the interested parties have not made available any new evidence establishing that the applicant does not manufacture any of such products. In view of the same, the Authority does not consider it appropriate to examine these claims of product exclusion made by the interested parties-
13. Rule 2(d) relating to the definition of "like article" specifies that "like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation, or in the absence of such an article, another article having characteristics closely resembling those of the article under investigation.
14. From the above definition of the term "like article", it is clear that the like article has to be identical or alike in all respects to the article under investigation. The scope of the term like article shall also include those articles having closely resembling characteristics to those under investigation in the absence of articles identical or alike in all respects.
15. The Authority notes that there is no known difference in the subject goods produced by the Indian domestic industry and those imported from the subject countries. The two are comparable in terms of physical characteristics, manufacturing process, functions and uses, product specifications, distribution and marketing, and tariff classifications of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers also use the two interchangeably. The Authority holds that the product manufactured by the Applicant constitutes like article to the subject goods being imported into India from the subject countries.

16. With regards to the claims to the heterogeneity of the products covered within the scope of the investigation, the Authority notes that it has determined to follow the PCN methodology to ensure the fair comparison of the heterogeneous products covered within the scope of the investigation.
17. The PUC falls under tariff item 8442.50 of the Customs Tariff Act, 1975. The PUC is also being imported under other customs tariff items, including, 3701.3000, 3704.0090, 3705.1000, 7606.1190, 7606.9190 and 7606.9290. Imports of PUC made under all the various HS codes have been taken into consideration for the purpose of injury assessment. The customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING

D.1 Submissions made by the other interested parties

18. The other interested parties have made the following submissions with respect to the Domestic Industry and Standing:
 - a. The applicant, Technova Imaging Pvt Ltd, acknowledged in its application that they imported the subject goods from both subject and non-subject countries during the POI, despite having anti-dumping protection, but did not disclose the reasons for such imports.
 - b. The indexed data provided by the applicant indicates that these imports from subject countries by the domestic industry constitute about 3% to 4% of the total imports of subject goods from subject countries during the POI. This amounts to approximately 6,09,929 sqm, which is six times more than the total imports of the subject goods from non-subject countries (1,66,592 sqm) and more than the combined imports from Japan, South Korea, and Vietnam.
 - c. Interested parties argue that Technova is ineligible to be considered a "Domestic Industry" under Rule 2(b) because it is a significant and habitual importer of the subject goods from the countries under investigation. This increased substantially during the period of investigation, disqualifying it from being treated as a domestic industry. Several past cases, including *Aluminium Foil from China PR (2017)*, *Flax Yarn from China PR (2018)*, and *Glazed/Unglazed Porcelain/Vitrified Tiles from China PR (2017)*, are cited to support this argument.

- d. Technova's regular imports contradict the claim that such imports are temporary, as noted in previous investigations where the Designated Authority allowed temporary imports to retain core customers. However, current import data shows that Technova has consistently imported subject goods not only during the POI and injury period but also before and after the POI. This pattern challenges the domestic industry's eligibility under Rule 2(b).
- e. Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules stipulates that regular importers of the subject goods cannot be considered a "Domestic Industry." The respondents submit that Technova's imports increased from 100 index points in FY 2019-20 to 354 index points during the POI, further disqualifying it under Rule 2(b).
- f. The Manual of Operating Practices for Trade Remedy Investigations (Para 4.9.20(v)) requires a specific reference from the Director General on the issue of imports by petitioners. The petitioner has not provided any exceptional circumstances for these imports, and the reasons for such imports have been kept confidential.
- g. The Authority must evaluate compliance with Rule 2(b), as regular imports by the applicant, even though claimed to be temporary, contradict its status as a domestic industry. The applicant's substantial imports, both from subject and non-subject countries, raise questions about its eligibility, as similar producers have been disqualified in previous cases like *Soda Ash from Turkey and USA*.
- h. The Federation pointed out that M/s HL Printech Solutions Pvt Ltd, a major importer of subject goods from Chinese companies and a supporter of Technova's application, has not disclosed its imports or its relationship with exporters/importers. This undermines the validity of their support for Technova's application.
- i. The existence of M/s Lastra Niraj Pvt Ltd, an associate company of Technova involved in a similar business, was not disclosed by Technova, affecting the applicant's standing. The Authority must thoroughly examine Lastra Niraj's potential imports and operational linkages with Technova.
- j. The Federation argues that both Technova and HL Printech Solutions should not be considered valid domestic producers under Rule 2(b) due to their import activities, which are substantial and habitual. The Authority is requested to terminate the investigation on these grounds.
- k. Technova's consistent imports are not insignificant, as claimed, and evidence suggests that these imports were regular, occurring during the injury period, POI, and post-POI. The applicant's imports were neither temporary nor made under a duty-free scheme.

- l. During the original investigation, the domestic industry's imports accounted for 7% of total imports, but the Authority treated these as temporary. However, current evidence suggests that the domestic industry remains reliant on imports, particularly from subject countries like China and Japan.
- m. Technova has regularly imported goods from both subject and non-subject countries during the POI, indicating that any decline in domestic production and sales cannot be attributed solely to the subject goods.
- n. The domestic industry is not fully equipped to serve all customers, lacks sufficient technology, and relies on imports to meet demand, which contradicts its claims of being a self-sufficient producer.
- o. The interested parties have alleged that the Petitioner made false claims regarding the import data for 2020-21 and 2021-22. Consequently, they have submitted a dataset which indicates that during 2019-20 and 2020-22, the domestic industry imported a total of 115,873 SQM.
- p. The volumes imported by the Petitioner are far too high to be imported for R&D purposes.

D.2 Submissions made on behalf of the Domestic Industry

19. The following submissions have been made on behalf of the Domestic Industry with regard to the domestic industry:
 - a. Out of total domestic production, the production share of the domestic producer's share is 96%. In view of the same, the domestic producer meets the requisite threshold to constitute domestic industry for the purposes of the present application.
 - b. The domestic producer has clearly demonstrated that it qualifies as "domestic industry" within the meaning of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of anti-dumping duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 ("AD Rules").
 - c. In order to qualify as "domestic industry", the domestic producer's production of the PUC must constitute a major proportion of the eligible domestic production. The domestic producer's production meets the threshold requirement.
 - d. While the domestic producer was constrained to make some imports during the POI, these imports are insignificant when compared to total production of the domestic producer, total imports of PUC into India and subject imports of PUC.

- e. The Domestic Industry has imported the PUC from both subject and non-subject countries due to each of their two plants underwent separate routine maintenance shutdowns.
- f. It may be noted that neither of the plants were shut down at the same time. Consequently, to fulfil its commitments to existing customers, the Domestic Industry imported the PUC as a temporary solution.
- g. Furthermore, Post COVID-19, the PUC witnessed a pent-up demand which is evident from the production and sales of the Domestic Industry during the same period. In order to meet the sudden increase in demand from its existing customers, the Domestic Industry imported a limited quantity of the PUC while paying the applicable duties including anti-dumping duties
- h. The Domestic Industry submits that the imports from the subject countries on account of the above reasons are only 1.8% of its production and 1.2% of the overall demand of the subject goods in the POI period.
- i. The Domestic Industry continues to focus on manufacturing of the subject goods and was constrained to import the PUC as a temporary measure to serve its existing customers. This does not alter the fundamental characteristic of the Domestic Industry's business i.e., manufacturing the PUC and supplying it to its customers.
- j. With regard to the imports from the non-subject countries (i.e., the European Union), the imports have been made from its erstwhile technology partner for the purpose of testing and market seeding.
- k. Since the imports by the domestic producer from the subject countries constitute only 1.8% of its total production of the PUC, 1.2% of the total demand, and 3.5% of the import from subject countries, such low imports could not have conferred any undue benefits to the Applicant.
- l. Indian courts have held that where the principal business of the producer is not importation, it should not be excluded from the scope of domestic industry. A producer who imports a small fraction of its total production, and that too, during production disruptions, should not be considered an importer under Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules.
- m. The Petitioner manufactures the subject goods in India as a predominant activity and possess all the essential characteristics of a manufacturer. The domestic production of the Petitioner accounts for almost 67% of the demand of the subject goods.

- n. The Petitioner is the largest producer of the subject goods accounting for 96% of the total domestic production.
- o. The Petitioner continues to focus on domestic production, continuing to further the Indian government's ambitions of "Make in India" and continues to expand its capabilities to serve the domestic customers.
- p. The Domestic Industry argues that "temporary" imports should not be conflated with "non-recurring." Occasional small imports do not indicate that the industry is a habitual importer or shifting towards trading activities. These imports are driven by short-term needs, and the primary focus remains domestic production.
- q. The Authority has consistently considered domestic producers with minimal imports as eligible for domestic industry status in previous anti-dumping investigations. Examples include cases involving natural mica-based pigments, flax yarn, and caprolactam.
- r. The Domestic Industry confirms that LNPL is its associate company by virtue of TechNova's shareholding in the company. LNPL is a producer of NPUC, and therefore, is not relevant for the purposes of the subject review

D.3 Examination by the Authority

20. Rule 2(b) of the Rules provides as follows:

“domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.

21. The Authority notes that the Application has been filed by M/s. TechNova Imaging Systems (P) Ltd. In addition to TechNova, there is only one other producer of the subject goods namely HL Printech Pvt. Ltd., who has filed a support letter in the said investigation.
22. The Applicant submitted that it is not related to any of the exporters of the PUC from the subject countries or importers of the PUC from the subject countries. However, the

Applicant has submitted that it has imported the PUC from one of the subject countries during the period of investigation.

23. The Authority notes that Rule 2(b) of the AD Rules provides that the domestic producers which are related to the exporters or importers or which themselves are importers of the allegedly dumped goods **may** be excluded from the scope of domestic industry. The usage of the word “may” under Rule 2(b) indicates that producers related to exporters or importers as well as importing producers are not automatically excluded from being part of the domestic industry. The Authority has discretion to determine on the inclusion or exclusion of such producers within the scope of the domestic industry, on a case-to-case basis after making all due considerations in this regard. In particular, the Authority is required to examine if the Applicant has imported the PUC in such substantial volumes and under such conditions which would render the Applicant ineligible as domestic industry under Rule 2(b) of the AD Rules.
24. The Authority has also taken note of the arguments raised by interested parties, which assert that the Applicant’s imports of the subject goods cannot be characterized as ‘temporary,’ given that the Applicant had imported the subject goods during the POI of the original investigation as well. The Domestic Industry (DI), in response, contends that the term ‘temporary’ should not be conflated with ‘non-recurring.’ The Authority notes that occasional imports made by domestic producers, driven by specific and short-term needs such as unexpected demand surges or production disruptions, should not result in the conclusion that the imports are ‘habitual’ or not ‘temporary’ as long as such imports are incidental to its primary role as a domestic manufacturer and do not signify a shift in its business activities toward trading.
25. In this regard, the Authority notes that the details of imports made by the Applicant are as follows:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Imports made by the Applicant from the subject countries	SQ M	***	***	***	***
Production Quantity	SQ M	***	***	***	***
Total Imports	SQ M	1,45,05,33 4	73,67,19 0	86,88,78 5	1,43,03,15 6

Total Demand	SQ M	***	***	***	***
Imports in relation to					
- Production of the Applicant	%	0-1%	NIL	NIL	1-2%
- Demand of the subject goods	%	0-1%	NIL	NIL	1-2%
- Subject Imports	%	1-2%	NIL	NIL	3-4%

26. The Authority notes that the volume of imports of the PUC by the Applicant during the POI are insignificant compared to the total imports, total domestic production or total demand of the country. The volume of imports made by the Applicant in relation to total demand, its domestic sales and production is in the range of 1-2%. The same has been verified from the DG Systems data.
27. It is noted that the Applicant is the largest producer of the subject goods, constituting about 96% of the total domestic production in the country. Therefore, the imports made by the Applicant are consistent with its role as a domestic producer and do not indicate a shift toward trading or habitual importation.
28. With regard to the claims made by the interested parties regarding the Applicant's associate company, Lastra Niraj Private Limited, being engaged in the production and import of the PUC, the Authority notes that Lastra Niraj Private Limited is not engaged in the importation or sales of the PUC. The same has been verified from the DG systems data.
29. With regard to the alleged imports made by HL Printech Solutions Pvt Ltd, who is a supporter in the present review, the Authority notes that the supporter has not participated in the present review after its initiation. However, the Authority analysed the import data and found that there are no imports of PUC made by HL Printech Solutions Pvt Ltd over the injury period. The Authority further notes that HL Printech only constitutes about 4% of the domestic production of the PUC in India. Accordingly, irrespective of its eligibility, the Applicant meets the standing requirements required under law.
30. In view of the above, the Authority holds that the Applicant i.e., TechNova Imaging Systems (P) Ltd. satisfies the requirement of Rule 2(b) of the Rules and considered to be an eligible domestic producer for the purpose of determining domestic industry standing.

31. Based on the information available on record, the Authority notes that the production of the Applicant in the POI is about 96% of the total Indian production and constitutes a major proportion. Accordingly, the application filed by the Applicant satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the AD Rules.

E. CONFIDENTIALITY

E.1 Submissions made by the other interested parties

32. The other interested parties have made the following submissions with respect to the Confidentiality:
- a. The applicant has violated the specific provisions of Trade Notice No. 10/2018 dated 7.09.2018 by claiming excessive confidentiality over various pieces of information.
 - b. The applicant has claimed the following information as confidential, which includes:
 - i. Production process
 - ii. Names of major raw materials
 - iii. Imports made by the Domestic Industry (+/- 5% range)
 - iv. Non-Injurious Price Calculation (+/- 10% range)
 - c. Rule 7 of the Indian Anti-Dumping Rules requires parties providing confidential information to furnish non-confidential summaries or provide reasons why summarization is not possible.
 - d. If the Designated Authority finds that the confidentiality claim is not warranted or the party is unwilling to disclose the information in a generalized form, the Authority may disregard the information.
 - e. Rule 7 emphasizes that not all information submitted confidentially should be treated as such unless supported by valid reasons and accepted by the Authority.
 - f. The applicant is responsible for providing detailed summaries to allow reasonable understanding of the confidential information, enabling other interested parties to respond effectively and assist the Authority in making the correct determinations.
 - g. The Hon'ble CESTAT, in the Vitriified Tiles case, held that information submitted confidentially should not automatically be considered confidential and emphasized the need for transparency.
 - h. The CESTAT ruling laid down guidelines for examining confidentiality claims and stated that there is an obligation for the Authority to require detailed non-confidential summaries from parties to allow a reasonable understanding of the confidential information.

- i. If the request for confidentiality is not warranted, and the party refuses to disclose the information in a generalized or summarized form, the Authority may disregard such information.
- j. The respondents request that the Authority terminate the investigation, as it is without jurisdiction due to the applicant's excessive and unjustified confidentiality claims.

E.2 Submissions made on behalf of the Domestic Industry

33. The domestic industry has made the following submissions with respect to the Confidentiality:
- a. Interested parties have filed questionnaire responses that are grossly deficient, excessively confidential, and does not meet the required standards under Trade Notice 07/2018 dated September 7, 2018.
 - b. The Domestic Industry points out that Kodak China was acquired by Lucky Huaguang in 2019, but Kodak China and its parent company, Eastman Kodak, did not disclose this information in their responses.
 - c. The Petitioner requests that the Authority examine Kodak China's and Lucky Imaging's commercial relationship, the impact on the production, sale, and marketing of the product under consideration (PUC) in India, and whether related parties provided inputs/raw materials.
 - d. The Domestic Industry asks the Authority to reject incomplete questionnaire responses from interested parties.
 - e. Responses filed by interested parties are excessively confidential, lacking meaningful non-confidential summaries, thereby hindering the Petitioner's ability to comment on the data provided.
 - f. Several cases were cited to demonstrate how the Authority has rejected responses from foreign producers when they were found deficient or excessively confidential.

E.3 Examination by the Authority

34. On confidentiality of information, Rule 7 of the Rules reads as follows:

“Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and subrule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as

to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.”

35. The Authority made available non-confidential version of the information provided by - various interested parties to all interested parties through the public file containing non-confidential version of evidence submitted by various interested parties for inspection as per for inspection as per Rule 6(7) of the Rules.

36. The Hon'ble Supreme Court in the case of Reliance Industries V. Designated Authority, had emphasized upon the importance of confidentiality. In para 3 of said decision it was reaffirmed that:

“3. ... confidentiality under Rule 7 is not something which must be automatically assumed. Of course, in such cases there is need for confidentiality as otherwise trade competitors would obtain confidential information which they cannot otherwise get. But whether information supplied is required to be kept confidential has to be considered on a case- to-case basis. It is for the Designated Authority to decide whether a particular material is required to be kept confidential.”

37. Accordingly, the Authority examined the information provided by the domestic industry and other interested parties on a confidential basis for sufficiency of such claims in accordance with Rule 7 of the AD Rules. On being satisfied, the Authority accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential.

Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non confidential version of the information filed on confidential basis.

38. With regard to the confidentiality claims over the name of raw materials, production process, imports by the domestic industry as well as NIP range, the Authority notes that the name of raw material, imports in ranges as well as injury margin in ranges has been disclosed by the domestic industry in its submissions including the petition. With regard to the confidentiality over production process, it is noted that such information is confidential in nature and disclosure of such information may adversely impact the domestic industry.

F. MISCELLANEOUS

F.1 Submissions made by the other interested parties

39. The following miscellaneous submissions have been made by the interested parties:
- a. Technova Imaging Pvt. Ltd. has consistently sought and received trade remedy protections, including anti-dumping and countervailing duties, on Digital Offset Printing Plates from various countries since 2011. The duties have been extended repeatedly, most recently against China, Japan, Korea, Taiwan, and Vietnam, with a countervailing investigation initiated against China and Taiwan in September 2023.
 - b. Despite these long-standing protections, Technova continues to claim injury from dumped and subsidized imports. The Federation argues that this could either indicate fabricated injury claims or internal structural issues within the domestic industry that trade remedies cannot resolve. They assert that it is economically illogical for multiple countries to consistently dump goods into India, given the demand-supply gap.
 - c. Interested parties urge the Authority to critically evaluate Technova's claims of continued injury before recommending an extension of duties. They suggest that the user industry should not bear the burden of additional duties, especially if inefficiencies within the domestic industry are the primary cause. They recommend the immediate termination of duties, asserting there is no real injury or likelihood of its recurrence.
 - d. The interested parties submit that the petitioner, Technova, selectively chooses periods of adverse market trends to file for investigations, using trade remedies as a shield against competition.
 - e. The interested parties request the Authority to conclude both the Anti-Dumping and Countervailing Duty investigations concurrently. This would allow for a comprehensive and integrated assessment of injury margins and ensure consistent and

effective remedies. By handling both anti-dumping and countervailing investigations simultaneously, the Authority can conduct a unified analysis of the cumulative effects of unfair trade practices, avoiding fragmented and inconsistent conclusions. This approach would also enhance efficiency by preventing duplicative efforts and potential discrepancies arising from separate investigations.

- f. The producer/exporter submits that a sunset review can only be initiated when the petitioner provides sufficient evidence of dumping, material injury, and causation. In this case, the information provided by the petitioner is inadequate to justify the investigation under Rule-5(3) of the Rules, relying primarily on estimates and assumptions.
- g. The Authority has appropriately initiated the investigation under Rule 23(IB), which pertains solely to the extension of existing anti-dumping duties, as reflected in the initiation notification. The applicant specifically requested a five-year extension of the current duties on page 56 of its application. As this investigation was initiated under Rule 23(IB), the respondents respectfully request the Authority to limit its scope to the extension of existing duties and not their modification, as modification can only occur under Rule 23(1A), which is not applicable here.
- h. The producer/exporter submits that the domestic industry has refrained from making substantial submissions during the oral hearings, likely because they recognize that the facts do not justify the extension of duties. Their delay in presenting substantial submissions until the rejoinder stage prevented interested parties from properly addressing their claims.
- i. Interested parties emphasize that verification is meant to cross-check existing information, not introduce new evidence. They urge the Authority not to allow the domestic industry to present new information during physical verification, as this would undermine due process and fairness.
- j. In the original investigation, imports under various HS codes (3701.3000, 3704.0090, 3705.1000, 7606.1190, 7606.9190, and 7606.9290) were considered for injury assessment, but in the current investigation, the petitioner has only focused on tariff item 8442.50, potentially skewing the injury analysis by excluding other relevant HS codes. This selective approach may distort the actual import volume and provide an inaccurate assessment of the injury, leading to flawed conclusions. The Authority is urged to scrutinize this selective reporting to ensure the injury assessment reflects the full scope of relevant import data.

- k. The allegation by the petitioner that Fujifilm Group filed a delayed response is incorrect. The Authority granted an extension to Fujifilm Group based on merit, and the response was filed within the prescribed timeline.
- l. The claim that Chinese exporters, including FFPS, China, engage in trade malpractices is unsubstantiated. FFPS operates ethically and follows high standards. Moreover, with NIL duty imposed, there is no incentive for such malpractices. The applicant has provided no evidence to support these allegations.
- m. Kodak requests documentary evidence from TechNova to substantiate claims regarding circumvention. Since no circumvention investigation has been initiated under Rule 25 of the Anti-Dumping Rules, the circumvention allegations lack validity.
- n. In the original anti-dumping investigation, TechNova committed an investment of 400 crores for capacity enhancement. However, no concrete action has been taken by TechNova in this regard.
- o. Chongqing Huafeng Di Jet Printing Material Co., Ltd. and Huangshan Jinruitai Technology Co., Ltd. should be granted individual duty since they commenced production during the injury period.
- p. The applicant has categorically requested the Authority on page no. 56 of its application to “extend the period of imposition of the existing anti-dumping duties for a further period of five years”. Accordingly, the Authority has rightly initiated the investigation in terms of Rule 23(1B) as evidenced from the initiation notification, which is for sunset review investigation and prescribes only for extension of the period of imposition of the existing anti-dumping duties and not modification of the existing duties.
- q. The Domestic Industry has merely requested extension of duty and not requested to determine a common rate of duty for Kodak China and Lucky. In view of the above, they requested the Authority to continue the individual rate of duties for the respective entities as was done in the original investigation.
- r. The Anhui Strong State New Materials Co., Ltd earlier known as Anhui Strong state Printing Materials Co. ltd. in its questionnaire response stated about the change of name of the business name along with the relevant documents. An application of Mid-Term Review was also filed, requesting for change of name.

F.2 Submissions made on behalf of the Domestic Industry

40. The following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry:

- a. Despite the Authority's instruction to highlight new arguments in post-hearing written submissions, most interested parties failed to comply. This forced the Domestic Industry to sift through lengthy submissions within a tight two-day deadline, creating a significant disadvantage. The failure to follow the Authority's directive disrupted the efficiency of the anti-dumping investigation, undermining the time-sensitive nature of the proceedings.
- b. The Kodak Group argued that post-POI data should be considered for examining threat of material injury and likelihood scenarios. However, the Domestic Industry highlighted that Para 5.15 of the Manual of Operating Practices for Trade Remedy Investigations states that post-POI data should be mentioned in the Initiation Notification, which was not done in this case. Thus, considering post-POI data now would be procedurally unfair.
- c. Interested parties argued that the Domestic Industry did not provide sufficient evidence for initiation. The Domestic Industry responded that the review was initiated according to the Anti-Dumping Rules, with any deficiencies in the petition rectified before the Authority initiated the review.
- d. Some parties claimed the Domestic Industry made no oral submissions during the hearing. The Domestic Industry clarified that it did make submissions, relying on its petition for evidence. There is no legal obligation to make oral submissions, and written submissions and rejoinders allow all parties to defend themselves fully.
- e. Despite these challenges, the Domestic Industry has made investments and plans to expand its capacity, contingent on the enforcement of anti-dumping duties. Without continued duty protection, the industry would face renewed competition from dumped imports, threatening its growth and sustainability.
- f. Interested parties claimed the Domestic Industry selectively focused on tariff item 8442.50.20 to distort import data. The Domestic Industry responded that the Authority may verify the data and rely on DG Systems or DGCIS data for the review.

F.3 Examination by the Authority

41. The Authority notes that certain interested parties have argued that the present sunset review has been wrongly initiated since the petition filed by the domestic industry does not contain sufficient evidence as required under Rule 5(3) of the AD Rules. The Authority notes that

the investigation was initiated after satisfying itself of the *prima facie* evidence of dumping, injury and likelihood of recurrence of dumping and injury. During the course of the investigation, the Authority has gathered information and evidence from the interested parties which will form its basis for recommendation in the present sunset review.

42. The Authority notes that the domestic industry has argued that Fujifilm's responses should be rejected since it delayed the filing of a response to the questionnaires. In this regard, the Authority notes that upon its request and demonstration of genuine causes, the Authority granted an extension in deadlines for the Fujifilm group to file a response to the required questionnaires.
43. The Authority notes the concerns raised by interested parties relating to the non-inclusion of certain HS tariff items covered in the scope of the PUC in the original investigation. In this regard, the Authority has examined and relied on import data from DG systems to determine the volume of imports of the subject goods made from the subject countries in India. Import data from DG Systems has been examined for all HS tariff items which were covered in the original investigation and that have been reported by the Applicant in the petition. The import data has been sorted into PUC and Non-PUC based on the product description as well as relevant HS tariff items.
44. Regarding the allegations made by various interested parties that the domestic industry was allowed to submit additional information during the verification, the Authority notes that no additional information was accepted or presented during the verification except for the changes in the data that were rectified during the verification or sought by the Authority.
45. With regard to the contention of various interested parties on the limited submissions made by the domestic industry during the oral hearing, the Authority notes that Rule 6 of the Anti-Dumping Rules incorporates the right to a hearing granted to all interested parties in a quasi-judicial process under the principles of natural justice. The manner in which each party wishes to exercise its right is a matter of discretion. The Authority also notes that since oral submissions are taken on record only when presented in writing by the interested parties, no interested parties are prejudiced by the limited or descriptive oral submissions made by any of the interested parties. The Authority has considered the submissions made by all the interested parties including the domestic industry in writing.

46. With regard to the continuation or enhancement of duties, various interested parties have contended that Rule 23(1B) allows for only continuation of the duties and not enhancement of duties. The Authority notes that Rule 23(1B) of the AD Rules does not limit the Authority to merely continue the duties but allows for enhancement or vary the duties also if it comes to the conclusion the dumping and consequently the injury to domestic industry is likely to recur. The Authority further notes that in *Basf South East Asia Pte. Ltd. v. Designated Authority*, the Hon'ble CESTAT found that “*the Government has the power to vary the anti-dumping duty while continuing the same on conclusion of a sunset review under Section 9A(5) of the CTA. However, there is no warrant under the said Section 9A(5) to determine the current dumping margin and limit the anti-dumping duty to such limit as under Section 9A(1).*”
47. Various interested parties have averred that the Authority should investigate both the anti-dumping and parallelly ongoing countervailing duty (CVD) investigation together to avoid duplicity of efforts, comprehensive, holistic and integrated view of the injury caused to the domestic industry. In this regard, the Authority notes that the product scope of both the investigations is same and there is degree of overlap in the subject countries involved in both the investigations. While both the investigations are different and should be assessed on its merits, the Authority will appropriately take into consideration the facts presented by the interested parties while making its recommendations in both the investigations. However, the Authority notes that, as independent investigations with separate timelines governed by their respective rules, the Authority is fully entitled to conclude each investigation at different times, in accordance with the procedural requirements.
48. With regard to the contention of various interested parties that the petition filed by the domestic industry does not contain sufficient evidence under Rule 5(3) of the AD Rules, the Authority notes that the investigation was initiated after satisfying itself of the *prima facie* evidence of dumping, injury and likelihood of recurrence of dumping and injury. During the course of the investigation, the Authority has gathered information and evidence from the interested parties which will form its basis for recommendation in the present investigation.
49. Various interested parties have averred that the Applicant has enjoyed the protection from imports since 2011 despite that it continues to suffer from injury. Further, interested parties have argued that the claimed injury could be on account of internal structural problems or fabricated claims. The legal standard requires an assessment of the likelihood of

continuation or recurrence of dumping and injury, irrespective of the duration of protection. The Authority has relied on verified information for its assessment of injury caused to the domestic industry. The Authority further emphasizes that the purpose of anti-dumping duties is to only create a level playing field and mitigate the injurious effects of unfairly priced imports on the domestic industry. These duties are not intended to provide undue protection to the domestic industry or to disadvantage any other industry.

50. Interested parties have also argued that domestic industry allegedly selects adverse market periods to file for investigations, which suggests an attempt to shield itself from competition. In this regard, the Authority notes that the domestic industry filed for the initiation of the present sunset review in line with the timelines prescribed by the Authority with regard to the filing of a petition for the initiation of a sunset review.
51. The Authority notes that Kodak and Fujifilm have argued that the domestic industry has provided no evidence to demonstrate the evasion/circumvention of duties by Chinese exporters. They have also argued any circumvention should only be addressed through an investigation initiated under Rule 25 of the AD Rules. The Authority notes that the domestic industry has not requested the Authority to examine the alleged circumvention/evasion of duties, and has instead, approached the appropriate forum to register its complaints. The Authority has examined these claims in further detail in the relevant section of the final findings.
52. With regard to the submissions of various interested parties on the investment for expansion of capacities, the domestic industry submitted that it has purchased the plant but could not install the same due to effects of the COVID. The Authority notes that the domestic industry has purchased the machinery for capacity expansion which form part of their capital WIP in the financial statements.
53. The authority notes that Anhui Strong State New Materials Co., Ltd had filed an application for Mid Term Review requesting for change of their business name from Anhui Strong state Printing Materials Co. Ltd to Anhui Strong State New Materials Co., Ltd. It was decided that the said Mid-Term review application should be dealt with in the ongoing sun set review investigation. The said exporter in the current investigation filed its questionnaire response mentioning the change of its business name enclosing the relevant documents. The Authority after examining the documents placed on record regarding the change of it's

business name, noted the new name as Anhui Strong State New Materials Co., Ltd in place of Anhui Strong state Printing Materials Co. Ltd.

G. MARKET ECONOMY TREATMENT (MET), NORMAL VALUE, EXPORT PRICE & DETERMINATION OF DUMPING MARGIN

G.1 Submissions made by the other interested parties

54. Views of other interested parties with regards to normal value, export price and dumping margin, are as follows

- a. The producer/exporter submits that China's Accession Protocol to the WTO expired on 11th December 2016, and the use of the "surrogate country" practice in anti-dumping actions lacks a legal basis since that date.
- b. The producer/exporter requests that the Designated Authority not use the "surrogate country" methodology to calculate the normal value for this case, regardless of whether China is treated as a market economy.
- c. The interpretation of Article 15(a) and 15(b) of China's Accession Protocol, as clarified in the WTO Appellate Body's "Fastener case," supports China's automatic attainment of market economy status after the expiry of Article 15.
- d. The international law principle of "Pacta sunt servanda" requires signatories to uphold their treaty obligations, including the obligation not to invoke domestic laws to evade international commitments.
- e. China has fulfilled its obligations under the WTO framework and should be granted the corresponding rights, including recognition of its market economy status.
- f. India, as a WTO member, is obligated to recognize China's market economy status after 11th December 2016 and should amend its domestic regulations to stop using the "surrogate country" approach in anti-dumping investigations against China.
- g. Section 15 of China's Accession Protocol states that after 15 years from China's WTO accession, China must be treated like any other WTO member in anti-dumping investigations.
- h. The "surrogate country" methodology expired after 11th December 2016, and normal value for imports from China must now be determined based on Chinese prices and costs.
- i. The US and EU had previously supported the understanding that the "surrogate country" approach would expire after 15 years from China's accession to the WTO.

- j. After 11th December 2016, the classification of China as a non-market economy (NME) under domestic law is irrelevant for determining normal value in anti-dumping investigations.
- k. The WTO Appellate Body in EC – Fasteners confirmed that the provisions of Section 15(a) expire 15 years after China's accession, establishing that WTO members must calculate normal value for Chinese imports using Chinese prices and costs.
- l. Any continuation of the "surrogate country" practice after 11th December 2016 would be inconsistent with the WTO's Anti-Dumping Agreement and India's WTO obligations.
- m. It is also relevant to note that most of Jeil's production facilities were destroyed by a fire on August 26, 2021. After the fire, Jeil was unable to produce the PUC until new production facilities were installed, with production restarting in January 2023. The Hon'ble Authority is requested to adjust the cost incurred until 2022 in the cost of the PUC, as this was an infrequent occurrence.

G.2 Submissions made on behalf of the Domestic Industry

55. The following submissions have been made on behalf of the Domestic Industry with regard to the product under consideration:
- a. Sub-paragraph (2) of paragraph 8, Annexure I of the AD Rules stipulates that a country shall be considered as a non-market economy ("NME") in an anti-dumping investigation if the country has been treated as an NME by the Authority in three (3) years preceding the investigation period. It may be noted that unless the producers/exporters cooperating in the investigation produce sufficient evidence establishing that it operates under market economy principles, the country ought to continue to be treated as an NME by the Authority.
 - b. The Authority in its Final Findings Notification No. F. No.6/4/2021-DGTR dated March 30, 2022, issued in Anti-dumping Investigation concerning imports of Certain Rubber Chemicals viz., TDQ originating in or exported from China PR, European Union and Russia, PVI originating in or exported from China PR, and CBS originating in or exported from China PR and European Union" and Final Findings Notification No. F. No.6/3/2021-DGTR dated March 29, 2022, issued in "Anti-dumping investigation concerning imports of Fluoro Backsheet originating in or exported from China PR has treated China PR as an NME.
 - c. Accordingly, it has calculated the normal value for the producers/exporters from China PR as per paragraphs 7 and 8 of Annexure 1 of AD Rules.

- d. The Authority must continue to treat producers/exporters operating in China PR as operating under NME principles unless established otherwise by the said producers/exporters filing the relevant information.
- e. Some interested parties claim that China should be granted market economy status since its Accession Protocol expired on December 11, 2016. However, the Domestic Industry argues that this interpretation is incorrect, citing Section 15 of the Protocol, which outlines three distinct timelines and conditions.
- f. China can only be treated as a market economy if it proves so under the national law of the importing country.
- g. Section 15(a)(ii) reiterates existing provisions under the second Ad Note of Article VI of GATT, allowing alternative price comparison methods. Article 2.7 of the Anti-Dumping Agreement supports this, meaning there is no obligation for India to consider China a market economy after 2016.
- h. The Authority has confirmed in prior investigations, such as the “Untreated Fumed Silica” and “Vinyl Tiles” cases, that China remains an NME unless proven otherwise. Indian law also states that a country will continue to be treated as an NME if classified as such for the previous three years, unless producers provide evidence of market economy conditions.
- i. Major jurisdictions like the European Union and the United States continue to treat China as an NME in trade remedial investigations. China's requests for WTO panel rulings on its NME status in the EU and US have not resulted in favorable outcomes for China.
- j. In the current investigation, no Chinese producers or exporters have submitted a request for Market Economy Treatment. Therefore, there is no evidence to prove that Chinese producers of the PUC operate under market economy principles.
- k. Based on these factors, the Domestic Industry urges the Authority to continue treating Chinese producers/exporters as operating under NME principles and to rely on the constructed normal value based on the Domestic Industry's cost of production, adjusted for relevant expenses and reasonable profit.
- l. Jeil has claimed certain adjustments to its costs on account of its plant being un-operational between 2021 to January 2023. In this regard, the Domestic Industry requests the Authority to kindly calculate Jeil's dumping margin in accordance with the principles laid out in Annexure I of the Anti-Dumping Rules.

G.3 Examination by the Authority

Normal value for China PR

56. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows: Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

(a) In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following rules:

(i) If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;

(ii) The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.

(b) In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing

terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.

- (c) *The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.*
- (d) *Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provision of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."*

57. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a) (ii) have expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO, read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession Protocol require the criterion stipulated in Para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status.

58. As none of the producers from China PR have filed a questionnaire response, the normal value has been determined in accordance with para 7 of Annexure I to the Rules which read as under:

"7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India, or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated the Authority in a reasonable manner [keeping in view the

level of development of the country concerned and the product in question and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of the selection. Account shall also be taken within time limits; where appropriate, of the investigation if any made in similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.

8. (1) *The term "non-market economy country" means any country which the designated the Authority determines ds not operating on market principles of cost or pricing structures, so that sales of merchandise in such country do not reflect the fair value of the merchandise, in accordance with the criteria specified in subparagraph (3).*

(2) There shall be a presumption that any country that has been determined to be, or has been treated as, a non-market economy country for purposes of an antidumping investigation by the designated the Authority or by the competent the Authority of any WTO member country during the three-year period preceding the investigation is a non-market economy country. Provided, however, that the non- market economy country or the concerned firms from such country may rebut such d presumption by providing information and evidence to the designated the Authority that establishes that such country is not a non-market economy country on the basis of the criteria specified in sub-paragraph (3).

(3) The designated the Authority shall consider in each case the following criteria as to whether: (a) the decisions of the concerned firms in such country regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment, are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values; (b) the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in

relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment in lieu of compensation of debts; (c) such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms, and (d) the exchange rate conversions are carried out at the market rate. Provided, however, that where it is shown by sufficient evidence in writing on the basis of the criteria specified in this paragraph that market conditions prevail for one or more such firms subject to anti-dumping investigations, the designated the Authority may apply the principles set out in paragraphs 1 to 6 instead of the principles set out in paragraph 7 and in this paragraph.

(4) Notwithstanding, anything contained in sub-paragraph (2), the designated the Authority may treat such country as market economy country which, on the basis of the latest detailed evaluation of relevant criteria, which includes the criteria specified in sub paragraph (3), has been, by publication of such evaluation in a public document, treated or determined to be treated as a market economy country for the purposes of anti-dumping investigations, by a country which is a Member of the World Trade Organization

59. Para 7 lays down hierarchy for determination of normal value and provides that normal value shall be determined on the basis of price or constructed value in a market economy third country, or the price from such a third country to any other country, including India, or where it is not possible, on any reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like article, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. Thus, the Authority notes that the normal value is required to be determined having regard to the various sequential alternatives provided under Annexure-I.

60. It is to be noted that no information/evidence has been provided by the parties for the construction of the normal value on the basis of the first and second methods. In the absence of the above information/evidence, it is not possible for the Authority to determine normal value on the basis of the first or second method. Therefore, the Authority has decided to construct normal value based on the third method, i.e., on any other reasonable basis including the price actually paid or payable in India, for each quarter of the period of

investigation. The Authority has constructed the normal value on the basis of the price paid or payable in India.

Export Price for China PR

Kodak (China) Graphic Communications Company Ltd. (“Kodak China”), Eastman Kodak Company and Kodak India Private Limited

61. Kodak China has exported *** SQM of the product under consideration to India. Out of the above-mentioned exports *** SQM of PUC is exported through Eastman Kodak Company, a related trader who have further exported to Kodak India Private Limited. The producer has claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, inland transportation, port and other expenses, credit cost and packing cost. The Authority has accepted the adjustments claimed by producer after due examination. The net export price so determined is shown in the table below.

Lucky Huaguang Graphics Co

62. Lucky Huaguang Graphics Co has exported *** SQM of the product under consideration to India through unrelated importer. Out of the above-mentioned exports *** SQM of PUC is exported through Kodak (China) Graphic Communications Company Ltd. The producer has claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, inland transportation, port and other expenses, credit cost and bank charges. The Authority has accepted the adjustments claimed by producer after due examination. The net export price so determined is shown in the table below.

Anhui Strong State New Materials Co., Ltd.

63. The producer has reported *** SQM as exports of the product under consideration to India during the period of investigation. The producer has claimed that it has directly exported the product to India and no other related/unrelated party is involved in the export of the product under consideration. The producer has claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, inland transportation, commission, port and other expenses, bank charges and credit cost. The Authority has accepted the adjustments claimed by producer after due examination. The net export price so determined is shown in the table below.

Fujifilm Printing Plate (China) Co., Ltd. (FFPS), Fujifilm Corporation (FTYO) and Fujifilm India Private Limited

64. The producer has exported *** SQM product under consideration to India during the period of investigation through Fujifilm Corporation (FTYO) a related trader who have further exported to Fujifilm India Pvt. Ltd., a related importer, who have sold in Indian market. The producer and the exporter have claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, inland transportation, and credit cost. The Authority has accepted the adjustments claimed by the producer after due examination. The net export price so determined is shown in the table below.

Huangshan Jinruitai Technology Co., Ltd and Zhejiang Jinruitai New Material Co., Ltd

65. The producer has reported *** SQM as exports of the product under consideration to India during the period of investigation. The producer has claimed that it has directly exported the product to India and no other related/unrelated party is involved in the export of the product under consideration. The producer has claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, inland transportation, port and other expenses, bank charges and credit cost. The Authority has accepted the adjustments claimed by producer after due examination. The net export price so determined is shown in the table below.

Chongqing Huafeng Di Jet Printing Material Co., Ltd

66. The producer has reported *** SQM as exports of the product under consideration to India during the period of investigation. The producer has claimed that it has directly exported the product to India and no other related/unrelated party is involved in the export of the product under consideration. The producer has claimed adjustments on account of inland freight, handling charge, bank charges and credit cost. The Authority has accepted the adjustments claimed by producer after due examination. The net export price so determined is shown in the table below.

Export price for all non-cooperative producers/exporters from China PR

67. The export price for other non-cooperative producers/exporters from China PR has been determined based on the facts available in terms of Rule 6(8) of the Rules

Normal value for Korea RP

Jeil C&P Co. Ltd.

68. The producer has reported domestic sales of *** SQM in the period of investigation. The producer has claimed that all domestic sales are to unrelated parties. The producer has

claimed adjustments on account of warehouse storage fee, inland transportation, credit cost and free goods. The Authority has carried out ordinary course of trade (“OCT”) test. The Authority notes that ***% of the total domestic sales were found to be loss making. Therefore, for the purpose of determination of normal value the Authority disregards the domestic sales as the basis for normal value. Accordingly, the Authority calculated the normal value on the basis of cost of production of the producer along with the reasonable profit of 5%.

Normal Value for other producers/exporters in Korea RP

69. The normal value for all other non-cooperating producers and exporters of Korea RP has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Export Price for Korea RP

Jeil C&P Co. Ltd.

70. The producer has reported *** SQM as exports of the product under consideration to India during the period of investigation. The producer has claimed that it has directly exported the product to India and no other related/unrelated party is involved in the export of the product under consideration. The producer has claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, inland transportation, brokerage, port and other expenses, bank charges, courier charge, credit cost and duty drawback. The Authority has accepted the adjustments claimed by producer after due examination. The net export price so determined is shown in the table below.

Export price for all non-cooperative producers/exporters from Korea RP

71. The export price for other non-cooperative producers / exporters from Korea RP has been determined based on the best available in terms of Rule 6(8) of the Rules.

Normal value for Japan

Fujifilm Graphic Solutions Corporation, Fujifilm Corporation and Fujifilm India Private Limited

72. The Fujifilm Corporation has reported domestic sales of *** SQM in the period of investigation. The producer has claimed that all domestic sales are to the related party i.e. Fujifilm Graphic Solutions Corporation. The producer has claimed adjustments on account

of insurance and inland transportation. The Authority has carried out ordinary course of trade (“OCT”) test. The Authority notes that *** % of the total domestic sales for violet plates were found to be loss making. Therefore, for the purpose of determination of normal value the Authority disregarded the domestic sales as the basis for normal value and calculated the normal value for violet plates on the basis of cost of production of the producer along with the reasonable profit of 5%. With regard to calculation of the normal value for thermal plates all the profit making transaction are considered. The net export price so determined is shown in the table below.

73. The ex-factory normal value so determined has been mentioned in the dumping margin table below.

Normal Value for other producers/exporters in Japan

74. The normal value for all other non-cooperating producers and exporters of Japan has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Export Price for Japan

Fujifilm Graphic Solutions Corporation, Fujifilm Corporation and Fujifilm India Private Limited

75. The producer has exported *** SQM of the product under consideration to India during the period of investigation through Fujifilm India Private Limited a related trader, who have sold in Indian market to unrelated customers. The producer and the exporter have claimed adjustments on account of ocean freight, insurance, inland transportation, and port and other related expenses. The Authority has accepted the adjustments claimed by the producer after due examination. The net export price so determined is shown in the table below

Export price for all non-cooperative producers/exporters from Japan

76. The export price for other non-cooperative producers / exporters from Japan has been determined based on the best available in terms of Rule 6(8) of the Rules.

Normal Value for other producers/exporters in Taiwan and Vietnam

77. As none of producers/exporters from these two countries, have submitted their responses, the normal value for all non-cooperating producers and exporters of Taiwan and Vietnam has been determined based on facts available and the same is mentioned in the dumping margin table below.

Export price for all non-cooperative producers/exporters from Taiwan and Vietnam

78. The export price for other non-cooperative producers / exporters from Taiwan and Vietnam has been determined based on the best available in terms of Rule 6(8) of the Rules.

Dumping Margin

79. The normal value, export price and dumping margin in the present investigation is determined on a quarterly basis and is as follows:

Dumping Margin Table

SN	Particular	Normal value	Net export price	Dumping Margin	Dumping Margin	Range
		USD/SQM	USD/SQM	USD/SQM	%	%
1	China PR					
a	Lucky Huaguang Graphics Co. Ltd.	***	***	***	***	40-50
b	Kodak China Graphic Communications Co. Ltd.	***	***	***	***	20-30
c	Fujifilm Printing Plate (China) Co. Ltd.	***	***	***	***	20-30
d	Anhui Strong State New Materials Co., Ltd.	***	***	***	***	30-40
e	Huangshan Jinruitai Technology Co., Ltd.	***	***	***	***	30-40
f	Chongqing Huafeng Di Jet Printing Material Co., Ltd	***	***	***	***	50-60
g	Any other	***	***	***	***	50-60
2	Korea RP					
a	Jeil C&P Co. Ltd.	***	***	***	***	80-90
b	Any other	***	***	***	***	90-100
3	Japan					
a	Fujifilm Corporation	***	***	***	***	100-110
b	Any other	***	***	***	***	110-120
4	Taiwan					
a	All	***	***	***	***	50-60
5	Vietnam					
a	All	***	***	***	***	50-60

H. ASSESSMENT OF MATERIAL INJURY AND EXAMINATION OF CAUSAL LINK**H.1 Submissions made by the other interested parties**

80. The other interested parties have made the following submissions with regard to injury and causal link:

- a. The producer/exporter submits that the Indian printing plates market has an annual demand of 48 million square meters, while domestic production fulfills only 50% of this demand, creating a heavy reliance on imports to meet the remaining 50%.
- b. Imports from subject countries declined by 5% from the base year (2019-20) to the POI. Technova's own imports from subject countries constituted around 3-4%, further indicating that imports are not driving injury.
- c. During the POI, import volumes normalized after a decline during the pandemic years (2020-21 and 2021-22). The producer/exporter requests these pandemic years be excluded from analysis, with 2019-20 used as the base year for comparison.
- d. The producer/exporter contends that any increase in imports during the POI should not be seen as a genuine rise but rather as a return to pre-pandemic levels.
- e. The significant demand-supply gap in India allows exporters considerable leverage over pricing, making it unlikely that all exporters are engaging in dumping or that subsidies are specifically targeted at the Indian market.
- f. Import prices from China and Japan increased significantly during the POI, while the landed price of imports rose faster than the domestic selling price. For instance, from 2019-20 to 2022-23, the landed price from China rose from Rs.217/SQM (index 100) to Rs. 311/SQM (index 145), while domestic prices only increased from index 100 to 133.
- g. Price undercutting is negligible, as landed prices with anti-dumping duties (ADD) are higher than domestic prices. The producer/exporter argues that there is no price effect from imports that could negatively impact the domestic industry.
- h. The price undercutting and injury margins are within the same range, showing that imports are not causing significant harm. If the Net Sales Realization (NSR) and Non-Injurious Price (NIP) are equal, this suggests import pricing is not detrimental.
- i. The domestic industry's claim that imports undercut their prices is contradicted by the rising landed price of imports, which has outpaced domestic price increases.
- j. Given the price increase of imports by more than 43% and the domestic price increase of only 32%, the industry's claims of undercutting appear unfounded.

- k. The producer/exporter submits that price injury should be evaluated at the Product Control Number (PCN) level to get a more granular assessment, rather than applying a broad assessment across product types.
- l. CRISIL reports show a strong financial position for Technova, with a 35% year-on-year revenue growth in fiscal 2023 and an improved outlook from "Stable" to "Positive" in 2024.
- m. Technova's revenue growth of 38% in fiscal 2022 was supported by market reopening post-COVID, with expectations for further improvement due to stabilized commodity prices and pricing flexibility.
- n. Technova enjoys a diversified customer base, strong cash accruals, low leverage, and high interest coverage, contradicting claims of injury.
- o. Despite consistently raising its NSR, the domestic industry claims losses, which respondents attribute to mismanagement or internal inefficiencies rather than imports.
- p. The Federation asserts that Technova is using trade remedial measures to improve margins rather than addressing unfair trade practices. The company's financial data contradicts its claims of material injury.
- q. Technova's strong financial performance, as reflected in CRISIL reports, suggests that its claims of likely injury are exaggerated, and the purpose of continued protection may be to enhance profit margins.
- r. The respondents argue that, despite increasing profitability and financial stability, the domestic industry has not expanded its capacity or addressed production issues, leading to continued reliance on imports.
- s. Domestic production only fulfills about 50% of the total market demand for printing plates, and the domestic industry has not expanded its capacity despite claims of capacity expansion plans.
- t. The producer/exporter notes that domestic production of PUC increased significantly during the POI compared to prior years, rising from 68 index points in FY 2020-21 to 93 index points during the POI. This shows the domestic industry is capable of improving production without relying solely on trade protections.
- u. Productivity per employee increased during the POI, rising from 68 index points in FY 2020-21 to 94 index points during the POI, indicating operational efficiency.
- v. Inventory levels for the domestic industry declined significantly by around 45% during the POI, further contradicting claims of injury.

- w. Despite claims of expanding capacity, the domestic industry has not sufficiently scaled production to meet domestic demand, exacerbating the reliance on imports.
- x. The respondents argue that the 22% Return on Capital Employed (ROCE) used by the DGTR in calculating the Non-Injurious Price (NIP) is inflated and does not reflect current market realities, such as lower interest and corporate tax rates.
- y. CESTAT rulings have raised concerns about the reasonableness of the 22% ROCE, suggesting that actual profits earned during non-dumping periods should be used to calculate NIP.
- z. The EU follows a practice of determining reasonable returns based on profits earned during non-dumping periods, which the DGTR should consider adopting.
- aa. The producer/exporter submits that applying a uniform 22% ROCE on both debt and net worth components of capital employed results in excessive profit margins for the domestic industry, distorting injury and price underselling calculations.
- bb. There are discrepancies in the import data presented by the applicant, particularly regarding volumes from China, which distorts the injury claims. The producer/exporter requests that Technova's own imports be excluded from overall import volumes to provide a more accurate analysis.
- cc. The domestic industry's claim of circumvention through non-subject countries is unsubstantiated, as imports from non-subject countries remain de minimis.
- dd. The domestic industry contends that NIL duty imports are causing injury, but respondents argue that these imports are non-injurious based on the final findings.
- ee. The domestic industry claims increased production costs, but declining aluminum prices (a major component of production) contradict this claim.
- ff. The Federation argues that the domestic industry's inability to justify losses despite increasing NSR and declining costs suggests internal inefficiencies or mismanagement, not import-related injury.
- gg. It has also been alleged that the Petitioner benefits from distorted prices from China since it itself sources approximately 60-70% of its raw aluminium from China, with the remaining coming from other regions. Furthermore, the prices of import of raw material from China are lower than EU.
- hh. The comparison between the domestic industry's selling price and the landed price of imports is inappropriate because the domestic price includes considerable selling and distribution costs, unlike the imports.

- ii. The Importer has alleged that the Petitioner has failed to address why its cost of sales has not decreased during the Period of Investigation (POI) compared to the previous year, despite being linked to LME prices.
- jj. The user argues that the petitioner's claimed losses are inflated, as evidenced by economic factors highlighted in credit agency reports.
- kk. TechNova has devised a strategy of not increasing the price despite anti-dumping duty on imports. As a result, the duty will continue to remain ineffective in the future as well.
- ll. The injury, if any, is due to internal competition, notably from a new producer, H.L. Printech Solutions Pvt. Ltd., whose production increased by 3.3 times during the POI.
- mm. A 22% decline in the applicant's export sales during the POI increased fixed costs, contributing to any potential injury.
- nn. The applicant's inventory declined by around 45% in the POI compared to the base year, indicating no injury or likelihood of recurrence.
- oo. The applicant's productivity per employee increased significantly from 68 index points in FY 2020-21 to 94 index points during the POI.
- pp. The applicant's PUC production significantly increased during the POI compared to the preceding two years. The PUC production increased from 68 index points in FY 2020-21 to 93 index points during POI.
- qq. Kodak submits that the product is heterogeneous and inter-se non-substitutable, owing to differences in the cost of production, production process, and machine-specific end-use. Kodak requests the Authority to undertake price injury on the weighted average basis i.e. PCN level.
- rr. TechNova has reported significant losses for the product under consideration (PUC) despite it contributing over 70% of overall revenue, raising concerns that expenses may have been disproportionately allocated to the PUC, inflating losses and profits for other products.
- ss. Technova continues with PS plates infrastructural costs. Further, the company continues to incur all the fixed costs Technova had been incurring at that time. Since the company continues to incur those fixed costs, it is obvious that all those fixed costs are being charged to digital plates now thus resulting in increase in cost of production of digital plates.
- tt. It is submitted that the PUC production of the applicant industry significantly increased in the period of investigation (POI) as compared to the preceding two years.

- It may be noted that the PUC production of the applicant increased from 68 index points in FY 2020-21 to 93 index points during POI.
- uu. The applicant's productivity per employee increased significantly from 68 index points in FY 2020-21 to 94 index points during the POI.
 - vv. The applicant's inventory declined by around 45% in the POI compared to the base year, indicating no injury or likelihood of recurrence.
 - ww. The net sales realization (NSR) of the applicant is higher than the non-injurious price (NIP), suggesting no injury or likelihood of injury continuation.
 - xx. A 22% decline in the applicant's export sales during the POI increased fixed costs, contributing to any potential injury.
 - yy. The Authority must also examine the following: (i) Whether TechNova's raw material prices are comparable with global prices or the prices were influenced by long-term contracts entered by the company when the aluminium prices peaked. The Authority is requested to undertake a re-evaluation of inventory in case of inventory loss incurred due to long-term contracts (ii) Consider the monthly aluminium procurement price for computation of non-injurious price, cost of production, and other economic parameters (iii) Compare aluminium prices reflected in the cost of production for different PCNs at each plant level.
 - zz. As per Section 14 of the Customs Act and the judgment of the Supreme Court, the loading, unloading, and handling charges are an indispensable part of the assessable value. Therefore, these charges paid by Kodak India Pvt. Ltd. should be included for computation of the landed value of the goods. In the original investigation, the DGTR did not include handling charges for computing landed value since the interested parties had reported notional handling charges as against the actual handling charges. However, KIPL in the present investigation has provided the actual loading/unloading/handling charges and the same should be included in the landed value.

H.2 Submissions made by the Domestic Industry

81. The domestic industry has made the following submissions with regard to injury and causal link:
 - a. Rule 23(3) of the Anti-Dumping Rules states that Rule 11 of the Anti-Dumping Rules applies, ~~as is,~~ to a sunset review, for the purposes of determining the material injury caused to a domestic industry.

- b. In order to determine the impact of imports, the Domestic Industry has provided relevant information on volume injury, price injury, and performance on economic parameters for the PUC.
- c. The Domestic Industry also clarifies that the Authority has duly verified the relevant information regarding injury and the profitability of the company with regard to the PUC.
- d. The volume of imports from the base year to the POI has seen a slight decline. This decrease can be attributed to the anti-dumping duties that have deterred imports from the subject countries to a certain degree, particularly from countries other than China PR and Taiwan. The Domestic Industry asserts that while imports from other countries have decreased, imports from China PR and Taiwan have increased during the injury period.
- e. Import levels during the POI have shown a significant increase when compared to the previous year, specifically in FY 2021-22.
- f. The Domestic Industry submits that the imports of the subject goods in relation to the Domestic Industry's production have remained the same in the POI as compared to the base year. The imports in relation to production did not witness any decline despite anti-dumping duties in place.
- g. Subject imports in relation to the demand have remained the same in the POI as compared to the base year. However, the share of imports from China PR has increased from 31% in the base year to 33% in the POI.
- h. It may be noted that there is a significant increase in the subject imports in relation to both domestic production and demand in the POI, as compared to the previous year, i.e., 2021-22.
- i. It is interesting to note that the imports of the subject goods from China PR in relation to the production have increased compared to the base year. The imports from China PR were about 46% of the Domestic Industry's production in the year 2019-20, which has increased to 49% in the POI.
- j. Imports from the subject countries are coming at prices below the domestic selling price of the Domestic Industry, thus heavily undercutting its selling price and injuring the Domestic Industry. These declining prices have directly led to increased losses.
- k. The imports are coming into India at a much lower price compared to the non-injurious price, and are therefore, causing severe and material injury to the Domestic

Industry. Such low-priced imports have adversely affected the performance of the Domestic Industry by preventing it from achieving a fair selling price.

- l. Price suppression is the inability of the Domestic Industry to reflect the impact of its change in the cost to its sales price. Price suppression is a delta between the change in cost vis-à-vis changes in the selling prices of the Domestic Industry in the domestic market.
- m. The cost to make and sell has increased substantially for the Domestic Industry, i.e., by 41 indexed points in the POI compared to the base year 2019-20. During the same period, the Domestic Industry could not increase the selling price of the PUC commensurately with the increase in its cost, on account of imports from the subject countries. Further, the price suppression increased substantially in the POI on account of dumped imports.
- n. the market share of the imports from China PR has increased from 31% in the base year to 33% in the POI, and by 12% in the POI as compared to the previous year.
- o. The market share of the Domestic Industry has decreased by 9% in the POI as compared to the previous year despite a substantial rise in the demand of the subject goods.
- p. The market share of the Domestic Industry has also witnessed a decrease in the POI as compared to the base year.
- q. The market share of the subject countries other than China PR and Taiwan has declined, mainly on account of the imposition of anti-dumping duties.
- r. The domestic sales of the Domestic Industry declined at a much faster pace compared to the decline in the production of the PUC. This is clearly on account of the continued dumped imports from the subject countries, particularly from China PR.
- s. The domestic sales of the Domestic Industry declined despite a substantial rise in the demand for the subject goods.
- t. The production and capacity utilization of the Domestic Industry has also declined in the POI compared to the base year.
- u. The productivity per day has declined from 100 indexed points in the base year to 93 indexed points in the POI. The no. of employees has also decreased by 2 indexed points.
- v. At the same time, the wages to the employees increased by 11 indexed points in the POI, as compared to the base year.

- w. Continued and incessant dumped imports from the subject countries have led to a significant decline in all the financial performance indicators of the Domestic Industry, such as PBIT, cash profits, and return on capital employed.
- x. The losses of the Domestic Industry have more than doubled in the injury period. The Domestic Industry's losses have increased by 315 indexed points in the POI as compared to the base year. This is primarily on account of the substantial pricing pressure from the exporters from the subject countries, particularly from China PR.
- y. The Domestic Industry incurred cash losses during the injury period and the same has intensified in the POI.
- z. The return on capital employed declined by 220 indexed points in the POI as compared to the base year.
- aa. The level of the inventories of finished goods has increased substantially in the POI compared to the base year 2019-20.
- bb. The dumped imports have clearly caused a deterioration in the financial performance of the Domestic Industry's PUC business. The PUC is part of a large product portfolio for the Domestic Industry, and the decline in the financial performance has adversely affected the Domestic Industry's overall capability to attract capital at competitive rates.
- cc. Chinese exporters evaded anti-dumping duties by mis-declaring the origin of imports as Sri Lanka and Spain, leading to a significant influx of underpriced goods that severely impacted the Domestic Industry. This circumvention nullified the benefits of the duties.
- dd. The Domestic Industry's capacity expansion plans were further delayed by the COVID-19 pandemic, which brought unforeseen challenges, including reduced demand, lockdowns, and financial pressures, preventing them from taking full advantage of the duties in place.
- ee. Some parties argued that they are selling products above the Non-Injurious Price (NIP) and should not be considered injurious to the Domestic Industry. The Domestic Industry agreed that fairly priced imports are not harmful but highlighted that a substantial volume of imports from subject countries are being dumped at prices below the NIP, causing significant injury.
- ff. While non-injurious imports exist, the Domestic Industry emphasized that dumped imports at injurious prices continue to harm the Domestic Industry by undercutting

- prices, eroding market share, and reducing profitability. The Authority must recognize the impact of these injurious imports.
- gg. Some interested parties argue there is no volume effect in the current investigation and suggest comparing import volumes in the Period of Investigation (POI) to FY 2019-20, dismissing data from FY 2020-21 and 2021-22 due to COVID-19. The Domestic Industry counters that such analysis would skew the assessment, as the anti-dumping duties deterred imports, and import volumes during the POI have significantly increased compared to FY 2021-22.
- hh. Certain parties argue the Domestic Industry caused its own injury by importing 3-4% of subject imports. The Domestic Industry clarifies that import volumes are calculated after excluding its own imports, refuting this claim.
- ii. Interested parties argue that imports have not affected prices. However, the Domestic Industry demonstrates that Chinese import prices have consistently been lower than its net sales realization, causing significant price suppression. Although domestic costs rose by 23%, domestic prices only increased by 17%, highlighting the impact of suppressed Chinese prices.
- jj. Kapoor argues that the landed price of imports from Kodak China and Lucky should include anti-dumping duty and compare their resale prices. The Domestic Industry rejects this, stating it is standard practice to calculate landed prices without anti-dumping duty and to compare them to domestic prices, which already account for relevant costs.
- kk. Kapoor disputes the 26% increase in the Domestic Industry's production costs, citing a decrease in London Metal Exchange (LME) aluminium prices. The Domestic Industry counters that the (i) information provided is unreliable, (ii) the CSP of aluminium has increased at LME, and (iii) cost increase is due to premiums and procurement costs, verified by the Authority during on-site inspections.
- ll. AIFMP and Kapoor rely on a CRISIL report showing TechNova's financial performance, but the Domestic Industry argues the report covers TechNova's overall business, not just DOPP. The report also highlights that the removal of anti-dumping duties led to significant imports and competition, confirming injury to the Domestic Industry.

H.3 Examination by the Authority:

82. Rule 11 of the AD Rules, 1995 read with Annexure II to the AD Rules, 1995 provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “... *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles...*”. Further, in considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
83. Rule 23 of the Rules provides that the provisions of Rule 6,7,8,9, 10, 11, 16, 18, 19 and 20 shall apply *mutatis mutandis* in case of a review. In case the performance of the domestic industry shows that it has not suffered injury during the current injury period, the Authority shall determine whether cessation of the present duty is likely to lead to recurrence of injury to the domestic industry.
84. The submissions made by the domestic industry and other interested parties during the course of investigation with regard to injury and causal link and considered relevant by the Authority are examined and addressed below under the relevant parameters.
85. The Authority notes that it is not necessary that all parameters of injury show deterioration. Some parameters may show deterioration, while some others may not. The Authority considers all injury parameters for assessing the financial parameters of the domestic industry. The Authority has examined the injury parameters objectively considering the facts and arguments submitted by the domestic industry and the other interested parties.
86. With regard to the allegations of various interested parties for changing the injury data contained in Proforma IV-A at such a belated stage, the Authority notes that the changes made by the domestic industry in Proforma IV-A is on account of the corrections identified during the course of the verification, which are miniscule in nature and does not impact holistic injury assessment. In addition, the Authority notes that the changes made by the domestic industry do not materially change the injury assessment in the present review. The

Authority has taken the updated data on record and relied upon it for the purpose of present final findings.

87. The Authority notes that the imports have been made in various units of measurement, including SQM, KGs, Pieces, and cases. The import volume has been determined in SQM based on the standard conversion norm i.e., 1.32 SQM per KG. With respect to the imports not made in SQM or KG, their quantity has been converted on the basis of the information indicated (quantities, dimensions etc.,) in the products' import transaction description. The sorted DG Systems data has been considered for the purpose of assessment of the injury in the present final findings.

88. The Authority with respect to the claim of the interested parties that the 22% Return on Capital Employed (ROCE) used by the DGTR in calculating the Non-Injurious Price (NIP) is inflated and does not reflect current market realities, such as lower interest and corporate tax rates, notes that 22% Rate of Capital Employed (ROCE) is consistently applied as standard practice in all anti-dumping investigations. It may be noted that in the case of Merino Panel Products the Ld. CESTAT upheld DGTR's practice of applying a 22% ROCE.

Cumulative Assessment of Injury

89. Article 3.3 of the WTO Anti-Dumping Agreement and Para (iii) of Annexure II of the AD Rules provide that in cases where imports of a product from more than one country are being simultaneously subjected to an anti-dumping investigation, the Authority will cumulatively assess the effect of such imports, in case it determines that:

- a. The margin of dumping established in relation to the imports from each country is more than two percent expressed as percentage of export price and the volume of the imports from each country is three percent (or more) of the import of like article or where the export of individual countries is less than three percent, the imports collectively account for more than seven percent of the import of like article; and
- b. Cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles.

90. The Authority notes that the volume of imports from these countries is above the *de minimis* limits prescribed under the AD Rules.

91. In order to ascertain whether cumulative assessment of the effect of imports is appropriate in light of the conditions of competition between the imported article and the like domestic articles, the following parameters have been examined:

- a. Products supplied by different parties are like articles and are comparable in properties
- b. Domestically produced products and the imported products are interchangeable. Consumers are using domestic products and imported products interchangeably and the exporter and the domestic industry have sold the same product to same set of customers.
- c. There is direct competition between the domestic product and the imported product and inter-se between the imported products.
- d. Import price from the subject countries have moved in tandem with each other.

92. The Authority notes that the domestic industry has provided evidence that the domestic producers and exporters from the subject countries sell 'like' products to the same category of customers, and both are competing in the same market. Both the products are being used by the consumers interchangeably. The same has also been ascertained by the Authority through DG Systems data.

93. In view of the above, the Authority considers it appropriate to cumulatively assess the effects of dumped imports of the product under consideration from the subject countries on the domestic industry.

94. The Authority has examined the effect of dumped imports on the state of the Domestic Industry in the paragraphs below.

H.3.1 Assessment of demand

95. The Authority has defined, for the purpose of the present investigation, demand or apparent consumption of the product under consideration in India as the sum of domestic sales of the domestic industry and other Indian producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

Particulars	UOM	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Import from Subject Countries	SQM	1,38,48,618	62,84,725	67,27,717	1,23,85,703
	Indexed	100	45	49	89
Import Non-Subject Countries	SQM	6,56,716	10,82,464	19,61,069	19,17,453
	Indexed	100	165	299	292
Total Imports	SQM	1,45,05,334	73,67,190	86,88,785	1,43,03,156
	Indexed	100	51	60	99
Sales of Domestic Industry	SQM	***	***	***	***
	Indexed	100	73	95	94
Sales of other domestic	SQM	***	***	***	***

producer	Indexed	100	23,100	1,73,463	1,67,345
Total Demand/Consumption	SQM	***	***	***	***
	Indexed	100	66	86	98

96. It is noted that the demand for the subject goods declined in 2020-21 as compared to 2019-20 but increased thereafter in 2021-22 and the POI. However, the demand has largely remained stable throughout the investigation period. The decline in the demand of the subject goods in the year 2020-21 and 2021-22 is on account of COVID 19 pandemic.

H.3.2 Volume effect of imports from subject countries

97. With regard to the volume of the imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India. For the purpose of injury analysis, the Authority has relied on the transaction wise import data procured from DG systems.

a) Relative Increase in the imports

98. The import volumes of the subject goods from the subject countries during the injury period and the period of investigation in relation to the production of the domestic industry and demand of the subject goods are as follows:

Particulars	UOM	2019-20	2020-21	2021-22	POI
<u>Imports in relation to Production of the Petitioner</u>					
Subject Countries	%	***	***	***	***
	Range	40-50	20-30	20-30	40-50
Non-Subject Countries	%	***	***	***	***
	Range	0-10	0-10	0-10	0-10
Total Imports	%	***	***	***	***
	Range	40-50	30-40	30-40	40-50

<u>Imports in relation to Demand in the country</u>					
Subject Countries	%	***	***	***	***
	Range	30-40	20-30	10-20	20-30
Non-Subject Countries	%	***	***	***	***
	Range	0-10	0-10	0-10	0-10
Total Imports	%	***	***	***	***
	Range	30-40	30-40	30-40	30-40

b) Absolute Increase in the imports

99. The import volumes of the subject goods from the subject countries during the injury period and the period of investigation in absolute terms of the subject goods are as follows:

Particulars	UOM	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Import from Subject Countries					
- China	SQM	1,20,02,862	46,81,170	52,84,813	1,16,11,633
- Japan	SQM	10,44,526	6,36,933	1,38,105	25,889
- South Korea	SQM	5,53,851	8,62,020	11,68,832	50,953
- Taiwan	SQM	2,33,646	1,04,602	1,35,967	6,97,228
- Vietnam	SQM	13,733	-	-	-
Total Import from Subject Countries	SQM	1,38,48,618	62,84,725	67,27,717	1,23,85,703
	Indexed	100	45	49	89
Imports from Non-Subject Countries	SQM	6,56,716	10,82,464	19,61,069	19,17,453
	Indexed	100	165	299	292
Total Imports	SQM	1,45,05,334	73,67,190	86,88,785	1,43,03,156
		100	51	60	99

100. It is seen that:

- a. The volume of imports from the subject countries has declined in the POI compared to the base year 2019-20. The decline in the import volumes in the year 2020-21 and 2021-22 is on account of the COVID 19 pandemic.
- b. Imports from Taiwan has increased in the POI compared to the base year whereas there is a minor decline in the imports from China PR. During the same period, imports from other subject countries have declined.
- c. Although the demand of the subject goods has witnessed a minor decline from the base year, the imports other than non-subject countries have increased.
- d. The imports from subject countries in relation to production of the domestic industry has declined from ***% to ***%.

H.3.3 Price effect of the imports from subject countries

101. With regard to the price effect of the imports from the subject countries, it is required to be analysed whether there has been a significant price undercutting by the alleged imports as compared to the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account

of the imports from the subject countries has been examined with reference to price undercutting, price suppression and price depression, if any.

a) Price Undercutting

102.To determine price undercutting, a comparison has been made between the landed value of the product and average selling price of the domestic industry, net of all rebates and taxes, at the same level of trade. The prices of the domestic industry were determined at the ex-factory level:

Particulars	UOM	2019-20	2020-21	2021-22	POI
NSR of domestic industry	INR /SQM	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	114	133
Landed Price from subject countries	INR/SQM	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	114	133	141
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	(6.07)	(25.86)	46.25
Price Undercutting	% - Range	20-40%	Negative	Negative	40-50

103.It is seen that there is positive price undercutting in the injury period except in the year 2021-22 where there is slightly negative price undercutting. It is noted that the price undercutting in the POI has increased from the year 2020-21 to the POI.

b) Price suppression/depression

104.In order to determine whether the effect of imports depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the Authority has examined the changes in the costs and prices of the domestic industry (at ex-factory level excluding direct selling overheads) over the injury period.

Particulars	UOM	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Cost to make and sell	INR/SQM	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	115	142
Domestic selling price	INR/SQM	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	114	133
Landed Price	INR/SQM	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	114	133	141

105.The Authority notes that the domestic industry experienced price pressure from imports. As evident from the table above, the selling price of the domestic industry has been

consistently below the cost to make and sell. The gap between the cost to make and sell and selling price has increased in the POI compared to the base year.

106. With regard to the claims of a few interested parties that the raw material cost of the domestic industry has not moved in tandem with the change in the prices of aluminium as per the London Metal Exchange (LME), the domestic industry has submitted that the prices quoted on LME are the price of base metal. The lithographic aluminium coil includes additional charges such as conversion cost, metal premium, energy surcharge etc., The Authority has verified the cost of purchase of aluminium by the domestic industry.

H.3.4 Economic Parameters of the domestic industry

107. The AD Rules require that the determination of the injury shall involve an objective examination of the consequent injury of the subject imports on the domestic producers. With regard to the consequent impact of these imports on the domestic producers of such products, the AD Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry would include an objective evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, performance of the domestic industry has been examined over the injury period.

a) Production, capacity, capacity utilization and sales volumes

108. The performance of the domestic industry with regard to capacity, production, sales and capacity utilization over the injury period was as below:

Particulars	UOM	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Capacity	SQM	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	100	100
Production	SQM	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	68	91	96
Capacity Utilization	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	68	89	93
Domestic Sales	SQM	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	73	95	94

109. It is seen that:

- a. The production of the PUC has declined in the POI compared to the base year 2019-20. Further, the Authority notes that the production of PUC has increased significantly in the POI compared to the production in the year 2020-21 and 2021-22.
- b. The capacity utilization of the domestic industry has declined in the POI compared to the base year 2019-20. The Authority notes that capacity utilization of the domestic industry is more than 100%, however the domestic industry submitted that it has been able to improve its production by continuous process improvement and debottlenecking.
- c. The domestic sales of the domestic industry have declined in the POI compared to the base year 2019-20.

b) Market Share

110. Market share of the imports and domestic industry have been examined as below:

Particulars	UOM	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Import from Subject Countries	SQM	1,38,48,618	62,84,725	67,27,717	1,23,85,703
- China	SQM	1,20,02,863	46,81,170	52,84,812	1,16,11,632
- Japan	SQM	10,44,526	6,36,933	1,38,105	25,889
- South Korea	SQM	5,53,851	8,62,020	11,68,832	50,953
- Taiwan	SQM	2,33,646	1,04,602	1,35,967	6,97,228
- Vietnam	SQM	13,733	-	-	-
Imports from Non-Subject Countries	SQM	6,56,716	10,82,464	19,61,069	19,17,453
Total Imports	SQM	1,45,05,334	73,67,190	86,88,785	1,43,03,156
Domestic Industry	SQM	***	***	***	***
Sales of the other producers	SQM	***	***	***	***
Total Demand	SQM	***	***	***	***
Total Demand	Indexed	100	66	86	98
<u>Market Share</u>					
Import from Subject Countries	%	***	***	***	***
	Indexed	100	69	57	91
- China	%	***	***	***	***
	Indexed	100	59	51	99
- Japan	%	***	***	***	***
	Indexed	100	93	15	3
- South Korea	%	***	***	***	***
	Indexed	100	236	246	9
- Taiwan	%	***	***	***	***
	Indexed	100	68	68	305

- Vietnam	%	***	***	***	***
	Indexed	100	-	-	-
Imports from Non Subject Countries	%	***	***	***	***
	Indexed	100	250	348	298
Total Imports	%	***	***	***	***
	Indexed	100	77	70	101
Domestic Industry	%	***	***	***	***
	Indexed	100	110	110	96
Sales of the Supporter	%	***	***	***	***
	Indexed	100	35,043	2,02,335	1,70,881
Total Demand	%	100%	100%	100%	100%

111.The Authority notes that the domestic industry has lost its market share in the period of investigation compared to previous year whereas the market share of the subject countries have increased from ***% to ***% during the same period.

c) Inventories

112.Inventory position of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	UOM	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Opening Inventories	SQM	***	***	***	***
Closing Inventories	SQM	***	***	***	***
Average Inventories	SQM	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	91	55	55

113.It is noted that the inventories of the domestic industry have declined over the injury period.

d) Profitability, cash profits and return on capital employed

114.Profits, cash profits and return on capital employed of the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	UOM	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Profit/(Loss) before interest and tax (PBIT)	INR in Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	(100)	(146)	(216)	(391)
Profit/(Loss) before interest and tax (PBIT)	INR/SQM	***	***	***	***
Trend	Indexed	(100)	(200)	(228)	(417)
Cash Profits/(Losses)	INR in Lacs	***	***	***	***

Trend	Indexed	(100)	(280)	(597)	(2,010)
Cash Profits/(Losses)	INR/SQM	***	***	***	***
Trend	Indexed	(100)	(384)	(632)	(2,142)
Capital employed	INR in Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	101	104	129
Return on capital employed	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	(100)	(144)	(208)	(302)

115.The Authority notes that the performance of the domestic industry has further declined. It is noted that the inventories of the domestic industry have declined over the injury period. The profits, cash profits and return on capital have further declined compared to the base year. The domestic industry is incurring cash losses with negative return on capital employed.

116.With regard to the contention of various interested parties that the duties have had no effect on the performance of the domestic industry, the Authority notes that the domestic industry has not been able to increase its prices commensurate with increase in the cost.

e) Employment, wages and productivity

117.The Authority has examined the information relating to employment, wages and productivity, as given below:

Particulars	UOM	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Productivity per day	SQM/Day	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	68	89	93
Employment	Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	101	102	98
Wages	INR in Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	83	105	114

118.It is noted that the number of employees has remained stable over the injury period. The productivity per day has declined over the injury period, however, wages has increased over the period of investigation.

H.3.5 Ability to raise capital investment

119.The Authority notes that the performance of the domestic industry has declined concerning its PUC business. The domestic industry suffered losses as well as recorded a negative

decline in return on capital employed. Thus, the imports have adversely impacted the ability of the domestic industry to raise its capital investment.

I. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

120. The non-injurious price of the product under consideration has been determined by adopting the verified information/data relating to the cost of production for the period of investigation. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject countries for calculating the injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilisation of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilisation of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses are charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price.
121. Certain interested parties have argued to examine the cost of production and allocation methodologies followed for the determination of non-injurious price and injury claimed by the domestic industry. In this regard, the Authority notes that it has examined and verified the records of the domestic industry including but not limited to the allocation of the cost, to its satisfaction while computing the non-injurious price as well as the claims of injury made by the domestic industry. With regard concerns on the allocation of infrastructural cost of non-PUC products to PUC, the Authority has examined allocations made and allowed the cost appropriately for computation of NIP. The Authority has followed the principles laid down in Annexure III for computation of the non-injurious Price as indicated the table below.
122. The landed price for the cooperative producers / exporters from the subject countries has been determined on the basis of the data provided by the producers / exporters. For all the non-cooperative producers/exporters from the subject countries, the Authority has determined the landed price based on the facts available.
123. Some of the Interested parties averred that handling, loading, unloading charges should be considered for purpose of computation of landed value. The Authority has computed the landed price of based on assessable value of the subject goods which in in line with the

consistent practice followed by the Authority. The landed price as computed by the Authority is indicated in the table below.

124. Based on the landed price and non-injurious price determined as above for the PCNs prescribed by the Authority, the weighted average injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority and the same is provided in the table below

Injury Margin Table

SN	Producer	NIP	Landed Price	Injury Margin	Injury Margin	Range
		USD/SQM	USD/SQM	USD/SQM	%	%
1	China PR					
a	Lucky Huaguang Graphics Co. Ltd.	***	***	***	***	30-40
b	Kodak China Graphic Communications Co. Ltd.	***	***	***	***	Negative
c	Fujifilm Printing Plate (China) Co. Ltd.	***	***	***	***	0-10
d	Anhui Strong State New Materials Co., Ltd.	***	***	***	***	10-20
e	Huangshan Jinruitai Technology Co., Ltd.	***	***	***	***	20-30
f	Chongqing Huafeng Di Jet Printing Material Co., Ltd	***	***	***	***	30-40
g	Any other	***	***	***	***	30-40
2	Korea RP	***	***	***	***	
a	Jeil C&P Co. Ltd.	***	***	***	***	20-30
b	Any other	***	***	***	***	20-30
3	Japan	***	***	***	***	
a	Fujifilm Corporation	***	***	***	***	10-20
b	Any other	***	***	***	***	20-30
4	Taiwan	***	***	***	***	
a	All	***	***	***	***	30-40
5	Vietnam	***	***	***	***	
a	All	***	***	***	***	30-40

J. CAUSAL LINK AND NON – ATTRIBUTION ANALYSIS

J.1 Submissions made by the other interested parties

125. Various interested parties have made following submissions:

- Injury to the domestic industry is due to internal competition.

- b. A new producer, HL Printech Solutions Pvt. Ltd., began commercial production in FY 2020-21.
- c. HL Printech Solutions Pvt. Ltd. increased its production significantly from 100 index points in FY 2020-21 to 431 index points during the POI, an increase of approximately 3.3 times.
- d. The domestic sales of other producers rose substantially from 100 index points in the base year to 167,345 index points during the POI.
- e. The injury, if any, suffered by the applicant is due to the pricing strategies of other domestic producers, especially the new entrant, HL Printech Solutions Pvt. Ltd.
- f. The export sales of the applicant's PUC declined by around 22% during the POI compared to the base year, increasing the per-unit fixed cost. Any injury to the applicant is due to this decline in export sales.
- g. The applicant has enjoyed duty protection since December 2012, for approximately 11.5 years. The injury, if any, is due to mismanagement and poor business decisions by the applicant.
- h. The respondents request that the Authority not attribute any injury suffered by the applicant to imports from China PR and Japan, as other factors are responsible for any harm experienced.
- i. The domestic industry claimed during the oral hearing that it is a major producer and exporter of the product under consideration, and is price competitive in export markets.
- j. This raises concerns about the domestic industry's performance in India, where it claims injury due to dumped imports, while being price competitive in export markets.
- k. The domestic industry should address why it is competitive in export markets but struggles in its own home market.
- l. The domestic industry's claims of Chinese dumping and large production capacity raise questions about its ability to compete globally while claiming injury at home.
- m. The information provided by the domestic industry shows a decline in export volume during the injury period.
- n. The trends in domestic selling prices and export selling prices have been similar throughout the injury period.
- o. The injury, if any, is due to internal competition, notably from a new producer, H.L. Printech Solutions Pvt. Ltd., whose production increased by 3.3 times during the

POI. The new domestic producer's penetrating pricing policy is the real cause of any injury to the applicant.

- p. The Petitioner has deliberately overlooked other external factors which could cause injury to it, such as the Russia-Ukraine war.

J.2 Submissions made by the Domestic Industry

126. The domestic industry has made following submissions:

- a. In a sunset review, authorities must determine whether removing anti-dumping duties would lead to continued or resumed dumping and consequent injury to the domestic industry. It's not necessary to re-establish the causal link between dumping and injury, as sunset reviews focus on the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury.
- b. Several rulings, including the WTO's decision in the US–OCTG from Mexico case and Indian Supreme Court cases (Rishiroop Polymers and Union of India v. Kumho Petrochemicals), confirm that sunset reviews only assess whether withdrawing anti-dumping duties would lead to resumed dumping and injury, not whether dumping exists anew.
- c. Despite existing measures, the Domestic Industry remains at significant risk of injury from persistent dumping. Historical patterns indicate that removing duties would likely lead to intensified dumping and further harm.
- d. The claim that TechNova is attributing costs from obsolete infrastructure to the production of the PUC is incorrect. Only costs directly associated with PUC production are reported.
- e. Arguments that new producers, such as HL Printech, are creating competition for the Domestic Industry are dismissed. HL Printech's market share is minimal and has no impact on the Domestic Industry's performance.
- f. Claims that the Domestic Industry is injured due to export losses are irrelevant, as the injury analysis pertains exclusively to domestic sales. TechNova's export sales represent a small portion of its overall business and have little impact on its financial performance.
- g. While there was a fall in demand during the pandemic, the Domestic Industry's performance improved slightly due to a reduction in imports from subject countries. However, as conditions normalized, dumped imports surged again, leading to a decline in sales during the POI.

- h. Claims of injury due to mismanagement or poor business decisions are unsupported by evidence. The Domestic Industry has consistently made prudent decisions to maintain competitiveness, and the injury is directly attributable to intensified dumping.
- i. The conflict has disrupted supply chains and increased costs globally, but it has affected all parties in the investigation equally. The conflict did not affect dumping patterns, as import prices did not increase at the same rate as production costs, indicating dumping continued regardless of geopolitical issues.

J.3 Examination by the Authority

127. As per the Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than dumped imports which are injuring to the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. While the present review is a sunset review and causal link has already been examined in original investigation, the Authority examined whether other known listed factors have caused or are likely to cause injury to the domestic industry. In particular, the Authority has also examined if the removal of duties is likely to result in the continuation/recurrence of injury to the domestic industry.
128. **Volume and value of imports from third countries:** The Authority notes that imports from countries other than subject countries are insignificant. Therefore, imports from third countries cannot be the reason for the injury suffered by the domestic industry.
129. **Contraction in demand and pattern of consumption:** The Authority notes that the demand of the subject goods has been stable with minor decline. Therefore, imports from contraction in the demand of subject goods cannot be cause of injury to the domestic industry. Further, Authority notes that there is no material change in the pattern of consumption of the product under consideration, to which the injury suffered by the domestic industry can be attributed.
130. **Conditions of competition and trade restrictive practices:** There are no trade restrictive practice or conditions of competition which can cause to the domestic industry. With regard to the inter-se competition between the domestic producers, the Authority notes that the domestic producers including the domestic industry faces competition from the imports from the subject countries.

131. **Development of technology**: None of the interested parties have furnished any evidence to demonstrate significant changes in the technology that could have caused injury to the Domestic Industry.
132. **Performance of other products of company**: The Authority notes that the performance of other products being produced and sold by the Domestic Industry does not appear to be a possible cause of injury to the Domestic Industry. In any event, the Authority has considered the performance of PUC only for the purpose of the injury assessment.
133. **Export performance**: The Authority has considered the performance of domestic operations only for injury analysis of domestic industry. Further, the Authority notes that the domestic industry has very limited exports, therefore, external reasons such as Russia-Ukraine war cannot be a cause of injury to the domestic industry.
134. **Pricing strategy and other management decisions by the Domestic Industry**: The Authority notes that the interested parties have argued that the Domestic Industry has adopted poor pricing strategies which have resulted in loss of profitability. In this regard, the Authority notes that the Domestic Industry has been reeling under the pressure of dumped imports which have been suppressing the prices of the Domestic Industry. There is a causal link between the dumped imports and the injury caused to the Domestic Industry.

K. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

K.1 Submissions made by the other interested parties

135. Various interested parties have made the following submissions:

- a. The Federation argues that there is no likelihood of injury recurrence if duties are withdrawn, as Technova's physical and financial performance has significantly improved under the current anti-dumping duty (ADD) regime.
- b. The applicant's claims regarding the likelihood of injury are unsubstantiated, as they rely on flawed logic. The mere existence of spare capacities in exporting countries does not automatically justify injury recurrence without considering global demand-supply dynamics.

- c. The applicant's assertion that the Indian market is price attractive contradicts its claim of lower import prices. In a market with a demand-supply gap, foreign sellers would logically charge a premium. Additionally, the applicant has not provided sufficient data on inventories and price scenarios to support its injury claims.
- d. The existence of injury and dumping alone does not automatically imply a likelihood of continued or recurrent injury. It must be shown that the injury is caused by imports. If the injury stems from other factors, the claim of continued injury from imports cannot be sustained.
- e. While there is no strict format for substantiating the likelihood of injury, certain parameters have been considered by the Authority in past cases, as outlined in Trade Notice No. 4/5/2017-DGAD, dated December 12, 2017. These parameters include:
 - Total and surplus capacities of the product under consideration in subject countries during the POI and three years prior.
 - Quantities and prices of exports by producers/exporters in subject countries to destinations other than India.
 - Export orientation of producers/exporters in subject countries.
 - Justification for why the Indian market would be targeted for exports after the withdrawal of anti-dumping duties.
- f. The petitioner has not provided information on these key parameters. There is no explanation as to why the Indian market would be the preferred destination for exports after the removal of ADD, nor has the attractiveness of the Indian market been substantiated.
- g. The Appellate Body in the US — Corrosion-Resistant Steel Sunset Review noted that using presumptions without positive evidence can be inconsistent with the obligation to make determinations based on solid evidence. Thus, a firm evidentiary foundation is required to properly assess the likelihood of continued or recurrent dumping.
- h. The domestic industry claims that producers in subject countries, especially China, have significant spare capacity. However, surplus capacity alone does not establish a likelihood of dumping or injury. It must be demonstrated how this capacity would be directed to the Indian market. Past cases, such as Aniline from the USA and Japan, have shown that surplus capacity is insufficient to prove likelihood without further justification.

- i. The petitioner references anti-dumping duties imposed on China by other countries, including Brazil, South Korea, Chinese Taipei, and the EU. However, the imposition of duties by other countries does not automatically imply that the product will be diverted to the Indian market.
- j. The domestic industry attributes its continued injury to imports, but its performance has deteriorated despite the imposition of duties. This indicates that the injury is likely caused by other factors, not imports, as detailed in previous submissions.
- k. The companies rejected claims of excess production capacity in China, providing evidence of high capacity utilization. They argued that the mere existence of capacity does not equate to an imminent threat to the Indian market.

K.2 Submissions made by the Domestic Industry

136. Various interested parties have made the following submissions:

- a. Imports of the PUC from the subject countries continue to be dumped. The fact that imports continue to be dumped and cause injury to the Domestic Industry is sufficient to establish the likelihood of continuation of dumping and injury.
- b. Dumped imports continue to come from the subject countries in significant volumes. If the duties are withdrawn, there is a strong likelihood of incessant dumped imports from the subject countries.
- c. The Domestic Industry continues to suffer from price and volume injury despite the imposition of anti-dumping duties.
- d. Financial and economic performance has declined substantially over the past four years.
- e. Domestic Industry is forced to sell products at low prices, significantly impacting profitability.
- f. Despite anti-dumping duties, consistent profitability has not been maintained.
- g. Return on Capital Employed (ROCE) is negative and far lower than the benchmark rate of 22%.
- h. There is positive price undercutting, price underselling, price depression, and price suppression, as detailed in Part VI of the Petition.
- i. Injury is expected to continue and worsen if duties are withdrawn.
- j. In 2018, the Authority did not recommend continuing duties against China PR, leading to a substantial increase in injury to the Domestic Industry in a short period.

- k. Substantial excess and idle capacities exist in China PR for the production of the product under consideration (PUC).
- l. China PR's installed capacities exceed 1025 million SQM, while domestic demand is estimated at only 180-200 million SQM.
- m. Excess capacity of about 825 million SQM is directed toward export markets.
- n. India's market size for the subject goods is around 45 million SQM annually.
- o. The excess capacity in China PR is nearly 20 times greater than India's total domestic demand.
- p. If duties are withdrawn, China PR's excess capacity will likely be utilized for increased exports to India.
- q. China's aluminium market is distorted due to state intervention, as noted in OECD reports from 2019 and 2024.
- r. China has managed high input costs and low aluminium prices through sustained state support.
- s. China's tariff structure supports downstream aluminium activities, with high export tariffs and incomplete VAT rebates on primary aluminium exports.
- t. China provides preferential loans, tax incentives, and subsidized energy prices to aluminium manufacturers and PUC producers.
- u. This lowers production costs and leads to an oversupply of aluminum in the global market, affecting other countries' producers.
- v. These market distortions have created significant challenges for the Domestic Industry.
- w. Persistent state intervention and market distortions in China PR increase the likelihood of continued dumping and injury to the Domestic Industry.
- x. Chinese exporters engage in trade malpractices, such as transshipment and false declarations of origin (e.g., declaring origin as Sri Lanka or Spain instead of China PR).
- y. These malpractices flood the Indian market with dumped products, undermining the Domestic Industry.
- z. Imports of the subject goods are priced substantially lower than domestic prices.
- aa. With increased demand and anti-dumping measures in other countries, India becomes an attractive market for exporters from subject countries.
- bb. Various jurisdictions, including Brazil, South Korea, Taiwan, the USA, and the EU, have imposed anti-dumping duties on digital plates from China PR, highlighting the

- global recognition of China's dumping practices and increasing the likelihood of redirected excess production to India if duties are withdrawn.
- cc. In the absence of anti-dumping duties, imports and dumping will likely increase.
 - dd. Anti-dumping measures in Brazil, South Korea, Taiwan, the USA, and the EU increase the risk of Chinese dumping in India.
 - ee. Without anti-dumping duties, India would become a prime target for dumped digital plates at unfair prices, severely harming the Domestic Industry.
 - ff. Trade Notices serve as guidelines for investigations but are not legally binding. Particularly in cases of establishing the likelihood of continued or recurred dumping and injury, the Domestic Industry may not have access to confidential information, such as surplus capacities of foreign producers. The goal is for the Domestic Industry to provide sufficient reason to believe there is an imminent threat of continued/recurred dumping if duties expire.
 - gg. The Domestic Industry provided evidence that China's total installed capacity for the PUC is over 1025 million SQM, with domestic demand at only 180-200 million SQM, leaving an excess of around 825 million SQM dedicated to export markets. In contrast, India's market size is only 45 million SQM annually, making China's excess capacity nearly 20 times India's total demand.
 - hh. Although the PUC lacks a dedicated HS tariff code, making it difficult to provide third-country export data, the Domestic Industry established that the subject countries are export-oriented and adopt unfair practices globally. Countries like Brazil, Taiwan, Korea RP, and the USA have imposed duties on DOPP imports from China.
 - ii. The Domestic Industry has shown that if anti-dumping duties are removed, India would be a prime target for low-priced, dumped digital plates from China, as other jurisdictions become unviable for Chinese producers.
 - jj. Jeil admitted its exports were minimal during the injury period due to plant shutdowns. However, with new capacities now in place, Jeil is likely to increase exports to India if anti-dumping duties are removed.
 - kk. The Domestic Industry argues that if anti-dumping duties are withdrawn, India risks becoming a dumping ground for Chinese imports, particularly given the substantial dumping and injury margins that have persisted despite existing duties.
 - ll. China's state-supported aluminium market gives its producers an unfair advantage by allowing them to undercut global competitors, including those in India. Other

- countries like Brazil, South Korea, and the USA have imposed anti-dumping measures against Chinese exports to combat this threat.
- mm. Without anti-dumping protections, India will be vulnerable to a surge in dumped imports, exacerbating the injury already suffered by the Domestic Industry and destabilizing the market with cheap, low-quality imports.
- nn. None of the interested parties have disputed the facts presented by the Domestic Industry regarding the likelihood of continued or recurred dumping and injury.

K.3 Examination by the Authority

137. The present review is a sunset review of anti-dumping duties imposed on the imports of the product under consideration from China PR, Korean RP, Japan, Taiwan and Vietnam. Under the AD Rules, the Authority is required to determine whether cessation of existing duty is likely to lead to continuance or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
138. The Authority has examined the likelihood of continuation or recurrence of injury considering the requirement laid down under Section 9A (5), Rule 23 and parameters relating to the threat of material injury in terms of Annexure - II (vii) of the Rule rules, and other relevant factors brought on record by the interested parties.
139. There are no specific methodologies available to conduct such a likelihood analysis. However, Clause (vii) of Annexure II of the Rules provides, inter alia for factors which are required to be taken into consideration, viz.
- a. A significant rate of increase of dumped imports into India indicating the likelihood of substantially increased importation.
 - b. Sufficient freely disposable, or an imminent, substantial increase in, capacity of the exporter indicating the likelihood of substantially increased dumped exports to Indian markets, taking into account the availability of other export markets to absorb any additional exports.
 - c. Whether imports are entering at prices that will have a significant depressing or suppressing effect on domestic prices and would likely increase demand for further imports; and
 - d. Inventories of the article are being investigated

140. The Authority has, *inter alia*, considered the above requirements and following parameters in order to determine whether dumping is likely to recur in the event of cessation of anti-dumping duty, and if so, whether the same is likely to cause injury to the domestic industry. Additionally, the Authority has examined all the relevant information brought on record by the domestic industry and the other interested parties.

Significant Rate of increase of dumped imports

141. The Authority notes that while the overall imports of the PUC have remained stable, the imports from subject countries have increased significantly in the POI compared with the imports made in the year 2020-21 & 2021-22. The imports from the subject countries are provided in the table below:

Particulars	UOM	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Subject Countries	SQM	1,38,48,619	62,84,725	67,27,716	1,23,85,702
	Indexed	100	45	49	89

142. The Authority notes that anti-dumping duties were in effect from January 30, 2020, were not applicable for most of the year 2019-20. The Authority notes that imports have continue to be significant even after imposition of anti-dumping duty. Consequently, if these duties are permitted to lapse, there is a significant likelihood of increased imports from the subject countries.

Continued and existing dumping and injury

143. The Authority notes that the imports of the product under consideration in the current period of investigation are at dumped prices despite anti-dumping duties in existence. It is also noted that the performance of the domestic industry has significantly deteriorated in respect of the profits, cash profits and the return on capital employed. It is also seen that the subject imports are undercutting the prices of the domestic industry.

Surplus and disposable capacities

144. Based on the information made available by the interested parties, the Authority notes that there are substantial excess and idle capacities to product the PUC in the subject countries (particularly from China PR). The domestic industry submitted that the total installed capacities in China PR are in excess of 1025 million SQM, whereas the total demand in the country is estimated to be only 180-200 million SQM. The excess capacities of about 825 million SQM are dedicated for the export markets. The excess capacities are about 20 times

of the Indian demand. The Authority notes that none of the interested parties have provided any information or evidence contrary to the claims made by the domestic industry.

145. Further, the analysis of the questionnaire response filed by the responding exporters from the subject countries shows as follows:

Particulars	Unit	Exporters from China PR	Exporters from Japan	Exporters from Korea RP	Total
Installed Capacity	SQM	***	***	***	***
Production	SQM	***	***	***	***
Capacity Utilization	%	***	***	***	***
Total Sales	SQM	***	***	***	***
Export Sales	SQM	***	***	***	***
Surplus capacities	SQM	***	***	***	***
Export Orientation – Ratio of export sales to total sales	%	40-50%	50-60%	40-50%	50-60%

146. As can be seen from the above,

- The producers and exporters have far higher capacities than the total Indian demand. Further, the unutilized capacities available with the participating producer and exporters is about ***% of the Indian demand.
- The producers and exporters are highly export oriented with about ***%-***% of the total sales are exported from respective countries. These exports can be diverted to India.

Imposition of duties by various countries

147. The applicant has submitted that the various countries have imposed anti-dumping duties on the PUC against China PR and other countries. The details of the same are provided as under:

- Brazil:** Brazil has extended definitive anti-dumping duty for a period of five years on the PUC imported from China PR, Chinese Taipei, the USA, the EU, and the UK on May 4, 2021. The duties range from USD 0.19 – 2.38/KG.
- South Korea:** South Korea has extended anti-dumping duty for a period of five years on the PUC imported from China PR on October 25, 2022. The duties range from 8.78 – 10.32%.

- c. Chinese Taipei: On May 25, 2023, the Ministry of Finance of Chinese Taipei initiated an anti-dumping investigation on the PUC originating in or imported from China PR. In June 2024, Chinese Taipei imposed duties on imports from China PR. The duties range from 13.52% - 76.89%.
- d. United States of America: The United States has preliminarily determined that Chinese exports of DOPP to the US are being both dumped and subsidized. The preliminary CVD duties range from 38.5 – 231.98%, while the preliminary anti-dumping duties range from 164.30-477.59%. In addition, the US is conducting an anti-dumping investigation against imports from Japan.

148. The Authority notes that the exporters and producers from the subject countries are dumping the PUC into India despite anti-dumping duty in force. The domestic industry has claimed that the dumping behaviours clearly establishes that in the event of cessation of the antidumping duty, the producers/exporters from the subject countries will continue to dump the product into India.

Suppressing and depressing effect of imports

149. As seen from the injury assessment, the imports from the subject countries are suppressing the prices of the domestic industry as well as undercutting the selling price of the domestic industry. The same is evident from the table below:

Particulars	UOM	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Cost to make and sell	INR/SQM	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	96	115	142
Domestic selling price	INR/SQM	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	114	133
Landed Price	INR/SQM	228	259	304	323
Trend	Indexed	100	114	133	141
Price Undercutting	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	(6.07)	(25.86)	46.25
Price Undercutting	% - Range	20-40%	Negative	Negative	40-50

150. It is seen that in the period of investigation, the landed price of the subject imports is below the selling price and cost of sales of the domestic industry. The Authority notes that with the expiry of measures, the imports will have a significant depressing or suppressing effect on prices of the domestic industry.

151. Post POI: The Authority notes that certain interested parties have requested the Authority to assess post-POI data in the present review, it is noted that since there is enough evidence on record to establish the likelihood of continuation of dumping and recurrence of injury, it was not deemed necessary to examine post-POI data.

L. INDIAN INDUSTRY INTEREST AND OTHER ISSUES

L.1 Submissions made by other interested parties

152. The interested parties have made following submissions:

- a. The Federation argues that the significant demand-supply gap in the Indian market for printing plates makes the allegation of continued dumping by all sources economically implausible. The total market for printing plates in India is approximately 48 million SQM annually, with segments including 18.5 million SQM for CTCP Digital Offset Plates, 13 million SQM for Thermal Digital Offset Plates, 7 million SQM for Chemical-Free Plates, and 1.5 million SQM for Process-less Plates. Domestic manufacturers can produce only 20-25 million SQM, covering about 50% of demand, forcing the user industry to rely on imports for the remaining requirement. This demand-supply gap gives exporters an advantage in setting prices in the Indian market, making it unlikely that all exporters would resort to dumping or that governments would be subsidizing exports, as claimed by the applicant. Due to the ongoing demand-supply gap, imposing or continuing anti-dumping or anti-subsidy duties would harm the user printing industry by increasing costs and disrupting supply chains.
- b. The domestic industry, particularly Technova, faces regular quality and supply disruption issues. Problems such as spot issues, lining issues, and sensitivity variations have been reported with Technova's plates. In contrast, imported plates offer consistent quality, making them preferable for users seeking reliable printing outputs. Despite these issues and the clear demand-supply gap, domestic producers, including Technova, have not made significant efforts to scale up production or improve product quality.
- c. Technova, in partnership with Agfa, has failed to maintain quality or expand production sufficiently to meet domestic demand, while restrictions prevent producers from countries like China from entering the Indian market.
- d. The continuation of anti-dumping duties could increase costs for industries reliant on the PUC, including printing and publishing companies, by raising the cost of imports.

This cost increase could result in higher prices for printed materials, packaging, and related products, which would ultimately be passed on to consumers.

- e. Higher prices could reduce the competitiveness of the Indian printing and publishing sectors, both domestically and internationally, and hurt profit margins in industries that operate on thin margins.
- f. Maintaining the duties could disrupt established supply chains, especially for companies with tight margins that depend on affordable and stable supplies of DOPP.
- g. If domestic production cannot meet demand, the increased costs due to anti-dumping duties could cause production delays, reduced output, or decreased profitability for the user industry. The broader economic impact should also be considered, as the printing and packaging industries contribute significantly to employment and ancillary sectors in India. MSMEs, in particular, would struggle with the higher input costs, threatening their financial stability and growth prospects.
- h. The continuation of duties could lead to increased operational costs for the downstream industries reliant on DOPP, disrupting supply chains and negatively impacting the broadereconomy. The producer/exporter argues that the ongoing reliance on imports is necessary to bridge the demand-supply gap, and the imposition of ADD harms the downstream industry without addressing the root causes of the domestic industry's struggles.
- i. Digital offset printing plates produced by Chinese manufacturers are of superior quality, without the technical issues faced with Technova's products, which use outdated technology.
- j. The printing industry comprises different types of operations based on run-length. Long runs for large quantities (e.g., newspapers) where plate costs are a smaller share of operational expenditure. Medium runs for print volumes like brochures and catalogs, which may not justify the higher setup costs of traditional offset printing. iii. Short runs for on-demand or limited quantities (e.g., business cards), where plate costs can account for up to 85% of total expenditure, making price changes impactful.
- k. The imposition of anti-dumping duties on digital offset printing plates significantly affects the packaging printing industry by increasing raw material costs and squeezing profit margins in an already price-sensitive market.
- l. The increased costs also negatively impact plate bureaus and pre-press houses, which rely heavily on digital offset plates. The imposition of duties strains their financial positions.

- m. Protecting local manufacturers is important, but the claim that continuing anti-dumping duties is crucial for India's self-sufficiency in this sector is unfounded.

L.2 Submissions made by the Domestic Industry

153. The interested parties have made following submissions:

- a. Continuation of anti-dumping duties will have a negligible effect on downstream industries, with a 20% average duty translating to only 0.5% to 1.5% of the average cost of a print job in segments like newspaper, commercial, and packaging printing. No users opposing duties have demonstrated any adverse public interest impacts from the duties.
- b. Non-continuation of duties would lead to the shutdown of the Domestic Industry, which is critical for India's self-reliance in the printing sector, essential for industries such as media, publishing, and packaging.
- c. The DOPP market often has urgent needs, especially in sectors like newspapers and packaging. Relying on imports introduces risks of delays, quality issues, and price volatility, which are unacceptable in critical sectors.
- d. The Domestic Industry has proven its ability to meet urgent demands efficiently, as seen during the COVID-19 lockdown.
- e. During the lockdown, global supply chains were disrupted, but the Indian newspaper industry continued to function due to the availability of domestically produced DOPP.
- f. With imports unavailable, the nation relied on domestic manufacturers, demonstrating the importance of a robust Domestic Industry for national security and continuity of essential services.
- g. Despite the strategic importance of DOPP, the Domestic Industry is struggling to survive due to dumped imports being sold at artificially low prices.
- h. These imports are significantly undercutting domestic manufacturers' prices, making it economically unviable for the Domestic Industry to continue operations.
- i. The closure of domestic plants would result in substantial job losses and make India entirely dependent on imports.
- j. This would jeopardize India's ability to respond to future emergencies that require quick and reliable supply.
- k. To ensure that India remains self-sufficient in this strategically important sector, capable of meeting national needs during crises, it is crucial that the Authority continues the anti-dumping duties on DOPP imports.

1. Parties argued that imported plates are preferred due to consistent quality, while domestic plates often have quality issues. The Domestic Industry noted that TechNova has one of the lowest rejection rates and emphasized that anti-dumping duties are intended to ensure fair pricing, not limit competition based on product quality.

L.3 Examination by Authority

154. The Authority considered whether extension of ADD shall have adverse public interest. For the same, the Authority examined whether the extension of the anti-dumping duty on imports of the product under investigation would be against the larger public interest. This determination is based on consideration of information on record and interests of various parties, including domestic industry, importers, and consumers of the product.
155. The Authority issued gazette notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers, and other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the consumers to provide relevant information with respect to the present investigation, including the possible effects of the anti-dumping duties on their operations. The Authority sought information on, inter-alia, the interchangeability of the product supplied by various suppliers from different countries, ability of the consumers to switch sources, the effect of anti-dumping duties on the consumers, factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by the imposition of the antidumping duties.
156. It is noted that the purpose of anti-dumping measures, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. The Authority recognizes that the continuation of the anti-dumping duties might affect the price levels of the product under consideration as well as other downstream products manufactured by using the subject goods in India. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the imposition of anti-dumping measures. On the contrary, the continuation of anti-dumping measures would prevent the decline of the domestic industry that may ensue as a consequence of low-priced imports from the subject countries and help maintain the wider availability of choices to the consumers of the product under consideration.

157. It has also been claimed that there is a demand and supply gap in the country. However, the Authority notes that the demand-supply gap does not justify dumping. The Authority notes that the anti-dumping duties are not imposed to block imports, but to create a level playing field in the domestic market. The user industry of the PUC can continue to import at fair prices. The Authority notes that existence of a viable domestic industry (being the only large producer accounting for more than 95% of domestic production) is necessary for the user industry to avoid being excessively dependent on imports leading to high chances of supply chains disruptions.
158. The interested parties have claimed that there are quality issues such as spot issues, lining issues, and sensitivity variations etc., in the domestically manufactured products. On the other hand, the domestic industry has claimed that it has one of the lowest rejection rates in the industry and submitted relevant data in this regard. The Authority notes that the anti-dumping measures aim to ensure that all products, whether domestic or imported, are priced fairly and do not undermine the Domestic Industry through unfair competition. Anti-dumping duties aim to level the playing field and protect the integrity of the market, encouraging both domestic and foreign producers to meet high standards without engaging in unfair trade practices.
159. The Authority notes that the interested parties have not demonstrated how the prices of subject goods have adversely impacted the consumers. On the other hand, the domestic industry has submitted quantified information showing that the impact of the antidumping duties on the user industry would be miniscule. The domestic industry submitted that the current prevalent anti-dumping duties (assuming an average rate of 20%) translate to a cost increase of merely 0.5% to 1.5% of the average cost of a print job in the predominant end-use segments such as the newspaper printing segment, commercial printing segment, and packaging printing segment. From the information on record, the Authority notes that the impact of anti-dumping duty is miniscule to the consumers of the product under consideration.
160. The domestic industry procures its main raw material (litho grade aluminium coil) from Hindalco to the extent of their manufacturing capacity. The Authority notes that any decline in the production of the PUC by the domestic industry would adversely impact the operations of Hindalco for litho grade aluminium coils since the domestic industry is the only large manufacturer of the subject goods in the country. The Authority also notes that

Hindalco has extended the support to the domestic industry for imposition of anti-dumping duties on imports of PUC.

M. POST DISCLOSURE ANALYSIS

161. The Authority circulated the disclosure statement containing all essential facts under consideration for making final recommendations to the Central Government to all interested parties on 20th September 2024. The interested parties were directed to file their comments on the disclosure statement by 25th September 2024. The Authority has examined all post – disclosure comments made by the interested parties in these final findings to the extent deemed relevant. Any submission which was merely a reproduction of the previous submission and which had been adequately examined by the Authority have not been repeated for the sake of brevity.

M.1 Submissions made by the domestic industry:

162. The domestic industry has submitted the following:

- a) The applicant disputes claims made by interested parties that they had committed to invest INR 400 crores in future capacity expansion. The applicant clarified that the INR 400 crores were cumulative investments made in manufacturing facilities up until this period, not a future commitment. They argue that once a level playing field is restored, further investments will be made.
- b) The applicant argues that misdeclared imports from Sri Lanka and Spain which are actually of Chinese origin should be included in the Authority's injury assessment. They claim that the exclusion of these imports distorts the injury analysis and that Chinese exporters are engaging in trade malpractices such as transshipment to evade anti-dumping duties.
- c) The applicant disagrees with the Authority's decision to grant separate duty margins to producers like Huangshan Jinruitai and Chongqing Huafeng. TechNova argues that the residual rate of duty should be extended to these producers, citing the Authority's past practice in other sunset reviews where the same rate was applied to new producers.

M.2 Submissions by the other interested parties-

163. The other interested parties has submitted the following:

- a) Jeil C & P Co., Ltd argues that the dumping margin (80-90%) was incorrectly calculated due to errors in the cost per unit in Appendix 8. They claim the exclusion of inventory adjustments has led to an inflated cost of goods sold and request a recalculation. They also disputes the Authority's rejection of their inventory

- adjustment claim, explaining that it reflects the difference between production and sales quantity, not an adjustment. They request reconsideration for accurate cost representation.
- b) Kapoor Imaging challenges the decision to assign separate dumping and injury margins to Lucky Huaguang Graphics Co. Ltd. and Kodak (China) Graphic Communications Co. Ltd., despite their affiliation. They argue that, in line with established practice, affiliated companies should have a collapsed margin (i.e., one combined margin for both companies). Kapoor believes the decision to provide different margins is inconsistent with prior cases and requests the margins be consolidated for fairness.
 - c) Kapoor Imaging submitted that demand for the product has remained stable, except for a temporary decline during the COVID-19 pandemic. They argue that imports from the subject countries have declined during the period of investigation (POI). Despite this, the domestic industry claims injury, which Kapoor disputes, insisting that imports are not responsible for the industry's poor performance.
 - d) Kapoor Imaging submitted that there is a continued decline in the domestic industry's profitability, including a reduction in metrics such as PBIT (Profit Before Interest and Taxes), cash profits, and Return on Capital Employed (ROCE). They argue that the anti-dumping duties should have provided protection, but since the domestic industry's financial performance has deteriorated, this implies that imports are not the cause of the injury. Kapoor suggests that the domestic industry's own poor business decisions, including its pricing strategy, are more likely to blame.
 - e) Chongqing Huafeng objects to the Authority's decision to apply the same dumping margin and injury margin to both cooperative exporters, such as Chongqing Huafeng, and non-cooperative producers. It refers to the Manual of Operating Practices for Trade Remedy Investigations, which suggests that cooperative exporters should receive a lower duty than non-cooperative entities to encourage cooperation. Therefore, the company requests a lower rate for Chongqing Huafeng.
 - f) Other interested parties challenge the 22% ROCE used by the Directorate General of Trade Remedies (DGTR) in calculating the Non-Injurious Price (NIP). They argue that this rate is outdated, having been established in 1987 when economic conditions (interest rates and corporate tax) were significantly different, leading to inflated prices and undue protection for the domestic industry. The interested parties have referred to the Bridgestone judgement and suggested using a lower, more realistic ROCE based on current economic conditions.

- g) Eastman Kodak submitted that the Authority has found a nil injury margin for another exporter, Anhui Strong State New Materials Co., meaning no anti-dumping duty will be applied. Eastman Kodak raises concerns over this determination, suspecting that TechNova might be importing products from Anhui Strong at temporarily inflated prices to evade duties.
- h) Eastman Kodak requests a re-evaluation of Anhui Strong's margin to prevent potential circumvention of anti-dumping measures.
- i) Interested parties have argued that it is unclear whether the applicant has appropriately segregated import data and injury.
- j) Interested parties have argued that this level of imports by TechNova is substantial. Further, parties have claimed that these imports as "occasional" is unjustified. The parties have argued that TechNova cannot be considered as eligible domestic industry under the rules.
- k) The likelihood of injury recurrence has not been properly analysed. They argue that the Authority has not analysed post-POI data.
- l) In the public interest assessment, interested parties have submitted that the Authority has downplayed concerns raised by the user industry, including the demand-supply gap, quality issues, and the negative impact on the user industry. The Authority seems more concerned about the potential impact on Hindalco, a major supplier of raw materials to TechNova (the domestic industry), than on the user industry itself.
- m) Kodak India requested that separate duties should be imposed for different types of digital plates (Thermal, Violet, and CtCP plates), as they have different price and market dynamics. Further, Kodak submitted that the Authority has determined a reference price form of duty for these categories, and Kodak requests the same methodology be applied in the current review.

M.3 Examination by the Authority

164. With regard to the contention of Jeil about incorrect calculation of dumping margin due to rejection of their inventory adjustment claim, the Authority notes that Jeil has claimed cost of production as *** KRW/SQM in appendix 8. The Authority has adopted the same with minor adjustments and the same was used to work out normal value for the company. Post issuance of disclosure statement the company has claimed that the corporate overheads as claimed in Appendix 7 and 8 pertains to subject goods purchased from China and sold in the domestic market. However, no supporting documentary evidences were provided by the company to substantiate their claim. In view of the above, the authority has determined cost

of production taking into account the claim of the company as per their original questionnaire response as well as documents submitted during the desk verification process and such cost of production has been considered for determining the normal value.

165. The interested parties have argued that the domestic industry has not made any investments as claimed in the original investigation. In response, the domestic industry clarified that it has made a cumulative investment of INR 400 crores for the production of the PUC, as acknowledged at Para 18(d) of the Final Findings dated May 15, 2020 issued in the original investigation. Based on the available records, the Authority notes that the domestic industry has invested INR *** Lakhs in plant and machinery, which is part of the capital work in progress pending installation. This investment indicates the domestic industry's intention to expand its capacities in the future.
166. The domestic industry has claimed that import volumes from Sri Lanka and Spain have been mis-declared and should be included in the subject country volume for a fair injury assessment. The Authority notes that the issue of mis-declaration is not within the scope of the current review investigation. Therefore, it is inappropriate to cumulate such imports with those from the subject countries. The domestic industry may file an anti-circumvention investigation against such imports.
167. With regard to the submissions made by interested parties on the combination of duties for Lucky and Kodak, the Authority notes the following:
- Based on the information available, the majority shares of Kodak China were acquired by Lucky after the POI of the original investigation.
 - Lucky and Kodak China continue to operate as separate legal entities. While Lucky has assumed control of Kodak China, both companies operate under separate management and possess separate manufacturing facilities.
168. The Authority notes that it had considered the issue of change in the ownership in the original investigation, wherein the Authority acknowledged that the Lucky acquired Kodak China after the POI. The Authority noted that “*export pricing behaviour of the merged entity may be evaluated under a review investigation as and when filed by any interested party, in accordance with the relevant Rules/procedure*”. In this regard, the Authority has compared the price behaviour of both entities in the period of investigation for this review to that in the original investigation. The Authority notes that the price behaviour for Lucky

and Kodak China remains the same as the original investigation, and therefore, the margins calculated for them in the original investigation do not require any variation at this juncture.

169. In view of the same, the Authority finds it appropriate to extend separate duties to Kodak China and Lucky as levied in the original investigation.

170. The Authority consistently applies a 22% Rate of Capital Employed (ROCE) as standard practice in all anti-dumping investigations. The observations of the Ld. CESTAT in the Bridgestone case were specific to the use of 22% ROCE in determining price underselling, not its appropriateness in computing the Non-Injurious Price (NIP). Moreover, the Bridgestone decision predates the introduction of Annexure-III to the AD Rules, rendering reliance on it by other interested parties is unjustified. In the subsequent Merino Panel Products case, the CESTAT upheld DGTR's practice of applying a 22% ROCE.

171. With regard to contention of the interested parties on negative injury margin and dumping margin determined for Anhui Strong, the Authority has revisited the calculations made and made corrections in the exchange rate considered. The revised dumping and injury margin is reflected in the tables above.

172. Several interested parties have argued on the injury to the domestic industry is not on account of imports but some other factors as the performance of the domestic industry have continued to decline despite imposition of anti-dumping duties. In this regard, the Authority notes that it has examined the parameters of injury as well as parameters of non-attribution in detail in the foregoing paragraphs. Therefore, the same are not being repeated herein for sake of brevity.

173. With regard to contention of the interested parties on the segregation of the data, the Authority notes that it has analysed and segregated the import data from the DG Systems and verified the injury data from the records of the domestic industry.

174. Various interested parties have argued that the imports into the country are on account of demand supply gap. In this regard, the Authority notes that it is a well-established principle that demand-supply gap cannot be a ground for non-imposition of duties, as also held by the Hon'ble Gujarat High Court in *NOCIL Limited v. Government of India*.

175. With regard to the contention of the parties on the imports made by the domestic industry and its standing, the Authority notes that it has examined in detail the imports made by the domestic industry as well as its standing under the AD Rules in the foregoing paragraphs of the present findings.
176. The Authority notes that post-POI information is not mandatorily prescribed under the AD Rules for assessing likelihood. The Authority has examined the parameters of likelihood based on the information provided by the interested parties during the investigation.
177. With regard to the submissions on the public interest, the Authority notes that it is required to assess the interest of public at large which includes the upstream industry, the domestic industry as well as the user industry. The claims of the interested parties that the Authority has only considered impact on the raw material supplier is factually incorrect. The Authority has examined the impact of duties on the interest of public at large including the user industry and quantified the impact of the duties. The authority has also taken cognizance of submissions made by certain users acknowledging that the continued presence of a viable domestic supplier would be in the public interest.
178. As regards the submission of the parties on the change in the form of duty, the Authority considers that form of measures is required to be seen on a case-to-case basis. Neither Section 9A (5) of the Act nor Rule 23 of the Rules prescribes or proscribes any particular form or modification of the form at the stage of review. Accordingly, the Authority finds it appropriate to continue with the same form of duties i.e., fixed form of duties.

N. CONCLUSIONS

179. After examining the submissions made by all the interested parties and issued raised therein and considering the facts available on record, the Authority concludes that:
- a) The application for initiation of sunset review to extend the period of imposition of the existing anti-dumping duties for a further period of five years was filed by TechNova Imaging Pvt. Ltd.
 - b) The applicant is an eligible domestic industry under the Rule 2(b) of the AD Rules and accounts for a major proportion of Indian production. Therefore, the applicant constitutes domestic industry for the purpose the present investigation.

- c) The product under consideration in the present investigation is Digital Offset Printing Plates.
- d) The scope of product under consideration includes three types of digital offset printing plates, namely,
- i. Thermal Plates;
 - ii. Violet Plates;
 - iii. CtCP/UV CtP Plates.
- e) Waterless CtP plates are excluded from the scope of the PUC.
- f) Since no producer from China PR has filed request for market economy treatment, China PR has been considered as a non-market economy and the normal value has been determined based on the price payable in India which is based on cost of production of the domestic industry.
- g) Considering the normal value and export price determined, the dumping margin for the subject goods from the subject countries is positive.
- h) The demand for the subject goods has increased in India compared to the previous year. The volume of imports in India have increased despite anti-dumping duty in force particularly compared to the previous years. Such imports are undercutting and having depressing effect on the prices of the domestic industry. The domestic industry has suffered any injury due to low priced imports.
- i) The price undercutting and suppression has resulted in negative profit, cash profits, and return on capital employed.
- j) There is a likelihood of continuation of dumping and consequent injury to the domestic industry in case of cessation of anti-dumping duty in force. This is evident from the following.
- The prices of the domestic industry found to be suppressed and depressed from subject imports.
 - The producers from subject countries have continued dumping of the PUC in India despite the anti-dumping duties in force.
 - Surplus disposable capacities in the subject countries as well as with the cooperating producers from the subject countries.
 - Chinese producers are facing trade remedial measures on imports of subject goods from Brazil, South Korea, Taiwan and USA. In event of cessation of duties, there is likelihood the exports to these countries being diverted to India.

- k) The imports have entered into India at price below the non-injurious price of the domestic industry. In case of cessation of anti-dumping duty, the import price is likely to be lower.
- l) The continuation of anti-dumping duties is in the public interest. This is evident from the following:
- The impact of duties on the cost of user industry is insignificant which is in the range of 0.5% to 1.5% depending on the user segment.
 - Since the domestic industry is the only large manufacturer of the subject goods, any impact on the domestic industry manufacturing operations would impact the upstream industry as well.
 - The anti-dumping duties does not prohibit imports into the country but ensures a level playing field between the dumped imports and domestic manufacturer. The viable domestic industry ensures that the user industry is not fully dependent on the imports.
 - Indian industry has made investment for increase in capacities in India pending for installation.

O. RECOMMENDATIONS

180. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all the interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, the exporters, the importers, the users and the other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and the causal link and also on likelihood of dumping and injury to the domestic industry.

181. Having concluded that there is positive evidence of likelihood of dumping and injury if the existing anti-dumping duties are allowed to cease, the Authority is of the view that the anti-dumping duty in force on the imports of the product under consideration from the subject countries is required to be continued further. Considering the facts and circumstances of the case, as established hereinabove, the Designated Authority considers it appropriate to recommend extension of the anti-dumping duties on the imports of the subject goods from the subject countries. Accordingly, the anti-dumping duties for producers from the subject countries are recommended as per the duty table below.

182. Thus, in terms of provision contained in Rule 4(d) and Rule 17(1) (b) of the AD Rules, the Authority recommends the continued imposition of the existing anti-dumping duties, so as to remove the likelihood of dumping and injury to the domestic industry. Further, the

Authority considers that individual rate of anti-dumping duty cannot be recommended for new producer/exporter who did not participate in the original investigation and have participated for the first time in the present sunset review investigation. Accordingly, definitive anti-dumping duty equal to the amount mentioned in column 7 of the duty table below is recommended for the imposition for five (5) years from the date of the Notification to be issued by the Central Government, on all imports of subject goods originating in or exported from the subject countries.

Duty Table

SL	Tariff Heading	Description of Goods **	Country of origin	Country of Export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	8442.50, 3701.300 0, 3704.009 0, 3705.100 0, 7606.119 0, 7606.919 0, 7606.929 0	Digital Offset Printing Plates	China PR	Any country including China PR	Lucky Huaguang Graphics Co. Ltd.	0.55	SQM	USD
2	-do-	Digital Offset Printing Plates	China PR	Any country including China PR	Kodak China Graphic Communications Co. Ltd.	NIL	SQM	USD
3	-do-	Digital Offset Printing Plates	China PR	Any country including China PR	Fujifilm Printing Plate (China) Co. Ltd.	NIL	SQM	USD
4	-do-	Digital Offset Printing Plates	China PR	Any country including China PR	Anhui Strong State New Materials Co., Ltd.	0.60	SQM	USD
5	-do-	Digital Offset Printing Plates	China PR	Any country including China PR	Any producer other than at Serial Number (1) to (4) above.	0.77	SQM	USD
6	-do-	Digital Offset Printing Plates	Any other country	China PR	Any producer	0.77	SQM	USD
7	-do-	Digital Offset Printing	Korea RP	Any country including	Jeil C&P Co. Ltd.	0.15	SQM	USD

		Plates		g Korea RP				
8	-do-	Digital Offset Printing Plates	Korea RP	Any country including Korea RP	Any producer other than at Serial Number (7)	0.37	SQM	USD
9	-do-	Digital Offset Printing Plates	Any other country	Korea RP	Any producer	0.37	SQM	USD
10	-do-	Digital Offset Printing Plates	Japan	Any country including Japan	Fujifilm Corporation	0.13	SQM	USD
11	-do-	Digital Offset Printing Plates	Japan	Any country including Japan	Any producer other than at Serial Number (10)	0.27	SQM	USD
12	-do-	Digital Offset Printing Plates	Any other country	Japan	Any producer	0.27	SQM	USD
13	-do-	Digital Offset Printing Plates	Taiwan	Any country including Taiwan	Any producer	0.41	SQM	USD
14	-do-	Digital Offset Printing Plates	Any other country	Taiwan	Any producer	0.41	SQM	USD
15	-do-	Digital Offset Printing Plates	Vietnam	Any country including Vietnam	Any producer	0.60	SQM	USD
16	-do-	Digital Offset Printing Plates	Any other country	Vietnam	Any producer	0.60	SQM	USD

***Excluding waterless CtP Plates used for printing on specialised materials such as credit card, security card etc., and not on paper.*

P. Further procedure

183. An appeal against the order of the Central Government that may arise out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions of the Act.

DARPAN JAIN, Designated Authority